



# कानून भारतीय रेलवे

सन् १८९०

एक्ट ९ सन् १८९०

विषय-सूची

पहिला परिच्छेद

प्रारम्भिक

धाराएँ

१. नाम, प्रचारस्थान और प्रचारारम्भ ।
२. मंजूरी ।
३. परिभाषाएँ ।

दूसरा परिच्छेद

रेलवे का निरीक्षण

४. इंस्पेक्टरों की नियुक्ति और कर्तव्य ।
५. इंस्पेक्टरों के अधिकार ।
६. सुगमताएं जो इंस्पेक्टरों को दी जायगी ।

तीसरा परिच्छेद

इमारतों का बनाना और स्थिर रखना

७. समस्त आवश्यकताएँ इमारतें बनाने के सम्बन्धमें रेलवे प्रबन्धकों का अधिकार ।

८. नलों, तारों और मोरियों का बदलना ।
९. नरन्मत करने या घटना रोकने के लिये भूमि पर बन्धार्थ प्रवेश ।
१०. धारा ७, ८ या ९ के अनुसार उचित अधिकारों के प्रयोग के कारण घटित हानि के लिये दरजा दिया जाना ।
११. सुखद तामीरें ।
१२. मालिक, कानिज या स्थानीय हाकिम को अधिकार है कि यह अतिरिक्त सुखद तामीरें बनवाये ।
१३. बाड़े, परदे, फाटक और कूटहरे ।
१४. पुलों के ऊपर और नीचे ।
१५. उन वृक्षों का हटाया जाना जिनसे रेलवे के चलाने में भय हो या पाधा हो ।

## चौथा परिच्छेद

### रेलवियों का खोलना

१६. धुएँ की कलों के प्रयोग करने का स्वत्व ।
१७. जिस रेलवे के खोलने का निचार हो उसकी सूचना ।
१८. रेलवे के खोलने से पहिले गवर्नमेन्ट की अनुमति शर्त है ।
१९. रेलवे खोलने की अनुमति देने की कार्य प्रणाली ।
२०. रेलवे के वास्तविक परिवर्तन से ऊपर की शान्तिग लीन धाराओं की आज्ञाओं का सम्बन्ध ।
२१. छूट की आज्ञा ।
२२. रेलवे खोले जाने के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार ।
२३. खुली हुई रेलवे के प्रन्द करने का अधिकार ।
२४. बन्द की हुई रेलवे का फिर खोलना ।
२५. इस परिच्छेद के अन्तर्गत अधिकारों का इन्स्पैक्टरों को दिया जाना ।

## पांचवां परिच्छेद

### रेलवे कमीशन और ट्राफिक ( आने जाने ) की सुगमताएं

२६. रेलवे कमीशन का संगठन ।

२३. रेलवे कमीशन को केवल उन्ही मुकद्दमों का विचार अधिकार प्राप्त होगा जो उसको विशेष रूप से सुपुर्द किये गये हों।

२४. रेलवे कमीशन को मुकद्दमों का सुपुर्द होना।

२५. रेलवे कमीशन का हजलास सेशन में संगठन।

२६. रेलवे कमीशन के अधिकार।

२७. रेलवे कमीशन की आक्षाओं के विरुद्ध अपीलें।

२८. रेलवे कमीशन की आक्षाओं का पालन।

२९. असेस्सर।

३०. लोकान्जिल गवर्नर जनरल का इस परिच्छेद के प्रयोजनों के लिये नियम बनाने का अधिकार।

३१. इस परिच्छेद के अनुसार कार्यवाहियों का नाम।

३२. रेलवे कमीशन और हाई कोर्ट की आक्षाओं का पालन।

३३. दस्तावेज का प्रमाण।

३४. रेलवे कमीशन द्वारा लोकान्जिल गवर्नर जनरल को विशेष रिपोर्टों का भेजा जाना।

३५. रेलवे कमीशन का हटना।

३६. इस परिच्छेद की पिछली आक्षाओं के आधीन रेलवे कमीशन की आक्षाओं की अपरिवर्तनीयता।

३७. कुछ ऐसे मामले जो रेलवे कमीशन द्वारा विचार-योग्य हों साधारण अदालतों के विचार-अधिकार से बाहर हों।

## ट्राफिक की सुगमताएं

४०. रेलवे प्रबन्धकों का कर्त्तव्य है कि वह बिना अनुचित विलम्ब और बिना सरफदारी के ट्राफिक को प्राप्त करके और भेजने का प्रबन्ध करें।

४१. समान ट्राफिक या सेवाओं के लिये विषम गहराइलों की व्यवस्था में अनुचित विशेषता।

४२. सुगमताओं और समान व्यवहार सम्बन्धी आक्षाएँ जय कि पैसे अदाज या वोट प्रयुक्त हों जो रेलवे का भाग नहीं हों।

४३. नासिरी मंजिल के विराये।

४४. नासिरी मंजिल के विराये के नियम बनाने का रेलवे कमीशन का अधिकार है।

# छटा परिच्छेद

## रेलवे चलाना

सामान्य

४७. सामान्य नियम ।

४८. संयुक्त ट्राफिक के संचालन के सम्बन्ध में रेलवियों के मत-भेद का निर्णय ।

४९. पड़िये दार चीजों के बनाने या उनका पट्टा लेने के सम्बन्ध में स्कौन्सिल गवर्नर जनरल से इकरार नामे ।

५०. रेल चलाने का इकरार नामा करने के सम्बन्ध में रेलवे कम्पनियों का अधिकार ।

५१. ट्राफिक के आराम के लिये घाटों और रास्तों का स्थापित किया जाना ।

५२. नकशे ।

## सम्पत्ति का लाना ले जाना

५३. मालगाड़ी के डिब्बे के लिये अधिक से अधिक बोझ ।

५४. रेलवे प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि वह ट्राफिक चलाने के लिये शर्तें लगाएं ।

५५. महसूलों, आखिरी मंजिल के किरायों और अन्य रकमों के लिये माल रोकना ।

५६. रेलवे में ऐसी चीजों के सम्बन्ध में कार्य चाही जिनका कोई दोष दार न हो ।

५७. कुछ अवस्थाओं में माल के देने पर जमानत मांगने का रेलवे प्रबन्धकों का अधिकार ।

५८. माल की तफसील का लेख बद्ध हिसाब मांगा जाना ।

५९. भयप्रद या हानि कर माल ।

६०. सर्व साधारण को वह अधिकार पत्र दिखाना जिस के द्वारा कि लिखे हुए किराये मांगे जाते हैं ।

६१. थोक किरायों की तफसील देना रेलवे प्रबन्धकों पर आवश्यक है ।

## यात्रियों का लाना लेजाना

६२. यात्रियों और रेलवे के उन नौकरों के दरम्यान जिन की रक्षा में रेल गाड़ी हो सूचना देने का प्रबन्ध ।
६३. प्रत्येक कम्पार्टमेंट के लिये यात्रियों की अधिक से अधिक संख्या ।
६४. स्त्रियों के लिये कम्पार्टमेंटों का सुरक्षित रहना ।
६५. समय-सूचक और किराया-सूचक पत्रों का स्टेशन पर प्रदर्शन ।
६६. किराया देने पर टिकटों का दिया जाना ।
६७. उल्लंघन के विषय में आज्ञा जब कि उन रेल गाड़ियों के लिये टिकट बट चुकी हों जिन में अधिक यात्रियों के लिये स्थान न हो ।
६८. पास या टिकट बिना यात्रा करने का निषेध ।
६९. पास और टिकटों का दिखाना और वे देना ।
७०. वापसी और मौसमी टिकट ।
७१. ऐसे मनुष्य को लाने या ले जाने से इंकार करने का अधिकार जो सांक्रामिक या छूत वाले रोग से ग्रसित हो ।

## सातवां परिच्छेद

### वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धकों का उत्तर दायित्व

७२. पशुओं और माल के वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धकों के सामान्य उत्तर दायित्व का परिमाण ।
७३. पशुओं के वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धकों की ज़ुम्मेदारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त आज्ञा ।
७४. यात्रियों का असवाब ले जाने वाले की दैसियत से रेलवे प्रबन्धकों की ज़ुम्मेदारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त आज्ञा ।
७५. विशेष मृत्यु की वस्तुओं के वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धकों की ज़ुम्मेदारी के सम्बन्ध में अतिरिक्त आज्ञा ।
७६. उन गाड़ियों में प्रमाण भार-जो पशुओं या माल की जानि के सम्बन्ध में हों ।

७७. अधिक किरायों की वापिसी और हानि के दरजे के सम्बन्ध में दावों की विधि।
७८. उस हालत में जुम्मेदारी से बचाव जब कि माल का विवरण झूठा दिया गया हो।
७९. उन हानियों के सम्बन्ध में दरजे का चुकाना जो उन अफसरों लिपिद्वियों और भीष्ट को पहुँची हों जो काम पर हों।
८०. उस हानि के दरजे की नालिशें जो थू मुक़ड ट्राफिक को पहुँची हो।
८१. ( संसूख )
८२. समुद्र की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक की जुम्मेदारी की मीमांसा।

## आठवां परिच्छेद

### दुर्घटनाएं

८३. रेलवे की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट।
८४. दुर्घटनाओं की सूचना और तद्वर्तीकाल के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार।
८५. दुर्घटनाओं का नक़्शा भेजना।
८६. रेलवे दुर्घटनाओं में हानि प्राप्त मनुष्य की अनुवार्य हाथदरी परीक्षा के विषय में आज्ञा।

## नवां परिच्छेद

### दण्ड और अपराध

### रेलवे कंपनियों का दण्ड

८७. धारा १३ की आज्ञा उलंगन के कारण दण्ड।
८८. धारा १६, १८, १९, २०, २१ या २४ की प्रति कूलता के कारण दण्ड।
८९. ४७, ५४ या ६५ के अनुसार स्टेशनों पर कुल लेख पत्र न रखने या प्रदर्शन न करने के कारण दण्ड।
९०. धारा ४७ द्वारा आवश्यक नियमों के न बनाने के कारण दण्ड

९२. धारा ५२ या ८५ के अनुसार नकशों के भेजने में बिलम्ब करने के कारण दण्ड ।

९३. पहिचे वाली चीजों की बाहन-शक्ति सम्बन्धी धारा ५३ या ६३ की आज्ञाओं में असाधधानता होने के कारण दण्ड ।

९४. यात्रियों और रेलवे के नौकरों के बीच में खूबक सामिग्री स्थिर रखने के लिये धारा ६२ की आज्ञा पालन न करने के कारण दण्ड ।

९५. धारा ६४ के अनुसार खियों के लिये रक्षित कम्पार्टमेन्ट न रखने के कारण दण्ड ।

९६. धारा ८३ और धारा ८४ द्वारा आवश्यक दुर्घटनाओं की सूचना न देने के कारण दण्ड ।

९७. दण्ड-धन का वसूल किया जाना ।

९८. इस परिच्छेदकी पूर्वोक्त आज्ञाओं के चाराकार, पदले की या प्रसिद्ध स्थिति में ।

### रेलवे के नौकरों द्वारा अपराध

९९. धारा ६० द्वारा लगाये कर्तव्य ( ड्यूटी ) का पालन न करना ।

१००. नशा में होना ।

१०१. मनुष्यों की सलामती संशय में डाल देना ।

१०२. यात्रियों को उन दरजों में प्रवेश करने के लिये विवश करना जो पहिले ही से भरे हों ।

१०३. दुर्घटना की सूचना न देना ।

१०४. लेविल कालिङ्ग रोकना ।

१०५. झूठे नकशे ।

### अन्य अपराध

१०६. माल का झूठा हिसाब देना ।

१०७. रेलवे पर अनुचित रूप से भयानक या हानि कर माल लाना

१०८. ट्रेन गाड़ी में खूबक-सामिग्री में अनापश्यकतः हस्तक्षेप करना

१०९. रिजर्वड या पहिले से भरे कंपार्टमेन्ट में प्रवेश करना या न भरे हुए कंपार्टमेन्ट में प्रवेश करने से रोकना ।

११०. दम्भाकू पीना ।

१११. सार्वजनिक मूलना पत्रों का बिगाड़ना ।



११२. उचित पास या टिकट बिना, चलत यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना ।

११३. बिना पास या टिकट के, या अपर्याप्त पास या टिकट से या उस दूरी से अधिक यात्रा करना जहां तक यात्रा करने का अधिकार हो ।

११४. बापिसी टिकट का कोई अद्दा बदलना ।

११५. पूर्वोक्त अन्तिम दो धाराओं के जुग्माने के सम्बन्ध में कार्य-वाही ।

११६. पास या टिकट का बदलना या गिगाटना ।

११७. रेलवे में छूत या सांक्रामिक रोग सद्वृत्ति यात्रा करना या ऐसे मनुष्य को यात्रा करने देना ।

११८. चलती हुई गाड़ी में बैठना, या और तरह अनुचित रूप से रेल में यात्रा करना ।

११९. उस गाड़ी या अन्य स्थान पर प्रवेश करना जो स्त्रियों के लिये रिजर्व हो ।

१२०. रेलवे में, नशे में होना या कष्ट कर कार्य करना ।

१२१. रेलवे के नौकर को उस के सरकारी काम से रोकना ।

१२२. अनुचित प्रवेश और अनुचित प्रवेश से बाज़ आने से इंकार

१२३. ओमनीबस ड्राइवर्स का रेलवे के नौकरों की हिदायतों के सम्बन्ध में आज्ञा-उलंघन करना ।

१२४. फाटक खोलना या उचित रूप से बन्द न करना ।

१२५. पशुओं का अनुचित प्रवेश ।

१२६. हानि पहुंचाने की नीयत से ट्रेन गाड़ी बरबाद करना या बरबाद करने का प्रयत्न करना ।

१२७. हानि पहुंचाने की नीयत से उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना या पहुंचाने का प्रयत्न करना जो रेलवे से यात्रा कर रहे हों ।

१२८. इच्छा युक्त कार्य या कार्य-त्याग द्वारा उन मनुष्यों की सलामती संशय में डालना जो रेलवे में यात्रा कर रहे हों ।

१२९. जल्दी या असाबधानता के कार्य, या कार्य त्याग द्वारा उन मनुष्यों की सलामती संशय में डालना जो रेलवे में यात्रा कर रहे हों ।

१३०. विशेष आज्ञा यच्चों के उन कार्यों के सम्बन्ध में जिन से रेलवे में यात्रा करने वालों की सलामती में संशय पड़े ।

## कार्य प्रणाली

१३१. कुल धाराओं की प्रतिकूलता के अपराध में गिरफ्तारी।
१३२. ऐसे मनुष्यों की गिरफ्तारी जिन के भागने की सम्भावना हो या जिन का पता न मालूम हो।
१३३. मजिस्ट्रेट जिन को इस एक्ट के अनुसार विचार अधिकार प्राप्त हो।
१३४. विचार—स्थान।

## दसवाँ परिच्छेद

### पूरक आज्ञाएँ

१३५. स्थानीय अधिकारियों की ओर से रेलवेयों पर टैक्स।
  १३६. रेलवे की सम्पत्ति के प्रतिकूल इजराय डिग्री सम्बन्धी शर्तें।
  १३७. भारतीय दण्डसंग्रह के अध्याय ९ के अभिप्रायों के लिये रेलवे के नौकर सरकारी नौकर समझे जायंगे।
  १३८. रेलवे प्रबन्धकों को उस सम्पत्ति के सरसरी रूप से देने का कार्य कम जिते रेलवे के नौकर ने रोक लिया हो।
  १३९. सपरिषद् गवर्नर जनरल से प्राप्त पत्र व्यवहार को प्रकट करने की विधि।
  १४०. रेलवे प्रबन्धकों पर नोटिस की तामील।
  १४१. रेलवे प्रबन्धकों द्वारा नोटिसों की तामील।
  १४२. अनुमान जब कि नोटिस की तामील डांक द्वारा की जाय।
  १४३. नियमों के सम्बन्ध में आज्ञाएँ।
  १४४. सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिकारों का दिया जाना।
  १४५. रेलवे के मैनेजर्स और एजेंटों का अदालत में प्रति निधित्व।
  १४६. दुखानी ट्रामवेज के सम्बन्ध में एक्ट की प्रसार—वृद्धि करने का अधिकार।
  १४७. इस एक्ट से रेलवेज को पृथक् रखने का अधिकार।
  १४८. गाँवों जो रेलवे और रेलवे के नौकर की परिभाषा की पूरक हैं।
  १४९. भारतीय दण्ड संग्रह का संशोधन।
  १५०. विन्ध पेशीन रेलवे एक्ट १८८७ का संशोधन।
- पहिला शीटपूल—बानून जो मंजूर हुए  
दूसरा शीटपूल—जीने जो प्रकट और तीमा की जायगी।

॥ ओ३म ॥

# कानून भारतीय रेलवे

अर्थात्

(१)

एक्ट ९ सन् १८९०

(२१ मार्च सन् १८९०)

भारत में रेलवेयोंके सम्बन्धी कानून को संग्रह, संशोधन करने और बढ़ाने के लिये एक्ट

(१ जून सन् १९०९ तक संशोधित)

चूंकि यह उचित प्रतीत होता है कि भारत में रेलवेयों के सम्बन्धी कानून का संग्रह, संशोधन किया जाय तथा बढ़ाया जाय, अतएव इस के अनुसार निम्न लिखित आशाएं प्रचारित होती हैं:-

## पहिला परिच्छेद

प्रारम्भिक

धारा १-(१) यह एक्ट कानून भारतीय रेलवे सन् १८९० के नाम से पुकारा जा सकता है।

(१) उद्देश्य और कारणों के वर्णन के लिये देखिये, भारतीय गजट सन् १८८८, भाग ५, पृष्ठ १३३, सेलेक्ट कमेंटी की रिपोर्ट के लिये देखिये भारतीय गजट सन् १८९०, भाग ५, पृष्ठ २३, और कौन्सिल के विवादों के लिये, देखिये भारतीय गजट १८८८, भाग ६, पृष्ठ १२४ और १३७, और सन् १८९०, भाग ६, पृष्ठ १५ और ४८।

शैड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट सन १८७४ ( १४ सन १८७४ ) जनरल एक्ट्स, जिल्द दो. की धारा ३ ( क ) की विज्ञप्ति द्वारा, एक्ट ९ सन १८९०, निम्न सूची वर्णित जिलों में प्रचलित प्रकट किया गया है:—

तराई के परगने, आगरा प्रान्त, देखिये भारतीय गजट सन १८९० भाग १ पृष्ठ ५९६, जिला हजारी बाग, लोहार डांगा ( जिस में इस समय पलामऊ का जिला सम्मिलित है जो सन १८९४ में पृथक् कर दिया गया था ) और मान भूम, और परगना ढाल भूम, और कोलन जिला सिंग भूम में, देखिये वही पृष्ठ ८५९ ।

लोहार डांगा जिला अब जिला रांची कहलाता है, देखिये फलशुक्ता गजट १८९९ भाग १ पृष्ठ ४४ ।

संघाल परगनों के पंदोयस्त के रेगुलेशन १८७२ ( ३ सन १८७२ ) धारा ३ के अनुसार जैसी कि संघाल परगनाज जरिदत और ला रेगुलेशन १८९९ ( ३ सन १८९९ ) द्वारा संशोधित हुई है, इस का सम्बन्ध संघाल परगनों से किया गया है । देखिये पिछले रेगुलेशन की सूची का दूसरा भाग जैसा १ मार्च सन १९०९ तक संशोधित हुआ है ।

बरमा लाज एक्ट सन १८९८ ( १३ सन १८९८ ) बरमा कोड, के अनुसार यह कानून अपर बरमा ( शान स्टेट को छोड़ कर ) में प्रचलित प्रकट किया गया है ।

सिन्ध पेशीन रेलवे एक्ट १८८७ ( २ सन १८८७ ) की धारा ३, उपधाराएं ( २ ) और ( ३ ) के अनुसार इस एक्ट का सम्बन्ध कुछ संशोधनों के अधीन, नार्थ वेस्टर्न रेलवे के सिन्ध पेशीन स्थित उस भाग से किया गया है, जो सिन्ध प्रान्त के बाहर स्थित है । देखिये एपेन्डिक्स, बाल कोड, पृष्ठ १५६ ।

रेलवे बोर्ड एक्ट १९०५ ( ४ सन १९०५ ) इस एक्ट के साथ पढ़ा जायगा और इस का भाग समझा जायगा देखिये वही एक्ट, जनरल एक्ट्स जिल्द ६, धारा १ ( २ ) ।

( २ ) इसका सम्बन्ध समस्त ब्रिटिश भारत से है जिस में प्रचार स्थान | (जहां तक सिन्धु पेशावर रेलवे एक्ट १८८७ के आज्ञाओं के अनुसार इसका सम्बन्ध किया गया है या सम्बन्ध हो सकता है) ब्रिटिश थिलोचिस्तान, सम्मिलित है, और इस का सम्बन्ध साम्राज्ञी की उस समस्त प्रजा से भी है जो उन भारतीय राजाओं के देशों और देसी रियासतों में रहती है जो साम्राज्ञी की मित्रता-सूत्र से बद्ध हैं, और इसका सम्बन्ध साम्राज्ञी की उस समस्त देसी प्रजा से भी होगा जो ब्रिटिश भारत और उन देशों और रियासतों के बाहर रहती है; और

(३) इसका प्रचार १ मई सन १८९० को होगा।

( २ )

धारा २—( १ ) उस तारीख को और उस तारीख से, मंसूखी | कानून जिनका निरूपण पहिली सूची में हुआ है उस सीमा तक मंसूख हुए हैं जिसका वर्णन कि उसके तीसरे कालम में है।

(२) परन्तु उन कानूनों में से किसी के अनुसार या उस कानून के अनुसार जो उनमें से किसी के द्वारा मंसूख हुआ हो, तमाम नियम जो रचे गये हों, इकरार और नियुक्तियां जो की गई हों, मंजूरियां और हिदायतें जो दी गई हों, नमूने जो स्वीकार किये गये हों, अधिकार जो प्रदान किये गये हों, और विश्वासियां जो प्रकाशित की गई हों, जहां तक कि वे इस एक्ट के अनुकूल हैं यह समझा जायगा कि वे इस कानून के अनुसार क्रमशः रचे गये, किये गये की गई, दी गई, स्वीकृत किये गये, प्रदान किये गये और प्रकाशित की गई।

( १ ) शब्द “ अपरवरमा ” वरमा लाज एक्ट १८९८ ( १३ सन १८९८ ) के अनुसार मंसूख हुए।

(२) इस धाराका उत्तमा भाग जितनेका सम्बन्ध कि अपर वरमा लाज एक्ट १८९६ (२० सन १८९६) के भाग की मंसूखी से है, वरमा लाज एक्ट १८९८ ( १३ सन १८९८ ) के अनुसार मंसूख हुआ।

( ३ ) किसी ऐसे एनाक्टमेन्ट या लेख पत्र से जिसमें उन कानूनों या किसी ऐसे कानून का हवाला हो जो उनमें से किसी के द्वारा संसूख हुआ हो, सम्भवतः यह समझा जायगा कि उसमें इस एक्ट या उसके सम्बन्धी भागिका हवाला है ।

**धारा ३**—इस एक्ट में, जब तक कि उसके विषय या अभि-  
प्रायः प्राय में कुछ वैपरीत्य न हो,

( १ ) “ट्रामवे” का अभिप्राय उस ट्रामवे से है जो भारतीय ट्रामवेज के कानून सन १८८६ या ट्रामवेज संबंधी विशेष कानून अनुसार बनाई गई हो ।

( २ ) “पुल” में नावों का पुल, “पानट्रुस” अर्थात् बंधे हुए तख्तों का पुल, “राफ्ट” अर्थात् बेटा, “स्वूइंग ब्रिज” अर्थात् झूलता हुआ पुल, “फ्लाईंग ब्रिज” अर्थात् जल्दी पार करने वाला पुल, और अस्थायी पुल, और पुल में पहुंचने के मार्ग और उस से उतरने के स्थान सम्मिलित हैं ।

( ३ ) “देश गत जल” का अभिप्राय ब्रिटिश भास्त की किसी नहर, नदी, झील या जहाज़ चलाने योग्य जल से है ।

( ४ ) “रेलवे” से हर ऐसी रेलवे या रेलवे का भाग अभिप्रेत है, जो यात्रियों, पशुओं या माल के सामान्यतः ले जाने या लाने के लिये प्रयुक्त हो, और उसमें निम्नलिखित चीजें भी सम्मिलित हैं ।

( क ) समस्त भूमि जो ऐसे अद्वारों या अन्य सीमा-चिह्न के भीतर हो जो रेलवे सम्बन्धी भूमि की सीमाएं प्रकट करते हों ।

( ख ) रेल की तमाम लाइनें, पगली रास्ते या शाखाएं, जो किसी रेलवे के अभिप्राय के लिये या उस के संबन्ध में काम में लाई जायं ।

( ग ) तमाम स्टेशन, दफ्तर, गोदाम, घाट, काम करने के स्थान कारखाने, स्थित पौदे और फल और अन्य मकानात, जो रेलवे के प्रयोजन के लिये या उसके संबन्ध में बनाये जायं,

( घ ) तमाम पुल, जहाज़, नाव और बेटे जो रेलवे के ट्राफिक के अभिप्रायके लिये देश गत जलों पर प्रयुक्त होते और जो रेलवेप्रवन्दल अधिकारीकी संपत्ति हों या उसने किराये किये हों या उसके काम में हों ।

( ५ ) “रेलवे-कम्पनी” में ऐसे मनुष्य सम्मिलित हैं जो, समिति में हों अथवा न हों, किसी रेलवे के अध्यक्ष या पट्टेदार हों या रेलवे चलाने के इकरार नामे के फरक हों ।

( ६ ) “रेलवे प्रबन्धक” या “प्रबन्धक” से जब कि रेलवे का प्रबन्ध गवर्नमेन्ट या देसी रियासत की ओर से हों, रेलवे के गैनेजर से अभिप्राय है और उस में गवर्नमेन्ट या देसी रियासत भी सम्मिलित हैं, और, जब कि रेलवे का प्रबन्ध रेलवे कंपनी की ओर से हो, तो उसका अभिप्राय रेलवे कंपनी से है ।

( ७ ) “रेलवे का नौकर” का अर्थ हर ऐसे मनुष्य से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक ने रेलवे की सेवाएं सम्बन्ध में नौकर रखा हो,

( ८ ) “इन्सपेक्टर” का अभिप्राय हर ऐसे रेलवे के इन्सपेक्टर से है जो इस एक्ट के अनुसार नियुक्त हुआ हो ।

( ९ ) “माल” में हर प्रकार की वस्तुएं चीजें सम्मिलित हैं ।

( १० ) “पहिये वाली चीज़” में धुंए के एंजिन, कोयले की गाड़ियां गाड़ियां, माल की गाड़ियां और हर प्रकार की खुली गाड़ियां और ठेले गाड़ियां सम्मिलित हैं ।

( ११ ) “ट्राफिक” में हर प्रकार की पहिये वाली चीज, यात्री पशु और माल सम्मिलित है ।

( १२ ) “थिक ट्राफिक” का अभिप्राय ऐसे ट्राफिक से है जो दो या अधिक रेलवे प्रबन्धकों की रेलवे पर ले जाया जाय ।

( १३ ) “महसूल” में किसी यात्री पशु या माल के लाने, ले जाने का किराया, चार्ज या अन्य दैन सम्मिलित है ।

( १४ ) “आखरी मंजिल का महसूल” में स्टेशनों, बगली रास्तों घाटों, डिपो, गोदामों, और माल उठाने की कलों और घैसीही अन्य चीजों के सम्बन्ध का तथा उन स्थानों में होने वाले कामों का चार्ज सम्मिलित है ।

( १५ ) “पास” का अभिप्राय उस अधिकार पत्र से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक की ओर से, या उस अफसर की ओर से दिया गया हो जिसको किसी रेलवे प्रबन्धक ने नियत किया हो, और जिससे उस मनुष्य को जिसको कि वह दिया गया हो यह अधिकार प्राप्त होता हो कि वह रेलवे में यात्री रूप से बिना किराये दिये यात्रा कर सके ।

( १५ )

( १६ ) "टिकट" में एक ओर का टिकट, वापिसी टिकट और मौसमी टिकट सम्मिलित हैं ।

( १७ ) "मन" से अमिप्राय बत्तीस सौ तोले वजन से है और हर तोले में एक सौ अस्सी ग्रेन द्रव्य वजन होगा । और

( १८ ) "कलक्टर" का अमिप्राय उस मुख्यअधिकारी से है जिसकी सुपुर्दगी में जिले की मालगुजारी का प्रबन्ध हो, और उसमें ऐसा मनुष्य सम्मिलित है जो स्थानीय गवर्नमेन्ट द्वारा इस एक्ट के अनुसार कलक्टर के कर्तव्यों के सन्पन्न करने के निमित्त विशेषतः नियुक्त किया गया हो ।

## दूसरा परिच्छेद

### रेलवियों का निरीक्षण

धारा ४—( १ ) लोकान्जिल गवर्नमेन्ट जनरल को अधिकार हरपेक्टरों की नियुक्ति | देगा कि वह लोगों को उनके नाम से या और उन के कर्त्तव्य | उनके पद की हैसियत से रेलवियों के हरपेक्टर नियत करे ।

( २ ) रेलवे-इन्स्पेक्टर के कर्त्तव्य निम्न लिखित होंगे:—

- ( क ) यह निश्चय करने के विचार से रेलवियों का निरीक्षण करना कि आया वट सामान्यतः रानियों के लाने या ले जाने के लिये ठीक है अथवा नहीं, और उस पर इस एक्ट की माहानुसार लोकान्जिल गवर्न जनरल को रिपोर्ट करना ।
- ( ख ) किसी रेलवे या किसी एडिये वालीबीज का जो उसमें प्रयुक्त हो, ऐसा सामयिक या अन्य निरीक्षण करना जैसी कि लोकान्जिल गवर्नर जनरल माहा दें ।
- ( ग ) किसी रेलवे सम्बन्धी दुर्घटना के कारण इस एक्ट के अनुसार अन्वेषण करना ।
- ( घ ) अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस एक्ट या रेलवे सम्बन्धी इस समय प्रचलित किसी अन्य एक्ट द्वारा उस पर लगाये गये हों ।



( ५ ) “रेलवे-कम्पनी” में ऐसे मनुष्य सम्मिलित हैं जो, समिति में हों अथवा न हों, किसी रेलवे के अध्यक्ष या पट्टेदार हों या रेलवे चलाने के इकठ्ठार नामे के फरीक हों ।

( ६ ) “रेलवे प्रबन्धक” या “प्रबन्धक” से जब कि रेलवे का प्रबन्ध गवर्नमेन्ट या देसी रियासत की ओर से हों, रेलवे के गैनेजर से अभिप्राय है और उस में गवर्नमेन्ट या देसी रियासत भी सम्मिलित है, और, जब कि रेलवे का प्रबन्ध रेलवे कम्पनी की ओर से हो, तो उसका अभिप्राय रेलवे कम्पनी से है ।

( ७ ) “रेलवे का नौकर” का अर्थ हर ऐसे मनुष्य से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक ने रेलवे की सेवा के सम्बन्ध में नौकर रखा हो,

( ८ ) “इन्सपैक्टर” का अभिप्राय हर ऐसे रेलवे के इन्सपैक्टर से है जो इस एक्ट के अनुसार नियुक्त हुआ हो ।

( ९ ) “माल” में हर प्रकार की वस्तु सम्मिलित है ।

( १० ) “पहिये वाली चीज़” में धुंफ के एंजिन, कोयले की गाड़ियां गाड़ियां, माल की गाड़ियां और हर प्रकार की खुली गाड़ियां और ठेले गाड़ियां सम्मिलित हैं ।

( ११ ) “ट्राफिक” में हर प्रकार की पहिये वाली चीज़, यात्री पशु और माल सम्मिलित है ।

( १२ ) “थिक् ट्राफिक” का अभिप्राय ऐसे ट्राफिक से है जो दो या अधिक रेलवे प्रबन्धकों की रेलवे पर ले जाया जाय ।

( १३ ) “महसूल” में किसी यात्री पशु या माल के लाने, ले जाने का किराया, चार्ज या अन्य दैन सम्मिलित है ।

( १४ ) “आखरी मंजिल का महसूल” में स्टेशनों, दगली रास्तों घाटों, डिपो, गोदामों, और माल उठाने की कलों और वैसे ही अन्य चीजों के सम्बन्ध का तथा उन स्थानों में होने वाले कामों का चार्ज सम्मिलित है ।

( १५ ) “पास” का अभिप्राय उस अधिकार पत्र से है जो किसी रेलवे प्रबन्धक की ओर से, या उस अफसर की ओर से दिया गया हो जिसको किसी रेलवे प्रबन्धक ने नियत किया हो, और जिससे उस मनुष्य को जिसको कि वह दिया गया हो यह अधिकार प्राप्त होता हो कि वह रेलवे में यात्री रूप से बिना किराये दिये यात्रा कर सकें ।

( १६ ) "टिकट" में एक ओर का टिकट, वापिसी टिकट और मौसमी टिकट सम्मिलित है ।

( १७ ) "मन" से अभिप्राय बत्तीस सौ तोले वजन से है और हर तोले में एक सौ अस्सी ग्रेन द्रव्य वजन होगा । और

( १८ ) "कलक्टर" का अभिप्राय उस मुख्य अधिकारी से है जिसकी सुपुर्दगी में जिले की मालगुजारी का प्रबन्ध हो, और उसमें ऐसा मनुष्य सम्मिलित है जो स्थानीय गवर्नमेन्ट द्वारा इस एक्ट के अनुसार कलक्टर के कर्तव्यों के सन्पन्न करने के निमित्त विशेषतः नियुक्त किया गया हो ।

## दूसरा परिच्छेद

### रेलवियों का निरीक्षण

धारा ४—( १ ) लोकान्जिल गवर्नमेन्ट जनरल को अधिकार इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति | होगा कि वह लोगों को उनके नाम से या और उन के कर्त्तव्य | उनके पद की हैसियत से रेलवियों के इन्स्पेक्टर नियत करे ।

( २ ) रेलवे-इन्स्पेक्टर के कर्त्तव्य निम्न लिखित होंगे:—

- ( क ) यह निश्चय करने के विचार से रेलवियों का निरीक्षण करना कि आया वह सामान्यतः यात्रियों के लाने या ले जाने के लिये ठीक है अथवा नहीं, और उस पर इस एक्ट की धारा अनुसार लोकान्जिल गवर्न जनरल को रिपोर्ट करना ।
- ( ख ) किसी रेलवे या किसी एडिये वाली चीज का जो उसमें प्रयुक्त हो, ऐसा सामयिक या अन्य निरीक्षण करना जैसी कि लोकान्जिल गवर्नर जनरल आज्ञा दें ।
- ( ग ) किसी रेलवे सम्बन्धी दुर्घटना के कारण इस एक्ट के अनुसार अन्वेषण करना ।
- ( घ ) अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस एक्ट या रेलवे सम्बंधी उक्त समय प्रचलित किसी अन्य एक्ट द्वारा उस पर लगाये गये हों ।

**धारा ५**—हर एक इन्स्पेक्टर, उन कर्त्तव्यों में से किसी कर्त्त-  
इन्स्पेक्टर के अधिकार | व्य के प्रयोजन के लिये, जिन के संपन्न  
 करने की उसे आज्ञा दी गई हो, या जिन के सम्पन्न करने का  
 अधिकार हो, भारतीय दंड संग्रह के अर्थों में सरकारी नौकर  
 समझा जायगा और उस अभिप्राय के लिये सक्रॉन्सिल गवर्नर  
 जनरल की निगरानी के अधीन, निम्न लिखित अधिकार प्राप्त  
 होंगे, अर्थात्:—

- ( क ) किसी रेलवे या किसी पहिचाने वाली चीज़ का जो उस में  
 प्रयुक्त हो, प्रविष्ट हो निरीक्षण करना,
- ( ख ) अपने दस्तखती लेख बद्ध आज्ञा द्वारा जो रेलवे-प्रबन्धक के  
 नाम हो, किसी रेलवे के नौकर को अपने सामने उपस्थित  
 होने की आज्ञा देना, और रेलवे के उक्त नौकर या रेलवे  
 प्रबन्धक से ऐसे अन्वेषणों के सम्बन्ध में उत्तर या कैफियत  
 मांगना जो वह उचित समझे;
- ( ग ) किसी ऐली किभाव या लेख पत्र के पेश करने की आज्ञा  
 देना जो किसी रेलवे प्रबन्धक की सम्पत्ति हो या उस के  
 कब्जे या निगरानी में हो ( सिवाय उस पत्र व्यवहार के जो  
 किसी रेलवे कम्पनी और उस के कानूनी सलाहकार के  
 बीच में हो ) जिस का निरीक्षण करना उसे आवश्यक  
 प्रतीत हो ।

**धारा ६**—उन कर्त्तव्यों के पालन के लिये जो इस एक्ट द्वारा  
इन्स्पेक्टरों को दी जाते | उस पर लगाये जाय और उन अधिकारों  
वाली सुगमताएं | के प्रयोग करने के लिये जो इस एक्ट  
 द्वारा उस को प्रदान हों, रेलवे-प्रबन्धक इन्स्पेक्टर को समस्त  
 उचित सुगमताएं प्रदान करेगा ।



## तीसरा परिच्छेद

### इमारतों का बनाना और स्थित रखना

धारा ७—( १ ) इस एक्ट की आक्षाओं के आधीन और उस तमाम इमारतें बनाने के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धकों का अधिकार ।

अचल सम्पत्ति की अवस्था में जो रेलवे प्रबन्धक की न हो, सार्वजनिक प्रयोजनों और कम्पनियों के निमित्त भूमि प्राप्ति सम्बन्धी, उस समय पर प्रचलित, कानून की आक्षाओं के आधीन, और रेलवे कम्पनी की अवस्था में, उस संविद ( मुआहिदा ) की शर्तों के भी आधीन, जो उक्त कम्पनी और गवर्नमेन्ट के दरम्यान हो, किसी रेलवे प्रबन्धक का अधिकार है कि वह किसी रेलवे या उस के आराम के सामान या उन के सम्बन्ध में अन्य इमारतें बनाने के अभिप्राय के लिये और उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून में चाहे जो कुछ क्यों न हो,—

[ क ] किसी भूमि, या किसी गली, पहाड़ी, घाटी, रास्ते, रेलवे, दानवे, या किसी नदी, नहर, नाले, चश्मे, या अन्य पानियों, या अन्य मोरियों, पानी के नलों, गैस के नलों या तार की लाइनों में या उन पर या उन के आर पार या उन के नीचे या ऊपर, अस्थाई या स्थाई ढलवां सितह, महारायें, सुरंगें, पुल के नीचे के रास्ते, पुश्ते, पानी के रास्ते, पुल, सड़कें ( रेलवे की लाइनें ) \* रास्ते मार्ग, नहरें, मोरियां, खम्भे, कटे हुए रास्ते, और हाने बनावे जैसा कि रेलवे प्रबन्धक उचित समझे;

( ग ) नदियों, नालों, चश्मों या नालियों के मार्ग को, सुरङ्गों, पुलों रास्तों, या अन्य इमारतों के, उन के ऊपर या नीचे, बनाने के अभिप्राय के लिये, बदल दे, और अस्थाई या स्थाई रूप से, नदियों, नालों, चश्मों या नालियों, या सड़कों रास्तों या गलियों को भी फेर दे या बदल दे या उन की लिनह को उठाये या नीचा करे, ताकि रेलवे के ऊपर,

\* यह शब्द कानून रेलवे ( १८९० ) के संशोधक कानून सन १८९६ ( ९ सन ९६ ) की धारा १ के अनुसार बढ़ाये गये ।

या नीचे या बगल से उन का लाना अधिक सरल हो, अर्थात् जैसा कि रेलवे प्रबन्धक उचित समझे।

( ग ) रेलवे से या रेलवे तक पानी लाने के प्रयोजन के लिये रेलवे से मिली हुई किसी भूमि में या भूमि में होकर या भूमि के नीचे मोरियां या नहरें बनावे।

( घ ) ऐसे मकानात, गोदाम, दफ्तर और अन्य भवन बनाने और ऐसे आंगन, स्टेशन, घाट, अग्निजल, मशीन, सामान यंत्र और अन्य चीजें और आराम के सामान बनावे जैसा कि रेलवे प्रबन्धक उचित समझे;

( ङ ) उन भवनों, इमारतों और आराम के सामानों को जिन का ऊपर वर्णन हुआ, या उन में से किसी को बदले, मरम्मत करे या बन्द करे और उन के स्थान में दूसरी चीजें बनावे और

( च ) रेलवे के बनाने, स्थिर रखने, बदलने मरम्मत करने और प्रयोग करने के लिये अन्य समस्त आवश्यक कार्य करे।

( २ ) उन अधिकारों का प्रयोग, जो रेलवे प्रबन्धक पर उप धारा ( १ ) द्वारा हुआ है, सकॉन्सिल गवर्नर जनरल की निगरानी के अधीन होगा।

धारा ८—रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उन भिन्न-भिन्न तारों और मोरियों को बदलना | कारों को प्रयोग में लाने के प्रयोजन के लिये, जो इस एक्ट द्वारा उस को प्रदान किये गये हैं; किसी नल के स्थान को, गैस, पानी या मिश्रित हवा के संग्रह के लिये, या किसी धिजली के तार के स्थान को या ऐसी मोरी के स्थान को जो असल मोरी न हो बदल दे:

परन्तु शर्त यह है:—

( क ) जब रेलवे प्रबन्धक किसी ऐसे नल, तार या मोरी का स्थान बदलना चाहेगा तो उस के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने ऐसा करने के इरादे तथा उस समय से जब कि वह ऐसा करना प्रारम्भ करेगा उस स्थानीय अधिकारी या कंपनी को सूचना दे, जिस की निगरानी में नल, तार या मोरी हो, या जब कि नल, तार या मोरी स्थानीय अधिकारी या कंपनी की निगरानी में न हो, तो उसमनुष्य को सूचना दे जिस की निगरानी में कि नल, तार या मोरी हो,

( ख ) जिस रुधानोय अधिकारी, कम्पनी या मनुष्य को शर्त ( क ) के अनुसार नोटिस प्राप्त हो उसे अधिकार है कि वह उक्त कार्य की देख रेख के लिये किसी मनुष्य को भेज दे और रेलवे प्रबन्धक उक्त कार्य को इस प्रकार करेगा- जिस से इस प्रकार भेजे हुए मनुष्य को राहतोष हो जाय, और काम के जारी रहने की अपस्था में गैस, हवा, मिश्रित हवा, या बिजली के संग्रह करने या मोरी के स्थिर रखने का, जैसी दशा हो प्रबन्ध करेगा ।

धारा ६—( १ ) स्कौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है दुर्घटना की मरम्मत या रोकथाम के लिये भूमि पर अस्थाई प्रवेश कि वह किसी रेलवे प्रबन्धक को यह अधिकार प्रदान करे कि वह अपनी निगरानी में किसी कटे हुए रास्ते, पुश्ते या अन्य इमारत के टूटने या अन्य दुर्घटना होने या ऐसा होने की शंका होने की दशा में उक्त दुर्घटना की मरम्मत या रोकथाम के लिये, अपनी रेलवे के निरुद्ध की भूमि पर प्रवेश करे और ऐसे राय कार्य करे जो उस अभिप्राय के लिये आवश्यक हों ।

( २ ) आवश्यकता की दशा में, रेलवे प्रबन्धक उक्त भूमि पर प्रवेश कर पूर्णतः कार्यवाही करे, स्कौन्सिल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कर सकता है, परन्तु ऐसी दशा में, यह आवश्यक होगा कि उक्त प्रवेश के पश्चात् वह उत्तर वंशों के भीतर स्कौन्सिल गवर्नर जनरल को ऐसी रिपोर्ट जिस में दुर्घटना या शङ्कित दुर्घटनाका और उनकार्योंका प्रकार वर्णन करे जिनका करना कि आवश्यक हो और इस उपधारा द्वारा रेलवे प्रबन्धक पर प्रदत्त अधिकार नष्ट और समाप्त हो जायगा, यदि स्कौन्सिल गवर्नर जनरल रिपोर्ट पर विचार करने पश्चात् यह समझे कि उक्त अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक शान्ति के लिये आवश्यक नहीं है ।

धारा १८—( १ ) पूर्वोक्त सन्तिम तीन धाराओं में से किसी धारा ७, ८ या ९ के अनुसार अधिकारों के उचित प्रयोग के कारण हो होने वाली हानि का एवम देना । धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, रेलवे प्रबन्धक जहां तक सम्भव होकर कमहानि पहुंचावेगा और उन अधिकारों के प्रयोग से पड़ित हानि का एवम देना ।

[ २ ] उक्त हरजे के रुपये के हिस्सा पाने की नालिश न होगी परन्तु झगड़े की दशा में, कलकटर को प्रार्थना पत्र देने पर, हरजे की रकम सम्भवतः\* (धाराएं ११ से १५ (दोनों सम्मिलित) धाराएं १८ से ३४ तक, [दोनों सम्मिलित] धाराएं ५३ और ५४ कानून भूमि गति सन १८९४ की आज्ञाओं के अनुसार निश्चित और अदा की जायगी, और उक्त कानून की धाराएं ५१ और ५२ की आज्ञाएं हरजा दिलाने से सम्बन्ध रखेंगी । )

**धारा ११—**— ( १ ) रेलवे प्रबन्धक को आवश्यक होना नि आराम की चीजें | रेलवे की आसन्न भूमिके अध्यक्षों और अधिकारियों के आराम के लिये निम्न चीजों को बनावे और स्थिर रखे, अर्थातः—

( क ) रेलवे के ऊपर, नीचे या बगल में, या रेलवे से लेजाने वाले या रेलवे तक पहुँचाने वाले ऐसे और उतने सुभीते के चौराहे, पुल, महराबे, पुल के भीतर के मार्ग और रस्ते, जो सक्की निल गवर्नर जनरल की सम्मति में उन हस्तक्षेपों की पूर्ति के लिये आवश्यक हों जो उस भूमिके प्रयोग में जिसमें, होकर कि रेलवे बनाई जाय, रेलवे के कारण पड़ें, और

( ख ) रेलवे के ऊपर, नीचे या बगल से, ऐसी लम्बाई चौड़ाई के तमाम आवश्यकीय पुल, सुरंगें, पुल के नीचे के मार्ग, नाळे, जल मार्ग, या अन्य रास्ते, जो सक्की निल गवर्नर जनरल की सम्मति में, रेलवे से निकट की या रेलवे से प्रभावित, भूमि से या भूमि तक, हर समय रवतन्त्रता से पानी लाने के लिये पर्याप्त हो जैसी कि रेलवे बनाने से पूर्व हो या जहां तक हो सके उसके करीब २ हो ।

( २ ) इस एक्ट की अन्य आज्ञाओं के आधीन, उप धारा ( १ ) के खण्ड ( क ) और ( ख ) में निरूपित इमारतें, उस भूमि पर जिस पर होकर कि रेलवे जाय, रेलवे के डालने या तैयार करने के बीच में

\* यह शब्द और संख्याएं, असली शब्द और संख्याओं के अन्वय में रेलवे एक्ट सन १८९० के संशोधक एक्ट सन १८९६ ( ९ सन १८९६ ) की धारा २ के अनुसार दसे गये ।

या पश्चात् ही तुरन्त बनाई जायगी और इस विधि से बनाई जायगी कि उन मनुष्यों को जो भूमि में अधिकार रखते हों या जो हमारतों से प्रभावित होते हों सम्भवतः कम से कम हानि या कष्ट पहुँचे।

( ३ ) इस धारा की पूर्वोक्त लाक्षाएं निम्न लिखित शर्तों के अधीन हैं, अर्थात्:—

( क ) किसी रेलवे प्रबन्धक पर आवश्यक न होना कि वह इस तरीके से आराम की हमारतें बनाये जिसमें रेलवे के बनाने या प्रयोग करने में रुकावट या अड़खन डाले, या ऐसी आराम की हमारतें बनावे जिसके सम्बन्ध में भूमि के अध्यक्ष और अधिकारी, उनके हमारत बनाने के लिये विवश न होने के बदले में क्षति धन लेने पर राजी हों और वन्धों में उक्त क्षति—धन प्राप्त कर लिया हो;

( ख ) सिवाय इसके कि इस परिच्छेद में तत्पश्चात् आज्ञा हो, लोकनियुक्त गवर्नर जनरल की आज्ञा को छोड़ कर, कोई रेलवे प्रबन्धक उस तारीख से दस वर्ष व्यतीत हो जाने पर तब कि रेलवे भूमि पर होकर सर्व साधारण के लाने ले जाने के लिये खुले, उक्त भूमि के अध्यक्षों या अधिकारियों के प्रयोग के लिये किसी विशेष या अतिरिक्त आराम की हमारत बनाने का प्रयत्न करने के लिये विवश न किया जायगा,

( ग ) जहां कि रेलवे प्रबन्धकने सड़क या चशमेकेपार करनेका उचित सामान बना दिया हो, और तत्पश्चात् उक्त सड़क या चशमेका रख, उस मनुष्य के किसी कार्य या असावधानता के कारण फिर गया हो जिसकी निगरानी में कि उक्त सड़क या चशमा हो, तो रेलवे प्रबन्धक उक्त सड़क या चशमों को पार करने के निमित्त अन्य आराम का सामान बनाने के लिये विवश न किया जायगा।

( ४ ) लोकनियुक्त गवर्नर जनरल को अधिकार है कि उप धारा [ १ ] के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के लिये समय नियत करदे, और यदि उक्त समय के पश्चात् चौदह दिन तक रेलवे प्रबन्धक कार्य प्रारम्भ न करे या, प्रारम्भ करके पर्याप्त रीति से उसको सवत सम्पन्न न करे, तो लोकनियुक्त गवर्नर जनरल को अधिकार होना



कि वह उसको सम्पन्न करायें और उसकी तैयारी में जो व्यय हो उसको रेलवे प्रबन्धक से दसूल करें।

**धारा १२**—यदि किसी ऐसी भूमि का अध्यक्ष या अधिकारी अध्यक्ष, अधिकारी या स्थानीय हाकिम को अधिकार है कि वह अतिरिक्त आराम की इमारतें बनवा सकता है।

जो रेलवे से प्रभावित हो पिछली अन्तिम धारा के अनुसार बनी हुई इमारतों को भूमि के सुव्यवस्था के लिये अपर्याप्त समझे,

या यदि स्थानीय गवर्नमेन्ट या स्थानीय हाकिम रेलवे के ऊपर नीचे या ऊपर कोई सरकारी सड़क या अन्य तामीर बनाना चाहे, तो उस मनुष्य या गवर्नमेन्ट हाकिम को, जैसी दशा हो, अधिकार होगा कि वह किसी समय रेलवे प्रबन्धक की आज्ञा दे सकते हैं कि उस मनुष्य, गवर्नमेन्ट या हाकिम के व्यय से वह आराम का विशेष सामान तैयार करायें जिसे वह मनुष्य, गवर्नमेन्ट या हाकिम आवश्यकीय समझे और जिस के बनाने पर रेलवे प्रबन्धक सम्मत रहा हो, या मत भेद होने की अवस्था में जिस के सम्बन्ध में कि सको-निल गवर्नर जनरल अनुमति दे।

**धारा १३**—सकोनिल गवर्नर जनरल को यह आज्ञा देने का अधिकार होगा कि आज्ञा में निरूपित क्षीरकटहरे। समय के भीतर या उस समय विशेष के भीतर जो वह इस सम्बन्ध में नियत करें,—

(क) कि किसी रेलवे या उस के भाग के लिये, और उन सड़कों के लिये जो उस के सम्बन्ध में बनाई जाय, रेलवे प्रबन्धक की ओर से सीमा—चिन्ह या बाड़े बनाये जाय या उन का पुनर्निर्माण कराया जाय।

(ख) परदे की प्रकाश के कोई काम जो किसी ऐसी सरकारी सड़क के किनारे के पास या किनारे से मिला कर जो रेलवे बनने से पहिले बनी हो, रेलवे प्रबन्धक की ओर से सड़क के यात्रियों को ऐसे भय से बचाने के लिये, तैयार करायें जाय या उन का पुनर्निर्माण कराया जाय, जो रेलवे पर चलती हुई पहिले वाली चीज़ के देखने या शोर से घोड़ों या अन्य पशुओं के भड़कने के कारण उत्पन्न हो।

- ( ग ) कि रेलवे प्रबन्धक की ओर से उन स्थानों पर जहां पर कि रेलवे किसी सरकारी सड़क की धरातल के पार हो कर निकले, उचित फाटका, जंजीरे, फटहरे, सीढियां या इध-रेल बनाये जाय या उन का पुनर्निर्माण कराया जाय।
- ( घ ) कि रेलवे-प्रबन्धक की ओर से उक्त फांटकों, जंजीरों और फटहरों के खोलने और बन्द करने के लिये मनुष्य नियत किये जाय।

धारा १४—[ १ ] जहां कि रेलवे प्रबन्धक ने किसी सरकारी पुलों के ऊपर और नीचे | सड़क की धरातल के आर पार रेलवे बनाई हो, सड़क-निष्ठल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि यदि उन्हें सार्वजनिक सहायता के लिये आवश्यक प्रतीत हो, रेलवे प्रबन्धक को यह आज्ञा दे सकते हैं कि इनके समय के भीतर जितना कि यह उचित समझें, उस सड़क को रेलवे की आर पार न लेजा कर किसी पुल या मद्रास के द्वारा किसी रेलवे के नीचे या ऊपर निकालें जिस में आसान उढ़ाव और उतार और अन्य आगम के रास्ते हों, या ऐसी तामीरात बनाने की आज्ञा दे सकते हैं जो उक्त अवस्था में सड़क-निष्ठल गवर्नर जनरल को लेविल क्रासिंग से उत्पन्न भय के दूर या कम करने के लिये सर्वोत्तम प्रतीत हों।

[ २ ] सड़क-निष्ठल गवर्नर जनरल उप धारा [ १ ] के अनुसार आज्ञा देने के लिये पार्स रूप से यह आज्ञा दे सकते हैं कि वह स्थानीय अधिकारी, यदि कोई हो, जो सड़क को परफरार रखे, रेलवे प्रबन्धक को धागा पाटन समझी कुछ खर्च या उस के ऐसे अंश के भरा करने का जुम्मेदार होगा जो सड़क-निष्ठल गवर्नर जनरल उचित समझें।

धारा १५—[ १ ] निम्न लिखित किसी अवस्था में, अर्थात्:-

उन दृश्यों का घटाया जाना दिन से रेलवे के पटाने में भय हो या बाधा हो।

[ क ] जहां कि यह भय हो कि रेलवे के निकट खड़ा हुआ वृक्ष रेलवे पर इस तरह गिर सकता कि ट्राफिक रुक हो जाय,

[ख] जब कि कोई वृक्ष किसी नियत सिगनल के देखने में बाधक हो,

तो रेलवे प्रबन्धक का अधिकार है कि वह किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति से वृक्ष को गिरवा दे या कोई ऐसी कार्यवाही करे जिस से रेलवे प्रबन्धक की सम्मति में एक अथवा बाधा, जैसी कि दशा हो, दूर हो जाय।

[२] अत्यन्तावश्यकता की दशा में, उप धारा [१] में वर्णित अधिकार रेलवे प्रबन्धक द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना प्रयुक्त किया जा सकता है।

[३] जब कि वह वृक्ष जो उप धारा [१] या [२] के अनुसार गिराया गया हो या उस के संबंध में अन्य कार्यवाही की गई हो, रेलवे के बनने या सिगनल लगने से पड़ने में बाधा हो, तो प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह उन लोगों के आवेदन पत्र पर जो उस वृक्ष में स्वत्वाधिकारी हों, उन को ऐसा बदल धन दिलावे जो वह उचित समझे।

[४] उक्त बदल—धन के दिलाये जाने की आज्ञा, जब कि वह प्रेजीडेन्सी नगर में चीफ प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट को छोड़ कर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई हो, या अन्य स्थान पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ कर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई हो, चीफ प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, की निगरानी के अधीन, जैसी कि दशा हो, अपरिचर्त्तनीय होगी।

[५] किसी ऐसे वृक्ष के बदल—धन पाने की नालिश अदालत की दायी में दाखल न हो सकेगी जो इस धारा के अनुसार गिराया गया हो या उस के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही की गई हो।

## चौथा परिच्छेद रेलवियों का खोलना

धारा १६—[१] प्रत्येक रेलवे—प्रबन्धक को सकार्डिनल धुप की कलों के प्रयोग करने का स्वत्व।

गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से वह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी रेलवे पर, धुप से चलने वाले एंजिन या और चालक शक्ति प्रयोग करने और उस के द्वारा पड़ने वाली चीजों को निकालने।

[ २ ] परन्तु कोई पहिये वाली चीज़ किसी रेलवे पर धुएँ या अन्य कालक शक्ति द्वारा न चलाई जायगी तावके कि रेलवे के वह सामान्य नियम जो आवश्यकीय समझे जाय इस पृष्ठ के अनुसार बन न गये हों, और स्वीकृत और प्रकाशित न हो गये हों ।

धारा १७—[ १ ] उपधारा [ २ ] की आज्ञाओं के आधीन जिस रेलवे के खोलने का विचार यात्रियों के साधारणतः लाने या ले जाने के लिये किसी रेलवे के

खोलने का विचार करनेसे कम से कम एक मास पूर्व, रेलवे प्रबन्धक अपने विचार की लेख-पद्धति सूचना सिकौन्सिल गवर्नर जनरल को देगा ।

[ २ ] सिकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह किसी दशा में, यदि वह उचित समझे, उपधारा [ १ ] में वर्णित सूचना को भीयाद घटादे या उक्त सूचना के दिये जाने की आवश्यकता न समझे ।

धारा १८—यात्रियों के सामान्यतः लाने या लेजाने के लिये, रेलवे के खोलनेसे पहिले गवर्नमेन्ट कोई रेलवे उस समय तक न की अनुमति शर्त है । खोली जायगी जब तक कि सिकौ-

न्सिल गवर्नर जनरल ने या उस इन्स्पेक्टर ने, जिस को सिकौन्सिल गवर्नर जनरल ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो, उक्त अभिप्राय के लिये उक्त के खोले जाने की स्वीकृति की आज्ञा न दे दी हो ।

धारा १९—(१) पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार सिकौन्सिल रेलवे खोलने को अनुमति देने की गवर्नर जनरल की स्वीकृति कार्य-प्रणाली । उस समय तक न दी जायगी

यद्य तक कि इन्स्पेक्टर, रेलवे के निरीक्षण पश्चात्, सिकौन्सिल गवर्नर जनरल को निम्न बातों की लेख पद्धति सूचना न दे दे:—

[ क ] यह कि उस ने रेलवे और पहियेदार चीज़ों का विचार पूर्वक निरीक्षण किया है ।

[ ख ] यह कि वह और स्थिर चीज़ों को उस लम्बाई चौड़ाई में जो सिकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा नियत की गई हों, प्रतिकूलता नहीं की गई है ।

[ ग ] यह कि रेलों का गज़न, पुलों का ताकत, कामों की सामान्य निर्माण अवस्था और किसी पहिये वाली चीज़ की धुरी की लम्बाई चौड़ाई और उस धुरी पर अधिक से अधिक कुल बोझ वही है जो लोकनियुक्त गवर्नर जनरल ने निर्धारित किये हैं।

[ घ ] यह कि उक्त रेलवे के लिये पहिये दार चीज़ें पर्याप्ततः मौजूद हैं।

( ७ ) यह कि रेलवे के खोलने के सम्बन्ध के सामान्य नियम, जब कि वह यात्रियों के सामान्यतः लाने लेजाने के लिये खोली जाय, इस ऐक्ट के अनुसार बन गये, स्वीकृत तथा प्रकाशित हो गये हैं। और

[ झ ] यह कि उसकी सम्मति में यात्रियों के सामान्यतः लाने लेजाने के लिये रेलवे खोली जा सकती है और उस के प्रयोग से सर्व साधारण को भय नहीं है।

( २ ) यदि उक्त इन्स्पेक्टर की सम्मति में रेलवे इस कारण से नहीं खोली जा सकती कि उस के प्रयोग से सर्व साधारण को शंका होगी, तो वह उस सम्मति को कारणों सहित, बयान करेगा और तब लोकनियुक्त गवर्नर जनरल रेलवे प्रबन्धक को आज्ञा दे सकते हैं कि वह उक्त रेलवे का खोलना स्थगित रखे।

[ ३ ] प्रपोंक्त अन्तिम उपधारा के अनुसार आज्ञा में उन बातों का वर्णन होना चाहिये जिनका पालन होना रेलवे का खुलना मंजूर होने से पहिले शर्त की भांति आवश्यक है, और उरा में यह आदेश रहेगा कि रेलवे का खुलना उस समय तक स्थगित रहे जब तक कि उक्त बातों का पालन न हो जाये या लोकनियुक्त गवर्नर को अन्य प्रकार से यह समतोष न हो जाय कि उक्त रेलवे खोली जा सकती है और उस के प्रयोग से सर्व साधारण को कोई शंका नहीं है।

[ ४ ] मंजूरी जो इस धारा के अनुसार दी जाय, या तो स्वाधीन या उन शर्तों के आधीन हो सकती है जो लोकनियुक्त गवर्नर जनरल सर्व साधारण की रक्षा के लिये आवश्यकीय विचार करे।

( ५ ) जब किसी रेलवे के खोले जाने की मंजूरी शर्तों को आधीन दी जाय और रेलवे प्रबन्धक उन शर्तों के पूरा करने में अकृतकार्य रहे, तो उक्त मंजूरी अप्रभावक समझी जायगी और रेलवे उस समय

तक न चलाई जा प्रयुक्त की जायगी जब तक कि सकीन्सिल गवर्नर जनरल के सन्तोषानुसार शर्तें पूरी न हो जाय।

धारा २०—[१] रेलवे के खोले जाने के सम्बन्ध की धारा १७, १८ रेलवे के वास्तविक परिवर्तन से तथा १९ की आज्ञाएं, उपधारा २, में वर्णित मामलों से सम्बन्ध रखेंगी जबकि उक्त काम उक्त रेलवे का भाग हों या इससे सीधा सम्बन्ध रखते हों, जो यात्रियों के साधारणतः लाने ले जाने के लिये प्रयोग की जाय, और जो रेलवे के पट्टे हो पहले खुलने से पूर्व के निरीक्षण पश्चात् बनाये गये हों,

[२] काम जिसका निरूपण उपधारा [१] में हुआ है रेलवे की अनिश्चित लाइनों, तिनर बिनर लाइनों, स्टेशन, जंक्शन और खितह के टीराहे, और उक्त परिवर्तन या पुनर्निर्माण से अभिप्राय रखते हैं जिससे किसी ऐसे काम की रनाइट की अवस्था पर वास्तविक प्रभाव पड़ना हो जिससे धार १७ १८ तथा १९ की आज्ञा सम्बन्ध रखती हों या इस धारा द्वारा सम्बन्धित की गई हों।

धारा २१—जब कि कोई ऐसी दुर्घटना घट गई हो जिससे छूट की आज्ञा। कारण ट्राफिक अस्थाई रूप से रुक गया हो, और पाए गइली लाइन और काम उन गइली स्थिति पर शीघ्रता से का दिये गये हों, या आसन्न रूप से स्थिर रखने के लिये एक अस्थाई पृथक् लाइन डाल दी गई हो, तो यह अस्थायी लाइन और काम जो उक्त प्रकार तैयार दिये गए या अस्थाई लाइन, जैसी दशा हो इन्स्पेक्टर की अनुमति हैं, निम्न बातों में आधीन, यात्रियों के सामान्यतः लाने ले जाने के लिये खोली जा सकती है, अर्थात्:—

[क] यह कि रेलवे के उन तौर पर ने जिसके सुपूर्द यह काम हों जो दुर्घटना के कारण बनाये जाते हों यह तत्सदीक लेख पत्र पर दी हो कि अस्थायी लाइन में लाई हुई लाइन और कामों के खोले जाने का अस्थाई लाइन के खोले जाने से उसकी सम्मति में काम लाइन और काम या अस्थाई लाइन के प्रयोग करने वाली जनता के कोई डर नहीं है, और

[ख] यह कि लाइन और काम अस्थाई लाइन के खोले जाने की गार हाराखूना जहां तक सम्भव हो सीधे ही उस दर पर उतर दी गयी जायगी जो रेलवे के लिये नियत हो।

**धारा २२—**सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है रेलियों के खोलने के सम्बन्ध कि वह ऐसे नियम बनावे जिनमें मैं नियम बनाने का अधिकार । उन अवस्थाओं का निरूपण हो जिनमें और उन्हीं अवस्थाओं में सीमा का निरूपण हो जिस सीमा तक कि धारा १७ से २० तक [ दोनों सम्मिलित ] में निर्धारित कार्यवाही तयामी जा सके ।

**धारा २३—[ १ ]** जब किसी ऐसी खुली हुई रेलवे के निरी-  
खुली हुई रेलवे के बन्द | क्षण पश्चात् जो यात्रियों के सामान्यतः  
करने का अधिकार | लाने ले जाने में प्रयुक्त होती हो, या ऐसी  
 पहिये वाली चीज के निरीक्षण पश्चात् जो उक्त रेलवे पर प्रयोग  
 की जाती हो, यदि इन्स्पेक्टर की यह सम्मति हो कि उक्त रेलवे या  
 किसी विशेष पहिये वाली चीज के प्रयोग से उस को प्रयोग करने  
 वाली जनता को डर रहेगा तो वह उस सम्मति को उसके कारणों  
 सहित सकौन्सिल गवर्नर जनरल को लिख भेजेगा और तब सकौ-  
 न्सिल गवर्नर जनरल को यह आज्ञा देने का अधिकार है कि उक्त  
 रेलवे को यात्रियों के सामान्यतः लाने ले जाने के लिये बन्द कर दें,  
 या उक्त विशेष पहिये वाली चीज का प्रयोग बन्द कर दिया जाय या  
 उक्त रेलवे या उक्त विशेष पहिये वाली चीज ऐसी शर्तों पर यात्रियों  
 के सामान्यतः लाने ले जाने के लिये प्रयुक्त की जाय जो सकौन्सिल  
 गवर्नर जनरल जनता की रक्षा के लिये आवश्यकीय समझें ।

[२] उपधारा [१] के अनुसार आज्ञा में उन कारणों का वर्णन  
 होगा जिनके आधार पर वह आज्ञा दी गई हो ।

**धारा २४—[१]** जब कोई रेलवे पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार  
बन्द की हुई रेलवे का | बन्द हो गई हो, तो 'यह यात्रियों के सामा-  
फिर खोलना | न्यतः लाने ले जाने के लिये उस समय तक  
 फिर नहीं खोले जा सकती जब तक कि इस एक्ट की आज्ञाओं के  
 अनुसार इसका निरीक्षण न हो और उस का पुनः खोला जाना  
 मंजूर न हो गया हो ।

[२] जब कि पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार सकौन्सिल  
 गवर्नर जनरल ने यह आज्ञा दे दी हो कि अमुक पहिये वाली चीज  
 का प्रयोग बन्द कर दिया जाय, तो उक्त पहिये वाली चीज वरा

समय तक काम में न लाई जायगी जब कि इन्स्पेक्टर ने उसके प्रयोग के योग्य होने की रिपोर्ट न की हो और सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने उसका प्रयोग मंजूर न कर दिया हो ।

[ ३ ] जब कि पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने किली रेलवे या पट्टिये वाली छीज़ के सम्बन्ध में कोई शर्त लगा दी हो तो उन शर्तों का उस समय तक दृष्टि में रखना आवश्यक होगा जब तक कि वह सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा दृष्टा न ली जाय ।

धारा २५—[ १ ] सकौन्सिल गवर्नर जनरल सामान्य या इस परिच्छेद के अधिकारों विशेष आज्ञा द्वारा यह अधिकार दे का इन्स्पेक्टरों को किया जाना सकते हैं कि इस परिच्छेद के अनुसार

उन का कोई कर्त्तव्य किली इन्स्पेक्टर द्वारा सम्पन्न किया जाय, और ऐसे इन्स्पेक्टर द्वारा दी हुई मंजूरी या आज्ञा को रद्द कर सकते हैं जो उक्त कर्त्तव्य को सम्पन्न करता हो या उस में किली ऐसी शर्त की वृद्धि कर सकते हैं जिसे सकौन्सिल गवर्नर जनरल लगा सकते यदि वह मंजूरी या आज्ञा स्वयं उन्हीं के द्वारा दी गई होती ।

[ २ ] उप धारा [ १ ] के अनुसार लगाई हुई शर्त इस पक्ष के सम्मत प्रयोजनों के लिये बढ़ी प्रभाव रखेगी मानो वह सकौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा दी हुई मंजूरी या आज्ञा में बढ़ा दी गई हो ।

## पांचवां परिच्छेद

### रेलवे कमीशन और ट्राफिक की सुगमताएँ

धारा २६—[ १ ] इस परिच्छेद के प्रयोजनों के लिये सकौन्सिल गवर्नर जनरल जय कि रेलवे कमीशन का संगठन उन की सत्पत्ति में अक्सर की आवश्यकता हो, कमीशन नियत करेंगे जिसका नाम रेलवे कमीशन होगा [ और जो इस पक्ष में कमिशनर्स के नाम से वर्णन किये गये हैं ] और जिस में एक कानूनी कमिशनर और दो गैर कानूनी कमिशनर होंगे ।



हो तो, हाईकोर्ट आफ़ जुडीकेचर, फोर्ट विलियम बंगाल में दाइर होगी, और

[ ७ ] दूसरी अवस्था में, उस हाईकोर्ट में दाइर होगी जिस का कि कानूनी कमिश्नर मेम्बर हो ।

[ ३ ] उक्त अपील उस आज़ा की तारीख़ से छै माल के भीतर दाइर की जायगी जिस का कि वह अपील हो, और उस को सुनवाई उतने जजों की बेच द्वारा होगी जितने कि हाईकोर्ट नियम द्वारा निर्धारित करें, परन्तु वह तीन से कम न होंगे ।

[ ४ ] अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट को, इस परिच्छेद की अन्य आज़ाओं के आधीन, वह समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो उस को अदालत अपील की हैलियत से जावता दीवानी के अनुसार प्राप्त हों, और उस को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी आज़ा दे जो कमिश्नर दे सकते ।

धारा ३२—कमिश्नरों की आज़ा के विरुद्ध चाहे हाईकोर्ट में रेलवे कमीशन की आज़ाओं | अपील ही क्यों न हुआ हो, उक्त का पालन। आज़ा, जब तक कि कमिश्नर्स या उन में से अधिक कमिश्नर्स उस का स्थगित करना उचित न समझें, उस समय तक बराबर कार्य—परिणिग होता रहेगा जब तक कि वह उक्त हाईकोर्ट द्वारा रद्द न हो जाय या बदल न दी जाय ।

धारा ३३—[१] इस परिच्छेद के अनुसार विचार-अधिकार असेसर | के प्रयोग करने में कमिश्नरों को अधिकार होगा कि वह समय २ पर, स्कौन्सिल गवर्नर जनरल की सामान्य या विशेष स्वीकृति प्राप्त कर के, एक या अधिक ऐसे मनुष्यों को असेसरों की भांति काम करने के लिये नियत करें जो इन्जीनियरी या अन्य विशेष विद्या में पारदर्शता रखते हों ।

[ २ ] उक्त मनुष्यों को ऐसा सेवा-धन दिया जायगा जो स्कौन्सिल गवर्नर जनरल, कमिश्नरों की सिफ़ारिश पर, आज़ा करें ।

धारा ३४—स्कौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार होगा

इस परिच्छेद के अभिप्राय के | कि वह उस कार्य प्रणाली के लिये स्कौन्सिल गवर्नर जनरल सम्बन्धमें जो कमिश्नरों के सामने का नियम बनाने का अधिकार । हो, और इस परिच्छेद की

आज़ाओं को प्रभावित करने के लिये कमिश्नरों को अधिकार सम्पन्न

करने के सम्बन्ध में, और उन फीसों के सम्बन्ध में नियम बनाने जो कमिश्नरों के समक्ष कार्यवाहियों के सम्बन्ध में ली जाय।

**धारा ३५—**क्रिसोपेसी कार्यवाहीका असली और आकस्मिक

इस परिच्छेदकी कार्य वाहियो का व्यय।

व्यय जो इसपरिच्छेद के अनुसार कमिश्नरों या हाईकोर्ट के सामने

हो, कमिश्नरों या हाईकोर्ट की, जैसी दशा हो, मरजी पर होगा, और कमिश्नरों द्वारा दिलाया हुआ व्यय उस अदालत द्वारा जिस का कि कानूनी कमिश्नर जज हो इस प्रश्न अदा किया जा सकेगा जैसा कि हाईकोर्ट की डिगरी द्वारा आज्ञा होने की दशा में अदा किया जा सकता।

**धारा ३६—**[१]उस अदालत को, जिसके कि कानूनी कमिश्नर

रेलवे कमिश्नर और हाईकोर्ट की आज्ञा का पालन।

जज हो, यदि उस मनुष्यके प्रार्थना पत्र पर, जो कमिश्नरों के सामने

दोने वाली कार्यवाही का या हाईकोर्ट की अपील का एक फ़रीफ़ हो या उक्त मनुष्य का प्रतिनिध हो, यह बात मालूम हो कि उस ताकीदी आज्ञाका, जो इस परिच्छेदके अनुसार कमिश्नरों या हाईकोर्ट ने प्रदान की थी, उस मनुष्य द्वारा पालन नहीं किया गया जिस पर कि आज्ञा हुई थी, तो उक्त अदालत को यह अधिकार होगा कि उस फ़रीफ़ को यह आज्ञा करे कि वह एक ऐसी रकम प्रतिदिन जो एक हजार रुपये से अधिक न हो उक्त आज्ञा देने की तारीख के पश्चात जब तक ताकीदी आज्ञा का उलंघन किया जाय, अदा करे।

[ २ ] उक्त रकम उस अदालत द्वारा बसूल कराई जा सकती है जिस ने कि उक्त आज्ञा दी हो मानो कि उक्त अदालत ने वह डिगरी दी हो, और उक्त अदालत यह आज्ञा दे सकती है कि उक्त कुछ रकम या उसका कोई अंश, उस मनुष्य को जिसने उपधारा [ १ ] के अनुसार प्रार्थना पत्र दिया हो या गवर्नमेन्ट को अदा की जायगी।

**धारा ३७—**जिस दस्तावेज से यह प्रकट होता हो कि उस पर

दस्तावेजों का प्रमाण। कमिश्नरों या उनमें से किसी के हस्ताक्षर हैं यह दस्ताक्षर के प्रमाण बिना ही गवाही में ले लिया जायगा, चाहे जब तक कि प्रतिकूल प्रमाणित न किया जाय, यह समझा

जायगा कि उक्त दस्तावेज पर उक्त प्रकार हस्ताक्षर हुए और वह कमिशनरों द्वारा विधिवत सम्पन्न या जारी किया गया ।

धारा ३८—कमिशनरों को आवश्यक होगा कि वह, सम्भव-  
रेलवे कमीशन द्वारा सकौन्सिल तयः शीघ्र, प्रत्येक ऐसे मुकद्दमे  
गवर्नर जनरल को विशेष रिपोर्टों के समाप्त करने पश्चात्, जो  
का भेजा जाना उन के सुपुर्द हुआ हो, सकौन्सिल

गवर्नर जनरल की सेवा में मुकद्दमे की विशेष रिपोर्ट भेजें, और  
सकौन्सिल गवर्नर जनरल उक्त रिपोर्ट को उन लोगों की सूचना के  
लिये, जो उस मुकद्दमे के विवाद युक्त विषय से सम्बन्ध रखते हों,  
उस प्रकार से प्रकाशित करायेंगे जैसा कि वह उचित समझे ।

धारा ३९—सिवाय इसके कि पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अभि-  
रेलवे कमीशन का टूटना प्राय के लिये हो, कमिशनरों के उन  
इजलासों के अन्तिम इजलास की समाप्ति पर, जो उनको सुपुर्द हुए  
मुकद्दमों के निर्णय करने के लिये हों, यह समझा जायगा कि रेलवे  
कमीशन टूट गया ।

परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसे मनुष्यकी प्रार्थना पर, जो उस  
कार्यवाही का कोई फरीफ हो जो कमिशनरों के सामने हो या उक्त  
मनुष्य के प्रतिनिधि की प्रार्थना पर, सकौन्सिल गवर्नर जनरल को  
अधिकार है कि यदि वह उचित समझे, उस मुकद्दमे में जिसमें कि  
कमिशनरों द्वारा दी हुई आज्ञा की अपील न हो सकती हो, अपने निर्णय  
के पुनर्विचार की प्रार्थना सुनने के अभिप्राय के लिये, उसे स्वीकार  
करने, और यदि वे यह समझें कि मुकद्दमा फिर से सुना जाना चाहिये  
तो उस मुकद्दमे को फिर सुनने के लिये, कमिशनरों को पुनः  
नियुक्त करें ।

धारा ४०—इस परिच्छेद की पिछली आज्ञाओं के आधीन  
इस परिच्छेद की पिछली आज्ञाओं और सकौन्सिल हर मजिस्ट्री  
के आधीन, रेलवे कमीशन की साम्राज्ञी की किसी आज्ञा के  
आज्ञाओंकी अपरिवर्तननियिता आधीन, कमिशनरों की आज्ञा

कतई होगी और न तो उक्त पर किसी अदालत की ओर से आपत्ति  
होगी और न वह इसकी जासेगी ।

**धारा ८१—**सिवाय इसके जो इस एक्ट में आजा हो, किसी कुछेसे मामले जो रेलवे कमीशन ऐसे कार्य या कार्य-त्याग के द्वारा विचार योग्य हों साधारण सम्बन्ध में कोई नालिश या अदालतों के विचार अधिकार कार्यवाही न की जा सकेगी, जो रेलवे प्रबंधक ने, इस परिच्छेद से बाहर हैं।

की किसी आजा की प्रतिकूलता या विरोध में या उस आजा की प्रतिकूलता या विरोध में, किया हो, जो कमिशनरों या हाईकोर्टने इस एक्ट के अनुसार प्रदान की हो।

### ट्राफिक की सुगमताएं

**धारा ४२—(१)** प्रत्येक रेलवे प्रबंधक उन रेलवियों पर या रेलवे प्रबंधकों का कर्त्तव्य है कि उन रेलवियों से जिनका वह वह बिना अनुचित विलम्ब और मालिक हो या जिन को वह बिना तरफ़दारी के ट्राफिक के चलाता हो, ट्राफिक लेने, भेजने लेने और भेजने का प्रबंध करे। और देने के लिये तथा पहिंचे

वाली चीजों की वापिसी के लिये, अपने अधिकारों के अनुकूल समस्त उचित सुगमताएं प्रदान करेगा।

(२) कोई रेलवे प्रबंधक किसी विशेष मनुष्य या रेलवे प्रबंधक को, या उनके एक से, या किसी विशेष प्रकार के ट्राफिक के संबंध में, किसी प्रकार की दायें न हो कोई अयोग्य या अनुचित विशेषता न देगा या लाय न पहुंचायेगा, या किसी विशेष मनुष्य या रेलवे प्रबंधक को या विशेष प्रकार के ट्राफिक को, किसी प्रकार की दायें न हो कोई अयोग्य या अनुचित हानि या क्षति न पहुंचायेगा।

(३) ऐसे रेलवे प्रबंधक को जो किसी ऐसी रेलवे को रखता या चलाता हो जो किसी रेलवे के लगातार आवागमन की लाइन का भाग हो, या जिसका आखिर मन्जिल या स्टेशन दूसरे रेलवे प्रबंधक के आखिर मन्जिल या स्टेशन से एक मील से भीतर हो, आवश्यक होगा कि वह ऐसे समस्त ट्राफिक के लेने में जो उनमें से एक रेलवे से दूसरे आखिर मन्जिल या स्टेशन पर पहुंचे और उसमें से दूसरी रेलवे पर उसी भेजने में समस्त योग्य और उचित सुगमताएं बिना किसी अनुचित विलम्ब के और बिना किसी ऐसी विशेषता या लाय या हानि या क्षति के जिसका कि ऊपर वर्णन हुआ,

प्रदान करें, ताकि उक्त रेलवियों को आवागमन की लगातार लाइन की तरह प्रयोग करने की इच्छुक जनता को कोई रुकावट न हो, और ताकि जनता को इस सम्बन्ध में हर समय उक्त रेलवियों द्वारा समस्त उचित सुख सामिग्री प्राप्त हो सके।

(४) जो सुगमताएँ इस धारा द्वारा प्रदान की जायगी उनमें प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक की ओर से दूसरे रेलवे प्रबन्धक की प्रार्थना पर, किसी अन्य रेलवे प्रबन्धक को रेलवे से या रेलवे को, थर्ग्रेट के हिसाब से, थर्ग्रेट का योग्य और उचित रूप से प्राप्त करना, भोजना और प्रदान करना सम्मिलित है। परन्तु शर्त यह है:—

[ क ] कि वह रेलवे प्रबन्धक जो ट्राफिक को भोजना चाहें अपने प्रस्तावित महसूल थर्ग्रेट की लिखित सूचना प्रत्येक प्रेषक रेलवे प्रबन्धक को देगा जिसमें उसकी रकम और हिस्सा रसदी दोनों और वह रास्ता जिससे कि ट्राफिक को भेजे जाने का प्रस्ताव ही, वर्णन होगा। जानवरों या माल का प्रस्तावित थर्ग्रेट का महसूल प्रति ट्रंक [ खुलीगाड़ी ] या प्रति मन के हिसाब से हो सकता है।

[ ख ] कि उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् नियत समय के भीतर, प्रत्येक प्रेषक रेलवे प्रबन्धक को आवश्यक होगा कि वह उस रेलवे प्रबन्धक को जो ट्राफिक को भोजना चाहे, इस बात की लिखित सूचना दे कि आया वह उक्त रेट, हिस्सा रसदी और रास्ते से राजी है या नहीं, और, यदि उसको कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति के कारण क्या हैं,

[ ग ] यदि उक्त नियत समय की समाप्ति पर प्रेषक रेलवे प्रबन्धक द्वारा कोई आपत्ति न की जाय, तो उक्त समय के व्यतीत होने पर वही महसूल प्रभावित होगा।

[ घ ] यदि नियत समय के भीतर महसूल हिस्सा रसदी या रास्ते के सम्बन्धमें कोई आपत्ति भेजी जाय, तो सकौन्सिल गवर्नर जनरल, यदि उचित समझें तो, रेलवे प्रबन्धकों में से किसी की प्रार्थना पर, झगड़े को निर्णय करने के लिये कमिशनरों को सुपुर्द कर सकते हैं।

[ ङ ] यदि महसूल या रास्ते के स्वीकार करने के सम्बन्धमें आपत्ति हो तो कमिशनर्स इस बात का विचार करेंगे कि आया महसूल का स्वीकार होना सार्वजनिक हित के लिये

योग्य और उचित सुगमता है या नहीं, और स्थितियों पर ध्यान रखते हुए, प्रस्तावित रास्ता उचित रस्ता है या नहीं, और वह उक्त महसूल को अनुसारतः रबीकार या अस्वीकार कर देंगे, या कोई ऐसा अन्य महसूल नियत कर देंगे जो कमिश्नरों को ठीक और उचित मालूम होता हो।

[ च ] यदि आपत्ति महसूल के केवल हिस्सा रसदी के सम्बन्ध में हो, और मुकद्दमा कमिश्नरों के सुपुर्दे हो गया हो, तो महसूल का रेट नियत समय के व्यतीत होने पर प्रभावित हो जायगा, परन्तु उसका हिस्सा रसदी के सम्बन्ध में कमिश्नरों का निर्णय अतीत काल पर प्रभावित होगा, अन्य आपत्ति की अवस्था में, महसूल का प्रभावित होना उस समय तक स्थगित रहेगा जब तक कि कमिश्नर लोग मुकद्दमे में अपनी आज्ञा न प्रदान कर दें।

[ छ ] कमिश्नर धर्रेट के हिस्सा रसदी करने में मुकद्दमे की कुल स्थितियों पर विचार करेंगे जिनमें वह विशेष व्यय सम्मिलित है जो किसी रास्ते या रास्ते के भाग के बनवाने, रखने या खलाने में पड़ा हो और जिनमें वह विशेष खर्च भी सम्मिलित है जो कोई रेलवे प्रबन्धक उसके सम्बन्ध में दावा करने का अधिकारी हो।

( ज ) कमिश्नर किसी दशामें किसी रेलवे प्रबन्धक को ऐसे महसूल प्रति मील से कम महसूल प्रति मील देने के लिये विवश न करेंगे, जिसे रेलवे प्रबन्धक उसी प्रकार के ऐसे ट्राफिक के सम्बन्ध में, जो आने जाने के सायान साधन द्वारा आने जाने की किसी अन्य लाइन पर वैसे ही दो स्थानों के बीच अर्थात् धरु मार्ग के रवाना होने के स्थान और आगमन के स्थान के बीच लेजाया जाता हो, उस समय कानून के अनुसार लेता रहा हो।

[ ङ ] इस उपधारा की पूर्वोक्त शालाओं के आधीन, कमिश्नरों को इस बात के निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा कि प्रस्तावित पिट रेट योग्य और उचित है चाहे किसी प्रेषक रेलवे प्रबन्धक के विरुद्ध पिट रेट से उस अधिकतम अधिक महसूल से कम ही पैसे न उठा जाय, जो कि उस रेलवे प्रबन्धक

मांगने का अधिकारी होता, और यह कि वह उसके अनुसार थिरेरेट को उचित मानें और हिस्सा रसदी नियत कर दें।

[ ३ ] निर्धारित समय जिसका कि इस उपधारा में वर्णन हुआ है एक मास या ऐसा अधिक समय होगा जो संकौन्तिल गवर्नर जनरल सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा नियत करें।

**धारा ४३—**( १ ) जब कि यह दिखलाया जाय कि रेलवे समान ट्राफिक या सेवाओं के प्रबन्धक किसी व्यापारी से, लिखे विषम महसूलों की अवस्था किसी प्रकार के व्यापारियों से में अनुचित विशेषता । या किसी स्थानीय क्षेत्र फल के

व्यापारियों से वैसे ही या उसी प्रकार के जानवरों या माल के सम्बन्ध में, या वैसी ही या उसी प्रकार की सेवाओं के सम्बन्ध में, उस से कम महसूल लेता है जो वह अन्य व्यापारियों से, अन्य प्रकार के व्यापारियों से या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र फल के व्यापारियों से लेता है, तो इस बात के प्रमाणित करने का भार कि उक्त कम महसूल अनुचित विशेषता की श्रेणी तक नहीं पहुंचता, रेलवे प्रबन्धक पर होगा।

[ २ ] इस बात के निर्णय करने में कि अमुक कम महसूल अनुचित विशेषता की श्रेणी तक पहुंचता है या नहीं, कमिश्नरों को अधिकार होगा कि जहां तक वे उचित समझें, मुकद्दमासम्बन्धी अन्य विचारों के साथ यह बात भी विचार में रखें कि सार्वजनिक हित के विचार से उस ट्राफिक के प्राप्त करने के अभिप्राय के लिये जिस के लिये कि कम महसूल मांगा गया हो, उक्त कम महसूल मांगना आवश्यकीय है या नहीं।

**धारा ४४—**जब कि रेलवे प्रबन्धक ऐसे इकरार नामे का सुगमताओं और समान व्यवहार प्रणीत हो जो उस रेलवे का सम्बन्धी आज्ञापं जब कि ऐसे ट्राफिक प्राप्त करने के लिये हुआ जहाज़ या बोट प्रयुक्त हों जो हो जिस को किसी देशागत जल रेलवे का भाग नहीं है। पर ऐसी नाव, जहाज़, बोट या

वेड़े द्वारा लेजाता हो, जो रेलवे प्रबन्धक के न हों और न रेलवे प्रबन्धक जिन को किराये पर ले और न चढाये, तो पूर्वोक्त अन्तिम दो धाराओं की आज्ञापं जो रेलवे के सम्बन्ध में हैं नाव, जहाज़.

गोट या ब्रेड से, जहां तक कि वह रेलवे के ट्राफिक के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त हो, सम्बन्ध रखेंगी।

धारा ४५—रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह आखिरी आखिरी मंजिल के किराये | मंजिल के उचित महसूल मांगे।

धारा ४६—[१] लोकान्तिगल गवर्नर जनरल को अधिकार है आखिरी मंजिल के किराये | कि यदि वह उचित समझें तो वह निम्न करने का रेलवे कमीशन | किसी ऐसे प्रश्न या झगड़े को को अधिकार है। जो किसी ऐसे आखिरी मंजिल

के किरायों के सम्बन्ध में उत्पन्न होता हो जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा दाने जाते हों, निर्णयार्थ कमीशनरों के सुपुर्द करे, और कमीशनर तब इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि आखिरी मंजिल के किरायों के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक को क्या रकम दिलाना उचित है।

[२] उक्त प्रश्न या झगड़े के निर्णय करने में कमीशनरों को आवश्यक होगा कि वह केवल उस व्यवस्था पर विचार करें जो उस सुख-सामग्री के जुटाने के लिये उचित रूप से आवश्यक हो जिस के सम्बन्ध में कि आखिरी मंजिल के किराये मांगे जाते हों, बिना ध्यान में रखे हुए उन व्ययों के जो उक्त सुख-सामग्री के जुटाने में रेलवे प्रबन्धक ने वास्तव में किया हो।

## छटा परिच्छेद रेलवे का चलाना सामान्य

धारा ४७—[१] प्रत्येक रेलवे कम्पनी और, उस रेलवे की सामान्य नियम | दशा में जिसका प्रबन्ध गवर्नमेन्ट के हाथ में हो, वह सफासर जो इस सम्बन्ध में लोकान्तिगल गवर्नर जनरल की ओर से नियुक्त हों, इस एक्ट के अनुसूचक निम्न धर्मिप्राप्तों के लिये सामान्य नियम बनाएंगे, अर्थात्:—

[क] उस विधि के प्रबन्धके लिये कि जिस विधि से, और उस गति के प्रबन्ध के लिये कि जिस गति से वह पहियेदार चाँई जो रेलवे पर प्रयुक्त हो, चलाये जाते हैं।



- ( ख ) \* यात्रियों को सुख और सहूलियत के सामान संग्रह करने के लिये और उन का माल असबाब ले जाने के लिये ;
- ( ग ) \* यह निश्चय करने के लिये कि इस एक्ट के अधिप्रायों के लिये भयानक और हानि प्रद माल क्या २ समझा जायगा और ऐसे माल के ले जाने के प्रबन्ध के लिये,
- ( घ ) उन शक्तों के प्रबन्ध के लिये जिस पर कि रेलवे प्रबन्धक सांक्रामिक या दूत के रोगों से ग्रस्त यात्रियों को ले जायगा और उन गाड़ियों को जो उक्त यात्रियों द्वारा प्रयोग की जाय रोगरहित कराने के प्रबन्ध के लिये,
- [ ङ ] रेलवे नौकरों के आचरण के प्रबन्ध के लिये,
- [ च ] + उन नियमों और शक्तों के प्रबन्ध के लिये जिन पर कि रेलवे प्रबन्धक उस मनुष्य की ओर से जिस को कि माल भेजा जाय या मालिक की ओर से, किसी स्टेशन पर गोदाम में माल दाखिल करेगा या रखेगा । और
- [ छ ] \* सामान्यतः रेलवे पर सफ़र करने के लिये और रेलवे के प्रयोग, चलाने और प्रबन्धक को ठीक करने के लिये;

\* रेलवे-नौकरों के काम करने, चाल चलन, और मुसाफ़िरों और भयानक माल के ले जाने के सम्बन्ध में, ब्रिटिश इंडिया में उन तमाम खुली हुई लाइनों के लिये जो गवर्नमेन्ट के प्रबन्ध में हों, देखिये जनरल स्टैट्यूट आर एन्ड ओ जिल्द ३ पृष्ठ १३५० ।

+ उन नियमों के लिये जो ब्रिटिश इंडिया की समस्त रेल-वियों से लागू हों और जो उन शक्तों और नियमों के सम्बन्ध में हैं जिन पर कि रेलवे प्रबन्धक उस मनुष्य की ओर से जिस को कि माल भेजा जाय या मालिक की ओर से स्टेशन या डिपो पर, माल गोदाम में दाखिल करेगा या रखेगा, देखिये जनरल स्टैट्यूट आर एन्ड ओ जिल्द ३ पृष्ठ १३४५ ।

[ २ ] नियमों में यह आज्ञा हो सकती है कि वह मनुष्य जो उन में से किसी नियम का उल्लंघन करेगा उस को ऐसे जुर्माने की सजा होगी जिस की संख्या ५० तक हो सकती है, और यह कि उस नियम की अवस्था में जो उप धारा [ १ ] के खण्ड [ ड ] के अनुसार बने, रेलवे के नौकरों को उतना रूपया ज़बती में देना पड़ेगा जो एक महीने के वेतन से अधिक न हो, और जिस रुपये को रेलवे प्रबंधक उस के वेतन से मुजरा कर सकता है ।

[ ३ ] इस धारा के अनुसार बने हुए नियम का उस समय तक प्रभाव न होगा जब तक कि उस की मन्जूरी सिकौन्सिल गवर्नर जनरल से न हो जाय और जब तक कि वह भारतीय गज़ट में प्रकाशित न हो जाय ।

परन्तु शर्त यह है कि, जहां उक्त नियम उस नियम की शर्तों में हो जो भारतीय गज़ट में सविस्तार प्रकाशित हो चुका हो तो उक्त गज़ट में ऐसी विज्ञप्ति होना जिस में उस नियम का हवाला हो जो अभी उप नुका हो और जिस में उस पर अमल करने की सूचना दी गई हो, इस उप धारा के अर्थ के अन्तरगत भारतीय गज़ट में नियम का प्रकाशित होना समझा जायगा ।

[ ४ ] सिकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह इस धारा के अनुसार बने हुए किसी नियम को रद्द कर दे, और उस अपसर हो जिस को उप धारा के अनुसार यह आज्ञा हो कि उक्त उप धारा के अनुसार नियम बनाये, यह अधिकार होगा कि सिकौन्सिल गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से उक्त किसी नियम को रद्द कर दे या बदल दे ।

[ ५ ] जिस नियम से यह प्रकट होता हो कि वह किसी रेलवे के लिये भारतीय \* रेलवेयों के कानून सन १८७९ [ एक्ट १ सन् १८७९ ] की धारा ८ के अनुसार बनाया गया है, और भारतीय गज़ट से यह प्रकाशित होता हो कि इस एक्ट के प्रचार-आरम्भ

उन तमाम खुली लाइनों के लिये जो गवर्नमेन्ट के प्रबंध में हों भयानक माल संबंधी सामान्य नियमों में संशोधन के लिये देखिये, भारतीय गज़ट सन् १९०७, भाग १ पृष्ठ ६३९ और ८६१,

\* इस एक्ट द्वारा मंजूर हुआ ।

पर उक्त रेलवे से उक्त नियम का सम्बन्धित करना विचारणीय है तो चाहे उक्त नियम के बनाये जाने या प्रकाशित किये जाने में कोई दोष ही क्यों न हो, यही समझा जायगा कि उक्त नियम इस धारा के अनुसार बना और प्रभावित हुआ है।

[ ६ ] प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक के लिये आवश्यक होगा कि वह अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर उन सामान्य नियमों की एक नकल रखे जो इस धारा के अनुसार उस समय रेलवे में जारी हों और तमाम उचित समयों पर हर किसी मनुष्य को उसे मुफ्त देखने की अनुमति दे ।

धारा ४८—जब कि दो या अधिक रेलवे प्रबन्धक ऐसे हों, जो संयुक्त ट्राफिक के संचालन के सम्बन्ध में रेलवेयों के मत भेद का निर्णय

संयुक्त आखिरी मंजिल रखते हों या जिन की रेलवे की एक ही लाइन का भाग संयुक्त हो, या

रेलवे की आमदरफ्त की सिलसिलेवार लाइन में जिनके प्रथम २ भाग हों और जो उक्त संयुक्त आखिरी मंजिल में या अपने बीच के जोड़ में, सार्वजनिक रक्षा के साथ, अपने संयुक्त ट्राफिक के संचालन के प्रबन्ध में सहमत न होते हों, तो, सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि उन प्रबन्धकों या किसी प्रबन्धक की प्रार्थना पर उन विवाद प्रस्तुत बातों का जो उन के बीच में हों, वहां तक निर्णय करे जहां तक कि उन बातों का सम्बन्ध सार्वजनिक रक्षा से हो, और यह निर्णय करे कि उन प्रबन्धों में होने वाला कुल व्यय या उसका कितना अंश सब प्रबन्धकों की या किसी प्रबन्धक को क्रमशः उठाना पड़ेगा।

धारा ४९—प्रत्येक रेलवे कम्पनी को, जो पेसी रेलवे कम्पनी पहिले दार चीजों के बनाने या उनका पट्टा लेने के सम्बन्ध में सकौन्सिल गवर्नर जनरल से इकरार नामे।

न हो जिसके सम्बन्ध में स्टेट्यूट ४२ और ४३ ब्रिक्टोरिया परि-  
चलेद ४१ में आज्ञा है, अधिकार होगा कि वह समय २ पर किसी

पेसी पहिले वाली चीज, यंत्र या फल के बनाने के लिये जो रेलवे

पर या रेलवे के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती हो, या किसीऐसी पट्टिये वाली चीज़, यंत्र या कल या सामान पट्टे पर देने या लेने के लिये लो रेलवे पर प्रयोग करने के लिये आवश्यक हो, या पट्टिये वाली चीज़ों के स्थिर रखने के लिये, सकोन्सिल गवर्नर जनरल के साथ इकरार नामे करे और उन पर अमल करे ।

**धारा ५०—**प्रत्येक रेलवे कम्पनी को जो ऐसी रेलवे कम्पनी रेल चलाने का इकरार नामा न हो, जिसके सम्बन्ध में स्टैट्यूट करने के सम्बन्ध में रेलवे ४२ और ४३ विक्टोरिया परि-कम्पनियों का अधिकार चलेख ४१ में आज्ञा है, अधि-कार होगा कि वह समय २ पर, सकोन्सिल गवर्नर जनरल से, या उनकी मंजूरी लेकर किसी अन्य रेलवे प्रबन्धक से, निम्न प्रयोजनों में से किसी के सम्बन्ध में इकरार नामा करे और उस पर अमल करे, अर्थात्:—

- ( क ) किसी रेलवे के चलाने, प्रयोग, प्रबन्ध और स्थिर रखने के सम्बन्ध में,
- ( ख ) ऐसी पट्टियेदार चीज़ों और मशीनों के जुटाने के सम्बन्ध में जो खण्ड ( क ) में वर्णित किसी अभिप्राय के लिये आवश्यक हों और रेलवे ट्राफिक के संचालन के लिये अफसरों और नौकरों के संग्रह करने के सम्बन्ध में,
- ( ग ) उक्त संचालन, प्रयोग, प्रबन्ध और स्थिरता विषयक उन रकमों के सम्बन्ध में जो अदा की जायगी और उन शर्तों के सम्बन्ध में जो पूरी की जायगी
- ( घ ) ऐसे ट्राफिक के अदल बदल, ट्राव—सासिग्री और लेजाने के सम्बन्ध में जो इकरार नामा करने वाले फरीदों की पृथक २ रेटरिगोपर हों, या रेलवे से आता हो या जिनका उक्त रेलवे से पर लेजाने का विचार हों, और उस आय के नियत करने, संग्रह करने, बांटने और प्रयोग करने के सम्बन्ध में जो उक्त ट्राफिक से प्राप्त हो ।
- ( ङ ) सामान्यतः, इस धारा में उपरि वर्णित किसी प्रयोजन सम्बन्धी किसी ऐसी आग या चूर्त को अमल में लाने के सम्बन्ध में जो इकरार करने वाले फरीद उचित राशद और रिशत पर ऐ परस्पर सहमत हों

परन्तु शर्त यह है कि इकरार उन महसूलों पर कोई प्रभाव न डालेगा जिनके किसी मनुष्य से, समय २ पर, क्रमशः मांगने और लेने के वे रेलवे प्रबन्धकों को इकरार नामे के फरीकैन हैं, अधिकारी हैं, और प्रत्येक ऐसा मनुष्य, उक्त इकरार नामे के होते हुए भी, उक्त रेलवे प्रबन्धकों की रेलवे को प्रयोग करने और काममें लेने का उन्हीं शर्तों और नियमों पर, और उन्हीं महसूलों के देने पर, अधिकारी होगा जो वह उस समय होता जब कि उक्त इकरार नामा न किया गया होता।

**धारा ५१—**प्रत्येक रेलवे कम्पनी, जो जो ऐसी रेलवे कम्पनी ट्राफिक के आराम के लिये न हों जिसके सम्बन्ध में स्टेट्यूट घाटों और रास्तों का ४२ और ४३ विक्टोरिया, परिच्छेद ४१, में आज्ञा है, अधिकार है कि स्थापित किया जाना वह सफ़ौन्सिल गवर्नर जनरल की स्वीकृति से, समय २ पर, निम्न सब अधिशारों का या किसी अधिकार का प्रयोग करे, अर्थातः—

- (क) उसको अधिकार है कि वह अपनी रेलवेके ट्राफिकके आराम के लिये, ऐसी गुज़ारेका घाट स्थापित करे जो अच्छे प्रकारके और पर्याप्त परिमाणमें यंत्रों और कलोंसे संग्रहीत हो ताकि गुज़ारे के घाट का काम चल सके।
- (ख) उसको अधिकार है कि किसी ऐसे गुज़ारे के घाट को जिसको उसने स्थापित किया हो, रेलवे के ट्राफिक के आराम के अतिरिक्त अन्य अभिप्रायों के लिये काम में लावे।
- (ग) उसको अधिकार है कि वह अपने पुलोंमेंसे किसीपर पैदल चलने वालों, जानवरों, गाड़ियों, छकड़ों या अन्य ट्राफिक के लिये रास्ते बनवायें और उनको स्थिर रखे।
- (घ) उसको अधिकार है कि वह अपनी रेलवे से या रेलवे को आने जाने वाले ट्राफिक के आराम के लिये रास्ते बनवाये और स्थिर रखे।
- (ङ) उसको अधिकार है कि आने जाने के ऐसे साधन बनाये और स्थिर रखे जो ऐसे यात्रियों, जानवरों या माल की उचित सहूलियत के लिये आवश्यक हों जो उसकी रेलवे से ले जाये जाय या ले जाये जाने वाले हों।
- (च) उसको अधिकार है कि उस ट्राफिक पर जो वह गुज़ारे के

घाटों, रास्तों, मारगों, या आने जाने के साधनों को काम में लाये, जो इस धारा के अनुसार बनाये जाय, उस मद्दसूल के निरखों की सूची के अन्तर्कूल, राह दारी के किराये लगाये, जो सफ़ौन्सिल गवर्नर जनरल की मंजूरी से समय २ पर तैयार की जाय ।

धारा ५२—प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक के लिये आवश्यक होगा कि

नकशे / वह उन नमूनों में जो सफ़ौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित किये जाय, अर्द्ध वार्षिक या उन समयों पर जो सफ़ौन्सिल गवर्नर जनरल द्वारा नियत किये जाय, अपनी पूंजी, आय, के मामलों और अपने ट्राफिक के ऐसे नकशे तैयार करे जैसा कि सफ़ौन्सिल गवर्नर जनरल आज्ञा दें, और उक्त नकशों की एक नकल सफ़ौन्सिल गवर्नर जनरल की सेवा में उन समयों पर भेजे जैसा शिष्ट आज्ञा करें ।

## रम्पटि का लाना लेजाना

धारा ५३—(१) प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक हर माल गाड़ी या माल गाड़ी के डिब्बे के लिये / खुली गाड़ी के लिये जो उसके अधिक से अधिक बोझ / कदजे में हो, अधिक से अधिक बोझ निर्णय कर देगा, और उन शर्तों या अङ्कों को जो उक्त प्रकार निर्णय किये हुए बोझ को दृढ़ताते हों, प्रत्येक उक्त माल गाड़ी के या खुली गाड़ी के यादर विविष्ट रीति से प्रकट कर देगा ।

(२) प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसी माल गाड़ी या खुली गाड़ी का मालिक हो जो रेलवे पर होकर आनी जाती हो, आवश्यक होगा कि माल गाड़ी के या खुली गाड़ी के लिये इसी तरह पर अधिक से अधिक बोझ को निर्णय और प्रकट करे ।

(३) ऐसी प्रत्येक माल गाड़ी या खुली गाड़ी का कुल बज़न जो उस समय घुरी पर हो, जब कि माल गाड़ी या खुली गाड़ी में बोझ एक रूप से अधिक से अधिक भर दिया जाय, उस हद् से अधिक न होगा जो सफ़ौन्सिल गवर्नर जनरल उस प्रकार की घुरी के लिये नियत कर दें जो उस माल गाड़ी या खुली गाड़ी के नीचे हो ।

**धारा ५४—(१)** स्कौन्सिल गवर्नर जनरल की निगरानी रेलवे प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि वह ट्राफिक चलाने के लिये शर्तें लगाये | के आधीन, रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह जानवरों या माल के लेने, भेजने या देने के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगाये जो इस एक्ट के प्रतिकूल न हों और न किसी ऐसे सामान्य नियम के प्रति कूल हो जो उस के अनुसार बना हो।

( २ ) रेलवे प्रबन्धक अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर उन शर्तों की एक फापी रखेगा जो उपधारा ( १ ) के अनुसार उस समय स्टेशन पर प्रचलित हों, और प्रत्येक मनुष्य को तन्नाम उचित समयों पर उसे मुफ्त देखने की अनुमति देगा।

[ ३ ] रेलवे प्रबन्धक उस जानवर को लाने लेजाने के लिये बाध न होगा जो किसी सांक्रामिक या छूत के रोग से ग्रसित हो।

**धारा ५५—[ १ ]** यदि कोई मनुष्य रेलवे प्रबन्धक द्वारा या महसूलों, आखिरी मन्जिल के किरायों और अन्य रकमों के लिये माल रोक लेना | रेलवे प्रबन्धक की ओर से मांगा जाने पर उस महसूल, आखिरी मन्जिल के किराये या अन्य रकम को न दे जो उससे किसी जानवर या माल के सम्बन्ध में पावना है, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उस मनुष्य के सब जानवरों या माल को या किसी जानवर या माल को रोक ले, या यदि उक्त जानवर या माल रेलवे से पृथक् कर लिये गये हों तो उक्त मनुष्य के अन्य जानवर या माल को रोक ले जो उस समय रेलवे प्रबन्धक के कब्जे में हो या तत्पश्चात् आवे।

( २ ) जब कि उपधारा [ १ ] के अनुसार कोई जानवर या माल रोक लिया गया हो, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह, नष्ट योग्य माल की अवस्था में तुरन्त ही, और अन्य माल या जानवरों की अवस्था में, अभीष्ट नीलाम की एवम् रोज़ा ऐसी सूचना का समय मुहर जाने पर, जो एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हो, या जहाँ ऐसा कोई समाचार पत्र न हो तो उस विधि में जैसा कि स्कौन्सिल गवर्नर जनरल नियत करें, सार्वजनिक नीलाम द्वारा, उक्त उतने जानवर या उतना माल

नीलाम करें जिससे उतनी रकम निकल आवे जो उक्त मतालवे और उक्त रोक, सूचना और नीलाम के तमाम व्ययों के बराबर हो। उक्त व्ययों में, जानवरों की दशा में, वह व्यय सम्मिलित है जो उनके खिलाने, पिलाने और रख पाळी करने में हैं।

( ३ ) नीलाम की ठिकी में से, रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उतनी रकम रोक ले जो उक्त मतालवे और उक्त व्ययों के बराबर हो, और ठिकी का शेष, यदि कुछ हो, और उन जानवरों और माल को, यदि कुछ हो, जो अविक्रित रह गये हों, उस मनुष्य को दे दे जो उन जानवरों या माल का अधिकारी हो।

[ ४ ] यदि कोई मनुष्य जिससे कि कोई महसूल, आखिरी मजिद का किराया या अन्य मतालवा मांगा गया हो, रेलवे स्टेशन से, उचित अपघि के भीतर उन जानवरों या माल को न हटावे जो उपधारा [ १ ] के अनुसार रोक लिये गये हों या उन जानवरों या माल को न हटावे जो उपधारा [ २ ] के अनुसार नीलाम के पश्चात् अविक्रित रह गये हों, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उन सब का नीलाम कर दे और नीलाम की आय के सम्बन्ध में जहां तक हो सके लगभग उपधारा [ ३ ] के अनुसार कार्यवाही करे।

[ ५ ] उपर्युक्त उपधाराओं में चाहे कुछ ही क्यों न हो, रेलवे प्रबन्धक, मालिक द्वारा, उक्त महसूल, आखिरी मजिद के किराये या अन्य मतालवे को जिसका कि ऊपर वर्णन हुआ या उस के शेष रुपये को पसल कर सकता है।

धारा ५६—[ १ ] जब कोई जानवर या माल किसी रेलवे स्टेशन में ऐसी बीजों के सम्बन्ध में प्रबन्धक के फरजे में लाने लेजाने में कार्यवाही सिद्ध होई या किसी अन्य कार्य के लिये पाठे जाय तो

उक्त मालिक या उस अन्य मनुष्य की ओर से दावा न किया जाय जो रेलवे प्रबन्धक को उक्त रोक अधिकारी प्रतीत हो, तो रेलवे प्रबन्धक, यदि उक्त मालिक या मनुष्य का पता मालूम हो तो, उक्त रोक सूचना की तामील बराबरी कि वह जानवरों या माल को ले जावे।

[ २ ] यदि उक्त मालिक या मनुष्य का पता मालूम न हो, या सूचना की रस पर तामील न हो सकती हो, या यदि वह सूचना की



आज्ञा का पालन न करे तो, रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह, उचित समय के भीतर और किसी ऐसे अन्य कानून की आज्ञाओं के अधीन जो उस समय प्रचलित हो, सम्भवतः लगभग पूर्वोक्त अन्तिम धोरा के अनुसार उन जानवरों या माल को बेच दे और नीलाम की आय का शेष रूपया, यदि कुछ हो तो, किसी ऐसे मनुष्य को दे दे जो उसका अधिकारी हो।

**धारा ५७—**जब कि किसी ऐसे जानवर माल या नीलाम की कुछ अवस्थाओं में माल के देने आय पर जो रेलवे प्रब-  
पर जमानत मांगने का रेलवे प्रबन्धकों न्धक के कब्जे में हो, दो  
का अधिकार या अधिक मनुष्य दावा

करे, या ऐसी टिकट या रसीद पेश न की जाय जो जानवरों या माल के लिये दी गई हो, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह उक्त जानवरों, माल या नीलाम की आय को देना उस समय तक ले लिये रोक दे जब तक कि वह मनुष्य, जो रेलवे प्रबन्धक की सम्मति में उनके प्राप्त करने का अधिकारी हो, उस के सन्तोषानुसार उन जानवरों, माल या नीलाम की आय सम्बन्धी किसी अन्य मनुष्य के दावों के मुकाबिले में, जमानत न दे दे।

**धारा ५८—**(१) मालिक या वह मनुष्य जिसकी निगरानी में माल की तफसील का लेख वह माल हो जो रेलवे पर, उसके बद्ध हस्ताप मांगा जाना द्वारा ले जाये जाने के अभिप्राय से

लाया जाय, और वह मनुष्य (प्राप्ति—पात्र) जिसके नाम कि वह माल भेजा गया हो जो रेलवे पर ले जाया गया हो, किसी ऐसे रेलवे के नौकर की प्रार्थना पर जो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियुक्त किया लाये रेलवे के उक्त नौकर को लेख बद्ध ऐसा हस्ताप देगा जिस पर उक्त मालिक के या उस मनुष्य के या प्राप्ति—पात्र के हस्ताक्षर हों और जिसमें उक्त माल का ऐसा विवरण हो जो उस महसूल के निश्चय करने के लिये पर्याप्त हो जो रेलवे प्रबन्धक उसके सम्बन्ध में लेने का अधिकारी है।

(२) यदि उक्त मालिक, मनुष्य या प्राप्ति—पात्र उक्त हस्ताप देने से इनकार करे या देने में असाधधानता करे, और पारसल या

पेंकेज को जिसमें कि माल हो, इस अभिप्राय से कि उसमें किस प्रकार का माल है निश्चय होजायगा, खोलने से इन्कार करे, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि [क] उस माल के सम्बन्ध में जो रेलवे पर लेजाये जाने के अभिप्राय से लाया गया हो, उस समय तक लाने लेजाने से इन्कार कर दे जब तक कि उसके सम्बन्ध में ऐसा महसूल न दे दिया जाय जो उस सब से बड़े महसूल से अधिक न हो जो उस समय रेलवे में किसी प्रकार के माल के लिये जारी हो, या (ख) उस माल के सम्बन्ध में जो रेलवे पर लेजाया गया हो, ऐसा महसूल मांगे जो उक्त सब से बड़े महसूल से अधिक न हो।

( ३ ) यदि वह हिलाद जो उपधारा ( १ ) के अनुसार दिया जाय उस माल के विवरण के सम्बन्ध में वास्तव में झूठा हो जिससे उस विवरण का सम्बन्ध समझा जाता हो, और जो रेलवे पर लाया या लेजाया गया हो, तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह माल को लाने लेजाने के सम्बन्ध में ऐसा महसूल मांगे जो ऐसे सब से बड़े महसूल के तुल्य महसूल से अधिक न हो, जो उस समय रेलवे पर किसी प्रकार के माल के लिये जारी हो, ।

( ४ ) यदि रेलवे के नॉकर और ऐसे माल के मालिक, जुम्मेदार या प्राप्ति—पात्र के बीच में, जो रेलवे पर लेजाने के लिये लाया गया हो या रेलवे पर लेजाया गया हो, उस माल के विवरण के सम्बन्ध में, जिसका कि हिलाद इस धारा के अनुसार दे दिया गया हो, कोई मत—भेद उत्पन्न हो, तो रेलवे के नॉकर को अधिकार है कि वह माल को रोक ले और उसकी जांच करे ।

( ५ ) यदि जांच से यह बात मालूम हो कि उपधारा ( १ ) के अनुसार दिये हुए हिलाद में वर्णित विवरण से उक्त माल का विवरण भिन्न है, तो वह मनुष्य जिसने कि हिलाद दिया, या, यदि वह मनुष्य माल का मालिक न हो तो वह मनुष्य और मालिक संयुक्तः और प्रत्येकः रेलवे प्रबन्धक को उक्त माल को रोकने और जांचने का पद देन के जुम्मेदार होंगे, और रेलवे प्रबन्धक उस हानि सम्बन्धी तमाम उत्तर दायित्व से दखल रहेगा जो माल को रोकने और जांचने के कारण हुआ हो ।

( ६ ) यदि यह बात मालूम हो कि उपधारा ( १ ) के अनुसार दिये हुए हिलाद में वर्णित विवरण माल के विवरण से भिन्न नहीं है,

तो रेलवे प्रबन्धक उक्त माल को मालिक को रोकने और जांचने का व्यय अदा करेगा और उस हानि का जुम्मेदार होगा जिसका ऊपर वर्णन हुआ।

**धारा ५६—(१)** कोई मनुष्य इस बात का अधिकारी न भय प्रद या हानिकर माल / होगा कि वह रेलवे पर अपने साथ भय प्रद या हानि कर माल ले जाय या रेलवे प्रबन्धक से भय प्रद या हानिकर माल ले जाने के लिये कहे।

(२) कोई मनुष्य वैसे माल को रेलवे पर, स्टेशन मास्टर या रेलवे के उत्तरीकरणों, जिलकी निगरानी में कि वह स्थान हो जहां कि वह रेलवे पर माल लाया हो, उस माल के प्रकार की सूचना दिये बिना अपने साथ लाने का अधिकारी न होगा, और न वह इस बात का अधिकारी होगा कि वह उन पैकेजों के बाहर जिनमें कि वह माल हों, उसके प्रकार के सम्बन्ध में बिना स्पष्ट चिन्ह लगाये, या रेलवे के उस नौकर को जिसको कि वह माल पेश करता या देता हो, उस माल के प्रकार की बिना लेख बद्ध सूचना दिये, रेलवे पर लेजाने के लिये पेश करे या दे।

(३) रेलवे का नौकर ऐसे माल को लाने लेजाने के लिये लेने से इन्कार कर सकता है और जब कि वैसे माल उसकी जानकारी में \* [ उपधारा (२) ] में वर्णित सूचना दिये बिना, उक्त प्रकार माल लेलिया गया हो तो उसे अधिकार है कि वह उस माल को लाने लेजाने से इन्कार कर दे या उस माल का भेजना रोक दे।

(४) यदि रेलवे का कोई नौकर इस बात के विश्वास करने का कारण रखता है कि वैसे माल किसी ऐसे पैकेज के भीतर है जिसके भीतर के माल के सम्बन्ध में उसकी जानकारी में, उपधारा (२) में वर्णित सूचना नहीं दी गई है तो उसको अधिकार है कि उस पैकेज को उसके भीतर के माल के निश्चय करने के अभिप्राय के लिये खुलवा डाले।

---

\* शब्द और संख्या " उपधारा (२) " शब्द और संख्या " उपधारा १ " के स्थान में भारतीय रेलवे एक्ट सन १८९० के संशोधन कानून सन १८९६ ( ९ सन १८९६ ) के अनुसार रखे गये।

( ५ ) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ न लिया जायगा जिससे दण्डित एकल प्लाज़िब एक्ट सन १८८४ या उससे अनुसार बना हुआ कोई नियम रद्द हो लगे, और न उपधारा ( १ ) ( ३ ) और ( ४ ) की किसी बात का ऐसा अर्थ लिया जायगा जिससे कि वह उस माल से सम्बन्धित हो लाय जो गवर्नमेन्ट की आज्ञा से या और से लेजाने के लिये पेश किया या दिया गया हो, या जिसको कि कोई अफसर, सैनिक, नाविक या पुलिस अधिकारी, या वह मनुष्य जो भारतीय स्वयं सेवक कानून सन १८६९ ( एक्ट २० सन १८८९ ) के अनुसार भर्ती हुआ हो, अफसर, सैनिक, नाविक, पुलिस अधिकारी या स्वयं सेवक की हैलियत से अपनी नौकरी के कामाने में रेलवे पर अपने साथ लेजाये ।

धारा ६०— प्रत्येक ऐसे स्टेशन पर जिस पर कि रेलवे प्रवर्धन साधारण को वह अधिकार पत्र दिखाना जिसके द्वारा कि लिखे हुए किशारे मारी जाने हैं

अधक ने यात्रियों और उनके असबाब को छोड़ कर अन्य ट्राफिक को लेजाने के लिये,

दूसरे स्टेशन तक का महसूल लिख रखा हो, रेलवे का वह नौकर जो रेलवे प्रबन्धक की ओर से महसूल लिख रखने के लिये नियुक्त हुआ हो, किसी मनुष्य की प्रार्थना पर, तमाम उचित समयों और दिना किसी कीसके लिये, महसूल को वह कितापें या अन्य लेख पत्र दिखलायेगा जिनमें सम्बन्धित प्रबन्धक या प्रबन्धकों ने महसूल का अधिकार दिया हो ।

धारा ६१— ( १ ) जब किसी रेलवे प्रबन्धक द्वारा उस माल धोक तिरागों की तफसील देना हो सम्बन्ध में जो उस की रेलवे प्रबन्धकों पर आवश्यक है

रेलवे पर लेजाया गया हो

कोई रकम मानी जाय और वह उक्त प्रबन्धक को देदी जाय, तो रेलवे प्रबन्धक उस मनुष्य की प्रार्थना पर जिसने या जिसकी ओर से मांगी हुई रकम अदा की गई हो, प्रार्थी को ऐसा हिसाब देगा जिससे वह प्रष्ट हो कि क्या रकम प्रत्येक नीचे की मद में जाती हो, यथा—

( ५ ) रेलवे पर माल का लेजाता,

( ६ ) जालिरी मजिदर के हिसाबे

( ग ) विलम्ब दण्ड ( डेमरेज )

( घ ) संग्रह करने और देने का व्यय और अन्य व्यय ।

परन्तु उन पृथक् २ रकमों का विवरण दिये बिना जो प्रत्येक मद की मांगी हुई रकम में सम्मिलित हों ।

( २ ) उपधारा ( १ ) के अनुसार प्रार्थना पत्र लेख बद्ध होना चाहिये और मांगी हुई रकम प्रार्थी द्वारा या प्रार्थी की ओर से दी जाने की तारीख से एक मास के भीतर रेलवे प्रबन्धक के पास पहुंचना चाहिये और प्रार्थना पत्र के पहुंचने के पश्चात् रेलवे प्रबन्धक द्वारा दिसाव दे दिया जाना चाहिये ।

## यात्रियों का लाना लेजाना

धारा ६२—सकौन्सिल गवर्नर जनरल को अधिकार है कि यात्रियों और रेलवे के उन नौकरों के दरम्यान जिनकी रक्षा में रेल गाड़ी हो सूचना का प्रबन्ध वह रेलवे प्रबन्धक को इस बात की आज्ञा दे कि वह अपनी उस रेल गाड़ी में जिसे वह चलाता हो और जो यात्रियों को लाती ले जाती

हों, यात्रियों और रेलवे के उन नौकरों के दरम्यान जो रेलगाड़ी के रक्षक हों, सूचना के ऐसे समुचित साधन संग्रह करे और उन्हें उचित रीति में स्थिर रखे जिनको सकौन्सिल गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया हो ।

धारा ६३—प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक, सकौन्सिल गवर्नर जनरल प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये यात्रियों की अधिकसे अधिक संख्या की स्वीकृति के आधीन, यात्रियों की ऐसी अधिक से अधिक संख्या निर्धारित करेगा जो प्रत्येक प्रकार की गाड़ी के प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट में लेजाई जासके, और उक्त प्रकार निर्धारित संख्याको प्रत्येक कम्पार्टमेन्टके भीतर या बाहर विशिष्ट रीतिमें अङ्गरेजी में या उनदेशी भाषाओं में से एक वा अधिक भाषाओं में जो उस देश में स्थाधारणतः प्रयोग में आती हों, जिसमें होकर रेलवे निकली हो, या दोनों भाषाओं में अर्थात् अंगरेजी और ऐसी देसी भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं में, जैसा कि सकौन्सिल गवर्नर जनरल, रेलवे प्रबन्धक से परामर्श करने पश्चात्, निश्चय करें, प्रकट करेगा ।

**धारा ६४—(१)** पहिली जनवरी सन् १८९१ को और उस स्त्रीयों के लिये कम्पार्ट के बाद से, प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक को मेन्टो का सुरक्षित रक्षार्थ आवश्यक होगा कि वह उस गाड़ी में जो यात्रियों को लेजाती हो, सब से नीचे के दर्जे की गाड़ी का, जो रेलगाड़ी का भाग हो, कम से कम एक कम्पार्टमेन्ट स्त्रीयों के लिये सुरक्षित रखे।

(२) यदि रेलगाड़ी पचास मील से अधिक दूर जाने वाली हो तो उक्त प्रकार सुरक्षित ऐसे प्रत्येक कम्पार्ट मेन्ट में एक पखाना भी रहेगा।

**धारा ६५—**प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक को आवश्यक होगा कि समय-सूचक और किराया सूचक पत्रों का स्टेशनों पर प्रदर्शन वह अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर ऐसी जगह जो स्पष्ट हो और जहाँ पहुँचा जा सकता हो, अंग्रेजी में और उस देशी भाषा में जो उस प्रदेश में जहाँ कि स्टेशन हो साधारणतः प्रयोग में आती हो, ऐसे समय-सूचक पत्रों की, जो रेलवे पर उस समय जारी हों, एक नकल और उन किरायों के सूची पत्र लटकावें, जो उस स्टेशन से जहाँ कि सूची पत्र लटकाये गये हों, उस स्थान तक यात्रा करने के लिये, जिसे के लिये कि कार्ड टिकिट उक्त स्टेशन पर साधारण यात्रियों को जारी किये जाते हों, मांगे जाने योग्य हों।

**धारा ६६—(१)** प्रत्येक ऐसे मनुष्य को, जो रेलवे यात्रा करने का इच्छुक किराया देने पर हों, अपना किराया देने पर एक टिकिट मिलेगा टिकिटों का दिया जाना जिस में गाड़ी का दर्जा जिसके लिये, और स्थान जहाँ से ठेकर और वह स्थान, जहाँ तक का कि किराया दिया गया हो, और किराये की रकम निरूपित होंगे।

(२) उपधारा (१) के अनुसार आवश्यकीय बातें जो टिकिट पर निरूपित होती चाहिये,

(क) यदि गाड़ी का दर्जा जो उस पर निरूपित होना चाहिये सब से नीचा हो, तो ऐसी देशी भाषा में होगी जो उस प्रदेश में साधारणतः प्रयुक्त होती हो जहाँ हो कर कि रेलवे निबली हो, और

( ख ) यदि गाड़ी का दरजा जो निरूपित होना चाहिये सबसे नीचे दरजे के सिवाय कोई और हो, तो अंगरेजी में होगी।

**धारा ६७—( १ )** किरायों का स्वीकृत होना और टिकटों

उस अवस्था के विषय में आज्ञा	का बंटना इस अवस्था के
जब कि उन रेल गाड़ियों के	आधीन समझा जावगा कि
लिये टिकट बट चुकी हों	रेल गाड़ी में जिसके लिये कि
जिनमें अधिक यात्रियों के	टिकट बंटे हों जगह रहे।
लिये स्थान न हो	

( २ ) जिस मनुष्य को टिकट दिया गया हो और उसको उस रेल गाड़ी में जगह न मिले जिसके लिये टिकट दिया गया हो, तो उक्त रेल गाड़ी के चले जाने के पश्चात् तीन घण्टों के भीतर टिकट वापिस देने पर, वह मनुष्य तुरन्त अपना किराया वापिस पाने का अधिकारी होगा।

[ ३ ] जिस मनुष्य को गाड़ी के उस दरजे में जगह न मिले जिसके लिये कि उसने टिकट मोल लिया हो, और जिसको नीचे दरजे की गाड़ी में यात्रा करनी पड़ी हो तो वह टिकट देने पर इस बात का अधिकारी होगा कि उस महसूल के जो उसने दिया हो और उस महसूल के दरम्यान जो वह उस दरजे के लिये देता जिसमें कि यात्रा की हो, जो अन्तर हो वह उसे वापिस मिले।

**धारा ६८—** कोई मनुष्य, रेलवे के नौकर की अनुमति बिना, पास या टिकट बिना रेलवे की किसी गाड़ी में यात्री रूप से यात्रा करने का निषेध उसमें यात्रा करने के अभिप्राय से, उस समय तक, प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास उचित पास या टिकट न हो।

**धारा ६९—** रेलवे का प्रत्येक यात्री, रेलवे के उस नौकर के पास या टिकटों का मांगने पर जो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक दिखाना और दे देना की ओर से नियुक्त हुआ हो, जांच के रेलवे अपना पास या टिकट उक्त नौकर के तागने पेश करेगा, और उस यात्रा की समाप्ति पर या समाप्ति के लगभग, जिसके लिये कि

पाल या टिकिट जारी हुआ हो, या फसली पाल या टिकिट होने की दशा में, उस लघुधि की समाप्ति पर जब तक कि वह चालू रहे, उक्त पाल या टिकिट को रेलवे के नौकर को दे देगा ।

धारा ७०— वापिसी या मौलगी टिकिट किसी दूसरे मनुष्य वापिसी और मौलगी टिकिट / को नहीं दिया जा सकता और वह केवल उसी मनुष्य द्वारा प्रयुक्त हो सकता है जिसकी उन स्थानों से और उन स्थानों तक यात्रा के लिये जिनका निरूपण टिकिट पर हो, प्रहजारी हो ।

धारा ७१— ( १ ) रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वह ऐसे मनुष्य को लानेवाले जाने से इनकार करने का अधिकार जो साक्रामिक या छूतपाले रोग से ग्रसित हो किसी ऐसे मनुष्य को जो किसी साक्रामिक या छूत वाले रोग से पीड़ित हो लाने लेजाने से इनकार कर दें, सिवाय इसके कि वह उन शर्तों के अनुरूप हो जो धारा ( ४० ) उपधारा ( १ ), खण्ड ( ब ) द्वारा लगाए गए हैं ।

( २ ) जो मनुष्य उक्त किसी रोग से पीड़ित हो, स्टेशन मास्टर या रेलवे के दल नौकर की अनुमति बिना रेलवे पर प्रवेश या यात्रा नहीं कर सकता जिसकी निगरानी में वह स्थान हो जहाँ कि वह रेलवे पर प्रवेश करता हो ।

( ३ ) ऐसी अनुमति के देने वाले रेलवे के नौकर को, जिसका पर्वत कि उपधारा ( २ ) में हुआ है, चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करे कि उक्त रोग से पीड़ित मनुष्य उन अन्य लोगों से पृथक् रहे जो रेलवे पर हो या यात्रा कर रहे हों ।



# सातवां परिच्छेद

## वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धकों का उत्तर दायित्व ।

धारा ७२—रेलवे प्रबन्धक का उत्तर दायित्व, उन पशुओं पशुओं और मालके वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धक के सामान्य उत्तर दायित्व का परिमाण और माल की हानि, नाश या खराबीकेलिये, जो रेलवे प्रबन्धक को रेलवे द्वारा लाने ले जाने के लिये दिये जाय, इस एक्ट की अन्य आज्ञाओं के आधीन, बही होगा जो कानून भारतीय संविद ( मुआहिदा ) सन १८७२ ( एक्ट ९ सन १८७२ ) की धाराएं १५१, १५२ और १६१ के अनुसार चली ( संरक्षक ) का उत्तर दायित्व है ।

( २ ) वह इकरार जो उक्त उत्तर दायित्व का सीमा बद्ध करना प्रकट करता हो, जहाँ तक उससे उक्त सीमा—बद्धता पर प्रभाव पड़ता हो, उस समय तक अनुचित होगा, जब तक कि—

[ क ] वह लेख बद्ध न हो और उस पर उस मनुष्य के या उस मनुष्य की ओर से हस्ताक्षर न हों जो रेलवे प्रबन्धक को पशु या माल भेजता हो या देता हो, और

[ ख ] वह अन्यथा उस नमूने \* में न हो जो सक्कौन्सिल गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया है ।

[ ३ ] इंग्लैंड के साधारण कानून और कानून बाहक सन १८६५ ( एक्ट ३ सन १८६५ ) की कोई बात, जो पशुओं या माल के लाने ले जाने के संबन्धमें सामान्य वाहकों के उत्तर दायित्व के विषय में है, रेलवे प्रबन्धक के उस उत्तर दायित्व पर प्रभाव न डालेगी जिस की परिभाषा इस धारा में हुई है ।

---

\* रिज़र्व नोट कार्यों के लिये जो इसधारा द्वारा नियत हुए देखिये जनरल स्टैट्यूट आर एण्ड ओ, जिल्द ८, पृष्ठ १४९२, और भारतीय गजट १९०७, भाग १, पृष्ठ १८०, और १९०९, भाग १ पृष्ठ २३२ ।

धारा ७३—[१] पूर्वोक्त अन्तिम धाराके अनुसार रेलवेप्रबन्धक पशुओं के वाहक रूप से रेलवे का वह उत्तर दायित्व जो उन प्रबन्धक की जुम्मेदारी के पशुओं के हानि, नाश या खराब सम्बन्ध में अनिरिक्त आया होने के सम्बन्ध में हो जो उक्त प्रबन्धक को रेलवे पर लाने लेजाने के लिये दिये जाय उस समय तक किसी दशा में, हाथियों या घोड़ों की अवस्था में, ५००) पशु से अधिक न होगा, और या (खिच्छरों) ×, ऊंटों या लौंगदार पशुओं की अवस्था में, ५०) पशु से अधिक न होगा, या (गधों) × भेड़, बकरियों, कुत्ते या अन्य जानवरों की अवस्था में, १०) जानवर से अधिक न होगा, जब तक कि वह गनुष्य जो उक्त प्रबन्धक को जानवर भेजता या देता हो, रेलवे द्वारा लाने लेजाने के लिये देते समय, वह प्रकट न करावे या न करवे कि उक्त पशु क्रमशः पाँच ली रुपये, पच्चास रुपये या दस रुपये पशु से, जैसी कि अवस्था हो, अधिक मूल्य के हैं।

( २ ) जब कि उक्त अधिक मूल्य प्रकट किया गया हो तो रेलवे प्रबन्धक को अधिकार है कि वही हुई जोखिम के सम्बन्ध में, उस मूल्य के अधिक भाग पर जो पूर्वोक्त पृष्ठ २ रकमों के ऊपर उक्त प्रकार प्रकट की गई हो, प्रति सैकड़ा कुछ महसूल मांगे।

( ३ ) रेलवे प्रबन्धक के प्रतिकूल ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जो किसी पशु की हानि, नाश, खराबी के कारण हरजे के वसूल करने के लिये हो, जानवर के मूल्य के प्रमाणित करने का भार, और, जब कि जानवर को पूर्ण क्षति पहुँची हो तो क्षति का परिमाण प्रमाणित करने का भार हरजे के दावेदार गनुष्य पर होगा।

धारा ७४— किसी ऐसे सख्तवाह की हानि, नाश या खराबी या चोटों के अलगाव लेजाने के लिये, जो किसी यात्री का वाहकी एलियत से रेलवे प्रबन्धक की जुम्मेदारी की सम्बन्ध में अनिरिक्त आया हो या जो किसी यात्री की निगरानी में हो, रेलवे प्रबन्धक उस समय तक जुम्मेदार न

× गवर्न लिच्छर" और गधों" भारतीय रेलवे कानून १८९० के संशोधन कानून एन १८९६ ( एक्ट ९ एन १८९६ ) की धारा ४ द्वारा पढ़ाव गये।

होगा जब तक कि रेलवे के नौकर ने उक्त असबाब को अपने रजिस्टर में लिखकर उसकी रसीद न देदी हो।

**धारा ७५— ( १ )** जब कि ऐसी वस्तुएं जिनका दूसरे विशेष मूल्य की वस्तुओं के शैड्यूल में वर्णन है किसी वाहक रूप से रेलवे प्रबन्धक पारसल या पैकेज में बन्द की ज़ुम्मेदारी के सम्बन्ध में करके रेलवे द्वारा लेजानेकेलिये अनिश्चित आज्ञा किसी रेलवे प्रबन्धकके द्वारा

मूल्य, जो पारसल या पैकेज में हो, सौ रुपये से अधिक हो, तो रेलवे प्रबन्धक पारसल या पैकेज के क्षति होने, नष्ट होने या बिगड़ने का ज़ुम्मेदार न होगा सिवाय उस सूरत के कि उस मनुष्य ने जिसने उस पारसल या पैकेज को उक्त प्रबन्धक की भेजा या हवाला किया हो, रेलवे द्वारा भेजे जाने के लिये पारसल या पैकेज के देने के समय, उसके मूल्य और उसके अन्दर की वस्तुओं का स्पष्टीकरण किया या कराया हो, और रेलवे प्रबन्धक द्वारा आज्ञा देने की दशा में, उक्त स्पष्ट की हुई मालियत पर बढ़ती हुई ज़ुम्मेदारी के सम्बन्ध में हरजे के तोर पर सैकड़ों के हिसाब से कुछ दिया या देने का इकरार किया हो।

[ २ ] जब कोई ऐसा पारसल या पैकेज जिसकी मालियत का स्पष्टीकरण उपधारा [ १ ] के अनुसार हुआ हो, खो गया, नष्ट हो गया या खराब हो गया हो, तो उक्त क्षति, नष्ट होने या खराब होने के सम्बन्ध में बसूल होने योग्य हरजा उक्त प्रकार स्पष्ट की हुई मालियत से न बढ़ेगा और उक्त प्रकार स्पष्ट की हुई मालियत के प्रमाण करने का भार, ठीक मालियत होने के लिये, उस मनुष्य पर होगा जो दावा करता हो, इस बात के होते हुये भी कि स्पष्टीकरण (Declaration) में कुछ ही लिखा हो।

(३) रेलवे प्रबन्धकको अधिकार है कि वह किसी ऐसे पारसल के लेजाने के सम्बन्ध में जिस में दूसरे शैड्यूल में वर्णित वस्तु के रहने का स्पष्टीकरण किया जाय, यह शर्त लगा दे कि कोई रेलवे मुलाजिम जिस को इस सम्बन्ध में अधिकार दिया जाय, जांच या अन्य प्रकार से इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाय कि उक्त पारसल में वास्तव में वही चीज़ है जिस के रहने का उस में स्पष्टीकरण किया है।

धारा ७६— रेलवे प्रबन्धक के विरुद्ध किसी ऐसी नालिश में

<p>उन नालिशों का प्रमाण भार जो पशुओं या माल की हानि के सम्बन्ध में हो</p>	<p>जो उन पशुओं या माल के क्षति होने नष्ट होने या खराब होने के कारण हरजे के सम्बन्ध में किया जाय, जो</p>
---	---

रेलवे द्वारा लेजाये जाने के लिये रेलवे प्रबन्धक को हवाला किये जाय, मुद्दे के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह यह प्रमाणित करे कि क्षति, विनाश या खराबी क्यों कर हुई।

धारा ७७— कोई मनुष्य इस बात का अधिकारी न होगा कि

<p>अधिक किरायों की वापिसी और हानि के हरजे के सम्बन्ध में दावों की विवक्षित</p>	<p>उस को उन पशुओं या माल के सम्बन्ध में जो रेलवे द्वारा लेजाये गये हों, अधिक किराये की वापिसी</p>
--	---

मिले या उन पशुओं या माल के गुम होने नष्ट होने या खराब होने के कारण, जो एक प्रकार लेजाये जाने के लिये हवाला किये जाय, हरजे का अधिकारी होगा सिवाय उस दूरत के कि उक्त वापिसी या हरजे के सम्बन्ध का उसका दावा उस ने या उस की ओर से रेलवे द्वारा पशुओं या माल के लेजाये जाने के लिये हवाला करने की तारीख से छे मास के भीतर रेलवे प्रबन्धक के सामने लेख बद्ध पेश किया या पेश किया गया हो।

धारा ७८— इस परिच्छेद की पूर्वोक्त आज्ञाओं में चाहे जो

<p>वस एतत्त में जुम्मेदारी से बचाप जब कि माल का विवरण गूँठा दिया गया हो</p>	<p>कुछ क्यों न लिखा हो, रेलवे प्रबन्धक ऐसे माल के खो जाने नष्ट होने या खराब होने के लिये जुम्मेदार न</p>
---	--

होना जिस के विवरण के सम्बन्ध में धारा ५८ की उपधारा (१) के अनुसार बारम्बार गूँठा दिया गया हो, यदि उक्त क्षति, विनाश या खराबी किसी तरीके से झूठे हिसाब के कारण हुई हो और न किसी दशा में माल की मालियत से बटी हुई रकम के लिये जुम्मेदार होना, यदि उक्त मालियत झूठे हिसाब में दिये हुए विवरण के अनुसार लगाई गई हो।

**धारा ७९—** जब कि कोई अफसर, सिपाही या अनुयायी, उस

<p>उन हानियों के सम्बन्ध में हरजे का चुकाना जो उन अफसरों, सिपाहियों और भीड़ को पहुंची हो जो काम पर हों</p>	<p>समय जब कि वह अपनी उक्त हैसियत से काम पर ऐसी रेलवे में हो या सफर कर रहा हो जो गवर्नमेंट की हो और गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हो, ऐसी दशाओं में अपना प्राण खोवे या</p>
--	--

शारीरिक हानि उठावे कि यदि वह जैसा अफसर, सिपाही या अनुयायी, न होता जो अपनी उक्त हैसियत से अपने काम पर उक्त रेलवे में हो या सफर कर रहा हो तो हरजा पक्क १३ सन १८५५ के अनुसार देय होता या उस को दिलाया जाता, जैसी कि दशा होती, तो उस हरजे का तरीका और परिमाण जो उस को उस जान जाने और हानि उठाने के सम्बन्ध में दिलाया जायगा, उस हाल में जब कि उन सैनिक नियमों में इस सम्बन्ध में कोई आज्ञा हो जिन सैनिक नियमों का वह कि अपने मरने से पहिले आधीन था या अब तक है, उन्हीं नियमों के अनुसार, न कि किसी और तरह पर, निश्चय किया जायगा।

**धारा ८०—** चाहे ऐसे इस्तेमाल में कुछ भी क्यों न हो जिस से

<p>उस हानि के सम्बन्ध की नालिशें जो थू लुक्कड ट्राफिक को पहुंची हो</p>	<p>किसी रेलवे प्रबन्धक की जुम्मेदारी का, विशेषतः ट्राफिक</p>
--	--

के सम्बन्ध में जब कि वह किसी और प्रबन्धक की रेलवे पर हो, परिमित होना प्रकट होता हो, किसी मुसाफिर की प्राणहानि या शारीरिक हानि के हरजे की नालिश या पशुओं या माल के खोने, नष्ट होने या खराब होने की नालिश, उस दशा में जब कि उक्त मुसाफिर या पशु या माल दो या अधिक रेलवे प्रबन्धकों की रेलवेयों पर से जाने के लिये रजिस्टर में दर्ज हुए हों, चाहे उस रेलवे प्रबन्धक के नाम जिससे मुसाफिर ने अपना पास प्राप्त किया या टिकट खरीद किया था या जिस को वह पशु या माल उन के भेजने वाले ने हवाला किया थे, या उस रेलवे प्रबन्धक के नाम, जैसी कि दशा हो, दाहर की जा सकती है जिन की रेलवे पर क्षति, बिनाश या खराबी, या हानि हुई हो।

धारा ८१— भारतीय रेलवेज के कानून सन १८९० के संशो-  
 देशी जलों पर ऐसे जहाज द्वारा धन कानून सन १८९६ ( एक्ट  
 जो रेलवे का भाग न हो ट्राफिक ९ सन १८९६ ) की धारा ५ के  
 के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक की अनुसार मसूख ।  
जुम्मेदारी का परिमित होना

धारा ८२— ( १ ) जब कि कोई रेलवे प्रबन्धक मुसाफिरों  
 समुद्र की दुर्घटनाओं के या जानवरों या मालों को कुछ दूर  
 सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक तक रेलवे के द्वारा और कुछ दूर तक  
 की जम्मेदारी की सीमाद समुद्र के मार्ग से लेजाने का इकरार  
 करते तो एक ऐसी शर्त जिससे रेलवे प्रबन्धक किसी प्राण हानि या  
 शारीरिक कष्ट या जानवरों या मालों की हानि या हरजे की जुम्मे-  
 दारी से जो समुद्र के मार्ग से लेजाने के मध्य में, ईश्वर की इच्छा  
 से और राजा के वैरियों के हाथ से और आग से और कलों और  
 देव और भुपे की दुर्घटनाओं के कारण हों, और जिससे समुद्र और  
 दरिया और जहाज चलाने के समस्त और प्रत्येक अन्य आशङ्काओं  
 और दुर्घटनाओं की, चाहे वह किसी तरह और प्रकार के क्यों न  
 हों, जुम्मेदारी से मुक्त होजाय एषट वर्णन न होने पर भी इकरार  
 का एक अंश समझाजायगी और उपर्युक्त शर्तों के आधीन, रेलवे प्रब-  
 ण्धक, रिलायिदास एत बात के दि वह जहाज जो समुद्र में लाने  
 लेजाने के काम में आता हो जिस दाति का है या उसका मालिक  
 होन है, प्रत्येक ऐसी प्राण हानि या शारीरिक हानि या जानवरों  
 या मालों की दाति या हरजे का जो समुद्र के मार्ग से लेजाने के  
 मध्य में हो. उसी एत तक जुम्मेदार होना जिस इद तक वह  
 मर्चेंट शिपिंग एक्ट सन १८५४ और मर्चेंट शिपिंग एक्ट के संशो-  
 धन कानून सन १८६२ के धनसार जुम्मेदार होना यदि उक्त जहाज  
 उन दागनों में से पड़िते कानूनों के अनुसार रजिस्टरी किया हुआ  
 होता और रेलवे प्रबन्धक उक्त जहाज का माटिक होता परन्तु उस  
 एद से अधिक नहीं ।

( २ ) एत बात के प्रमाण करने का भार कि वैसी कोई हानि  
 या या हरजा जिससे सम्बन्ध में, उपधारा ( १ ) में वर्णन है समुद्र  
 के मार्ग से लेजाने के मध्य में हुआ है. रेलवे प्रबन्धक पर होगा ।

# आठवां परिच्छेद

## दुर्घटनाएं

धारा ८३—जब रेलवे के चलाने के मध्य में निम्न लिखित रेलवे की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट / दुर्घटनाओं में से कोई दुर्घटना हो, अर्थात:—

- ( क ) कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें मनुष्य के प्राण की हानि, ऐसी सख्त चोट जिसकी परिभाषा भारतीय दण्ड संग्रह में की गई है वा सम्पत्ति का सख्त नुकसान हो ।
- ( ख ) ऐसी ट्रेनों का टकरा जाना जिनमें से एक ऐसी ट्रेन हो जो मुसाफिरों को लाती या लेजाती हो ।
- ( ग ) किसी ऐसी ट्रेन का जो मुसाफिरों को लाती लेजाती हो, या उसके किसी भाग का, रेल की पटरी से उतर जाना ।
- [ घ ] इस प्रकार की दुर्घटना जिसमें सामान्यतः मनुष्य-प्राण की हानि, या सख्त चोट जिसका कि ऊपर वर्णन किया गया है या सम्पत्ति का सख्त नुकसान हो,
- [ ङ ] किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना जिसे सपरिपद गवर्नर जनरल इस सम्बन्ध में भारतीय गजट में विज्ञापित करे;

तो रेलवे प्रबन्धक जो रेलवे को चलाता हो, और यदि दुर्घटना ऐसी ट्रेन के सम्बन्ध में हो जो किसी अन्य रेलवे प्रबन्धक की हो तो दूसरा रेलवे प्रबन्धक भी, अनावश्यक्रीय विलम्ब बिना, उस दुर्घटना की सूचना स्थानीय गवर्नमेन्ट और रेलवे के लिये नियुक्त इन्सपेक्टर को देगा । और वह स्टेशन मास्टर जो उस स्थान के करीब तर हों जहां कि दुर्घटना हुई हो, या जहां कि स्टेशन मास्टर न हो, तो वह रेलवे का मुलाजिम जो उस रेलवे के भाग का इन्चार्ज हो जिस पर कि दुर्घटना हुई हो, अनावश्यक्रीय विलम्ब बिना, उक्त दुर्घटना की सूचना उस जिले के मजिस्ट्रेट को देगा जिसमें कि दुर्घटना हुई हो, और उस अफसर को सूचना देगा जिसकी निगरानी में वह पुलिस स्टेशन हो जिसकी स्थानीय सीमाओं के

अन्तरगत दुर्घटना हो, या उस अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर को जिसे कि सपरिषद् गवर्नर जनरल इस सम्बन्ध में नियुक्त करें।

धारा ८५— सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह दुर्घटनाओं की सूचना और तद्वशीकृत के सम्बन्ध में तद्वशीकृत के सम्बन्ध में निम्न बनाने का अधिकार उस समय प्रचलित हो, निम्न लिखित कुछ या किसी प्रयोजन के लिये नियम बनावे, अर्थात्:—

[ क ] उन सूचनाओं के नमूने नियत करने के लिये जिनका वर्णन ऊपर की अन्तिम धारा में हुआ है, और दुर्घटना की उन तफ़्तीलों के विषय में जो उक्त सूचनाओं में होंगी।

[ ख ] दुर्घटनाओं की किसी नियत करने के लिये जिसकी सूचना कि तार द्वारा दुर्घटना होने के पश्चात् तुरत ही भेजी जायगी।

[ ग ] रेलवे मुलाजिम, पुलिस अधिकारियों इन्स्पेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के, दुर्घटना होने पर, कर्तव्य निर्धारित करने के लिये।

धारा ८५— प्रत्येक रेलवे प्रबन्धक सपरिषद् गवर्नर जनरल को दुर्घटनाओं का नदशा अपनी रेलवे पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिये नदशा, चाहे उससे कोई शारीरिक हानि हो अथवा न हो, ऐसे नमूने, तरीके, और समयों पर भेजेगा जैसी कि सपरिषद् गवर्नर जनरल आज्ञा दें।

धारा ८६— जब कि कोई ऐसा मनुष्य जिसकी रेलवे की दुर्घटना के कारण हानि हुई हो, मनुष्य की अनिवार्य डाक्टरों की परीक्षा के विषय में आज्ञा करे, तो कोई अदालत या वह

मनुष्य जिसका दानून के अनुसार याफरीकैन की सम्मति से, उक्त दावा होने पर दावा अधिकार प्राप्त हो, वह आज्ञा दे सकता है कि हानि प्राप्त मनुष्य की किसी ऐसे सनद याफना डाक्टर द्वारा परीक्षा हो जिसका नाम कि आज्ञा में हो और जो किसी पक्ष का सहायक न हो, और परीक्षा के विषय के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती या दे सकता है जैसी कि उक्त अदालत या मनुष्य उचित समझे।



# नवां परिच्छेद

## दण्ड और अपराध

### रेलवे कम्पनियों के दण्ड

**धारा ८७—** यदि कोई रेलवे कम्पनी किसी ऐसी आज्ञा के धारा १३ की आज्ञा उलंघन के कारण दण्ड | अनुसार कार्य न करे जो धारा १३ के अनुसार दी गई हो, तो उस उक्त आज्ञा के उलंघन के कारण दो सौ रुपये गवर्नमेन्ट को तावान की तरह देने पड़ेंगे और पहिले दिन के पश्चात् हर रोज पचास रुपये जब तक कि आज्ञा उलंघन होती रहे, अतिरिक्त तावान के रूप में देने पड़ेंगे।

**धारा ८८—** यदि कोई रेलवे कम्पनी, धारा १६ उपधारा ( २ ) धारा १६, १८, १९, २०, २१ या २४ की प्रतिकूलता के कारण दण्ड | के प्रति कूल किसी रेलवे पर धूप या अन्य संचालक शक्ति द्वारा कोई गोल पहिये वाली चीज चलाये, या धारा १८, धारा १९, धारा २०, या धारा २१ के प्रति कूल किसी रेलवे को खोले या काम में लावे या काम करे या धारा २४ के प्रति कूल किसी रेलवे को पुनः खोले या गोल पहिये वाली चीज को काम में लावे, तो दो सौ रुपये प्रति दिन तावान के रूप में गवर्न मेन्ट को उसे उस समय तक देने पड़ेंगे जब तक कि संचालक शक्ति, काम, गोल पहिये वाली चीज उक्त किसी धारा के प्रति कूल काम में आती रहे।

**धारा ८९—** यदि कोई रेलवे कम्पनी उन रजिस्टरों या लेख धारा ४७, ५४ या ६५ के अनुसार स्टेशनों पर कुल लेख-पत्र न रखने या प्रदर्शन न करने के कारण दण्ड | पत्रों के सम्बन्ध में, जिन का उस के रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षण के लिये रखा जाना या विशिष्ट रूप से चिपकाया जाना आवश्यक है, धारा ४७ की उपधारा ( ६ ), धारा ५४ की उपधारा ( २ ) या धारा ६५ की आज्ञाओं के अनुकूल काम न करे, तो उसे आज्ञा उलंघन के कारण उस समय तक गवर्नमेन्ट को

पञ्चासुरगण प्रति दिन तावान के रूप में दैते पड़ेंगे जबतक कि आशा टलेंघन होती रहे।

धारा ९८— यदि कोई रेलवे कम्पनी, सामान्य नियमों के धारा ८७ द्वारा आवश्यक बनाने के समर्थ में, धारा ४७ की शर्तों के तहत बनाने के लिए आवश्यक काम न करे, तो उसे गवर्नमेन्ट की इस सलाह तक पचास रुपये प्रति दिन तादात के रूप में देने पड़ेंगे जब तक कि कामा उल्लंघन होता रहे।

धारा ९१— यदि कोई रेलवे कम्पनी, धारा ४८ के अनुसार धारा ४८ के अनुसार निर्णय— किये गये उपरिपद गवर्नर जनरल या अन्य न करके जे फाइनल बण्ड के किसी निर्णय के अनुसार लाय करने से इफ्तदार करे या अस्वाध्यायी रहे, तो उसे दोसरी रुपये प्रति दिन उस समय तक गवर्नमेन्ट को ताजान के रुपये देने पड़ेंगे जब तक कि इफ्तदार या अस्वाध्यायी होती रहे।

धारा ६२— यदि कोई रेलवे कम्पनी किसी नक़्शे के भेज़ने धारा ५२ या ८५ के अनुसार | दो सप्ताह में धारा ५२ या ८५ तत्त्वों के भेज़ने में विलम्ब की शिकायतों के अतक़ूब काम न करे, तो उसे पचास रुपये प्रति दिन एक सप्ताह तक नफ़ातिफ़ दो। ताज़ान के रूप में देने पर होने जब तक कि एक दिन से पन्द्रह दिन के पश्चात धारा उलंघन होती रहे और दिन दिन नक़्शे के भेज़ने के लिये नियत हो।

[illegible]

के सम्बन्ध में प्रतिकूलता करे, या जान बूझ कर किसी ऐसे मनुष्य को जो किसी ऐसी माल गाड़ी या खुली गाड़ी का मालिक हो जो उसकी रेलवे पर होकर जाती हो, उक्त धाराओं में से पहिली धारा की आज्ञाओं की प्रतिकूलता करे, तो उसे उस समय तक बीस रुपये प्रति दिन गवर्नमेन्ट को तावान के रूप में देने पड़ेंगे जब तक कि दोनों धाराओं में से किसी धारा की प्रतिकूलता होती रहे।

**धारा ९४—** यदि कोई रेलवे कम्पनी सपरिषद् गवर्नर जनरल यात्रियों और रेलवे के नौकरों की किसी ऐसी आज्ञा के बीच में सूचक-सामग्री स्थित रखने के लिये धारा ६२ की आज्ञा पालन न करने के कारण दण्ड

की किसी ऐसी आज्ञा के पालन में, जो धारा ६२ के अनुसार किसी ऐसी ट्रेन में जिसे वह चलाती हो और जो मुद्दा-फिरों को लेजाती हो, खबर

पहुँचाने के ऐसे पर्याप्त साधनों के संग्रह करने और उचित प्रबन्ध के साथ कायम रखने के सम्बन्ध में कसूर करे, जिनको सपरिषद् गवर्नर जनरल ने पसन्द कर लिया हो, तो उसे हर ऐसी ट्रेन के लिये जो उक्त आज्ञा के प्रतिकूल चले, बीस रुपये तावान के रूप में गवर्नमेन्ट को देने पड़ेंगे।

**धारा ९५—** यदि कोई रेलवे कम्पनी स्त्रियों के लिये रक्षित धारा ६४ के अनुसार स्त्रियों के लिये रक्षित कम्पार्टमेन्ट न रखने के कारण दण्ड

( Reserved ) कमरे रखने के सम्बन्ध में या उनमें पाखानों का प्रबन्ध रखने के सम्बन्ध में,

धारा ६४ की आज्ञाओं के प्रतिकूल काम करे, तो उसे हर ऐसी ट्रेन के लिये जिसके सम्बन्ध में कि आज्ञा उलंघन होती रहे, गवर्नमेन्ट को बीस रुपये तावान के रूप में देने पड़ेंगे।

**धारा ९६—** यदि कोई रेलवे कम्पनी धारा ८३ और उक्त धारा ८३ और धारा ८४ के अनुसार आवश्यक दुर्घटनाओं की सूचना न देने के कारण दण्ड

नियमों के अनुसार जो धारा ८४ के अनुसार उस समय प्रचलित हों, आवश्यक, किसी दुर्घ-

टना की सूचना देने में कुसूर करे, तो उसे उस समय तक जब तक कि उक्त कुसूर होता रहे, गवर्नमेन्ट को सौ रुपये प्रति दिन तावान के रूप में देने पड़ेंगे।

धारा ६७—[ १ ] जब किसी रेलवे कम्पनी पर, इस परिच्छेद दण्ड—धन का बखूल की ऊपर कही गई आज्ञाओं के अनुसार किया जाना किसी कार्य वा चूक के कारण, गवर्नमेन्ट को किसी रकम के देने का दण्ड हुआ हो, तो रकम उस जिला कोर्ट में नालिश द्वारा बखूल की जा सकती है जिसके विचार अधिकार [ Jurisdiction ] के भीतर वह स्थान हो जहां कि उक्त कार्य वा चूक हो।

[ २ ] उक्त नालिश सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त कर दाखर की जानी चाहिये और उक्त नालिश में वादी [ मुद्दा ] सपरिषद् भारत सचिब होंगे।

३] सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह किसी ऐसी रकम को, कुल वा उसका कोई भाग, माफ़ करदे, जिसके गवर्नमेन्ट को दिये जाने का इस परिच्छेद की उपर्युक्त आज्ञाओं के अनुसार दण्ड हुआ हो।

धारा ६८—उपर्युक्त आज्ञाओं की किसी बात का ऐसा अर्थ इस परिच्छेद की पूर्वोक्त आज्ञाओं में न लिया जायगा जिस से कि जो चारा शर, दंडों की या पूर्ति गवर्नमेन्ट किसी रेलवे कम्पनी पर स्थिति में हो उस कर्त्तव्य को सम्मान करदे दो सम्बन्ध में, जो इस एक्ट द्वारा उस पर लगाया गया हो, विवश करने दो अभिप्राय हो लिये, उक्त नालिश के धागे वा साथ २, तिरका दर्ज कि उपर्युक्त कर्त्तव्य धारा में हुआ है कार्यवाही का कोई और तरीका काम में लाने से बाध रहेगी।

## रेलवे के नौकरों द्वारा अपराध

धारा ६९—यदि कोई रेलवे का नौकर, जिसका कर्त्तव्य धारा ६० धारा ६० द्वारा लगाये कर्त्तव्य की आज्ञाओं का पालन करना [ उपरी ] का पालन न करेगा हो, अज्ञाबिधानता से या जान बूझकर आज्ञाओं के पालन करने में दुस्तर करने को देने देवे जुमाने वा दण्ड दिया जायगा जिसकी संहिता मौखिक रूप से दी सकती है।

**धारा १००—** जब कोई रेलवे का नौकर, जब कि वह अपने नशा में होना / काम [ Duty ] पर हो, नशे की दशा में हो, तो उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, या जहां कि उसके कर्तव्य की अनुचित सम्पत्तिता से किसी ऐसे मनुष्य की, जो रेलवे पर सफर कर रहा हो या रेलवे पर हो, रक्षा आशंकित हो जाने की सम्भावना हो, तो ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुरमाने का दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायंगे।

**धारा १०१—** यदि कोई रेलवे का नौकर जब कि वह अपने मनुष्यों की सलामती / काम पर हों, किसी निम्न लिखित कार्य संशय में डालना द्वारा किसी मनुष्य की सलामती संशय में डाले—

[ क ] किसी ऐसे सामान्य नियम के उलंघन द्वारा, जो इस एक्ट के अनुसार बना हो स्वीकृति हुआ हो, प्रकाशित हुआ हो, और विज्ञापित हुआ हो। या,

[ ख ] किसी ऐसे नियम या आज्ञा के उलंघन द्वारा जो एक नियम के प्रतिष्ठुल न हो, और जिसका पालन करना उक्त नौकर पर उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो, और जिसकी उसे सूचना हो, या

[ ग ] किसी शीघ्रता या असावधानता के कार्य या खूब द्वारा, उसे ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है या ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या पांच सौ रुपये तक हो सकती है या दोनों दण्ड दिये जायंगे।

**धारा १०२—** यदि कोई रेलवे का नौकर किसी मुसाफिर यात्रियों को उन दरजों में / को ऐसे दरजे में प्रवेश करने के प्रवेश करने के लिये विवश करना जो पहिले ही से चेष्टा करे, या प्रवेश करीये, जिसमें भरे हों। मुसाफिरों की वह अधिक से अधिक संख्या पहिले से हो जो धारा ६३ के अनुसार उक्त दर्जे पर

या उस दंड में प्रदर्शित की गई हो, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

धारा १०३— यदि कोई स्टेशन मास्टर या रेलवे का यह दुर्घटना की सूचना न देना | नौकर किसी निगरानी में रेलवे का एक भाग हो, किसी दुर्घटना की ऐसी सूचना

देने में विलंब करे, जो धारा ८३ और उन नियमों के अनुसार आवश्यक है जो धारा ८४ के अनुसार उस समय प्रचलित हों, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

धारा १०४— जब कोई रेलवे का नौकर अनावश्यक ट्रेनिंग कालिंग योजना | रूप से,—

[ क ] किसी एडिटेड पाली चीज़ को उस जगह के शान्त पार ठहरने के जहां कि रेलवे किसी सरकारी सड़क की सतह पर आग पार गुजरनी हो, या

[ ए ] किसी ट्रेनिंग कालिंग में सूर्य साधारण का आना जाना पड़े रहे।

उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

धारा १०५— यदि कोई गणना जो इस पद के अनुसार सूचे जाय | आवश्यक हो किसी तयारी में उस मनुष्य की जान कापी म. सुधारी, जो उस न. के पर दण्ड उतार दे, उस मनुष्य को ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या ५०० रुपये तक हो सकती है, या ऐसी दंड का दण्ड दिया जायगा जिसकी अधिकतम पर वर्ष तक की हो सकती है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

## अन्य अपराध

**धारा १०६—** यदि किसी मनुष्य से, भाग ५८ के अनुसार माल का गुंठा हिसाब देना / किसी माल के सम्बन्ध में कोई हिसाब पेश करने के लिये कहा जाय, जो वास्तव में गुंठा हो, तो उसे, और यदि वह उक्त माल का मालिक नहीं है तो उसके मालिक की भी, ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या माल के प्रत्येक मन या उस के भाग के लिये दस रुपये तक हो सकती है, और उक्त जुर्माना उस गुरह या अन्य महसूल के अतिरिक्त होगा जिस का कि माल जुम्मेदार हो।

**धारा १०७—** यदि धारा ५९ के प्रति कूल कोई मनुष्य रेलवे पर अनुचित रूप से भयानक / अपने साथ रेलवे पर कोई या हानि कर माल लाना / भयानक या हानिकर माल लावे, या रेलवे पर लेजाने के लिये कोई ऐसा माल पेश करे या दे, उस को ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या पांच सौ रुपये तक हो सकती है और वह किसी ऐसी क्षति, हानि या खराबी के लिये भी जुम्मेदार होगा जो उक्त माल के रेलवे पर उक्त प्रकार से लाये जाने के कारण हो।

**धारा १०८—** यदि कोई मुसाफिर, बिना उचित और ट्रेन गाड़ी में सूचक-सामग्री / पर्याप्त कारण के, उस सामग्री में अनावश्यकतः हस्तक्षेप करना / का प्रयोग करे या उस सामग्री में हस्तक्षेप करे, जो किसी रेलवे प्रबन्धक ने मुसाफिरों और उन रेलवे के नौकरों के दरम्यान खबर पहुंचाने के लिये संग्रहीत की हो जिन की निगरानी में कि ट्रेन गाड़ी हो, उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

**धारा १०९—** [ १ ] यदि कोई मुसाफिर किसी ऐसे दरजे में रिजर्व्ड या पहिले से भरे कम्पार्टमेंट / प्रविष्ट [ दाखिल ] होकर, न प्रवेश करना या न भरे एण्ड कम्पार्टमेंट में प्रवेश करने से रोकना / तो रेलवे प्रबन्धक द्वारा अन्य मुसाफिर के काम में आने के लिये रक्षित हो, या जिसमें मुसाफिरों की वह अधिक से

अधिक संख्या पहिले से मौजूद हो जो उस दरजे में या दरजे के ऊपर धारा ६३ के अनुसार प्रदर्शित की गई हो, उस समय जब कि उससे किसी रेलवे के नौकर द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाय, उक्त दरजे के छोड़ने से इन्कार करे, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

[ २ ] यदि कोई मुलाफिर दूसरे मुलाफिर के उचित प्रवेश को किसी ऐसे दरजे में रोके जो रेलवे प्रबंधक द्वारा रोकने वाली मुलाफिर के लिये रक्षित [ Reserved ] न हो या जिसमें मुलाफिरों की वह अधिक से अधिक संख्या पहिले से न हो, तो उस दरजे में या दरजे के ऊपर धारा ६३ के अनुसार प्रदर्शित की जावे, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

धारा ११०—[ १ ] यदि कोई मनुष्य, उली दरजे के अपने तम्बाकू पीना / पायी मुलाफिरों [ यदि कोई हो ] की रजामन्दी देना, किसी दरजे में तम्बाकू पीने जो उस दरजे के अतिरिक्त हो जो उक्त अधिप्राण के निम्ने विधिपर रूप में संग्रह किया गया हो, उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

[ २ ] यदि कोई मनुष्य किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा न पीने के लिये आगाह किया जाने परन्तु, उक्त प्रकार तम्बाकू पीता रहे, तो अध्याय [ १ ] में वर्णित जुर्मोदारी उठाने के अतिरिक्त किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा वह उस गाड़ी से निकाला जा सकता है जिसमें कि वह सफ़र कर रहा हो।

धारा १११—यदि कोई मनुष्य, इस अधिनियम में अनुमति तारीफ़ निकालना पक्षों / देना, किसी ऐसे तम्बे या कागज को बा बिगाड़ना / उतार लाते या जान दूत कर मुक़दमा पहुँचावे जो रेलवे प्रबंधक की आज्ञा से रेलवे पर या किसी गोष्ठ पहिले वाली सीढ़ पर चढ़ाया या लगाया गया हो, या किसी एक रुपये का कागज के किसी छहर या छद्म को मिटावे या बदले, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।



**धारा ११२** — यदि कोई मनुष्य, रेलवे प्रबन्धक को धोका  
 उचित पास या टिकिट बिना देने की नीयत से—  
 चलतः यात्रा करना या यात्रा  
 करने का प्रयत्न करना

[ क ] रेलवे की किसी गाड़ी में धारा ६८ के प्रतिकूल प्रवेश  
 करे, या

( ख ) किसी ऐसे सिग्नल पास या टिकिट को जो किसी पूर्व यात्री  
 में पहिले प्रयुक्त हो चुका हो, या चापिली टिकिट की दशा  
 में, उसके अर्द्ध भाग को, जो उक्त प्रकार पहिले प्रयुक्त हो  
 चुका हो, काम में लावे या काम में लाने की चेष्टा करे,

तो उसे उस फासले के लिये इकहरे किराये के अतिरिक्त जो  
 उस ने सफर किया हो, ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा  
 जिसकी संख्या सौरूपये तक हो सकती है।

**धारा ११३** — ( १ ) यदि कोई मुसाफिर किसी ट्रेन गाड़ी  
 बिना पास या टिकिट के या मे अपने पास बिना उचित  
 अपर्याप्त टिकिट या पास ले, पास या उचित टिकिट के गले  
 या उस दूरी से अधिक यात्रा हुए सफर करे, या किसी ट्रेन  
 करता जहां तक यात्रा करने का गाड़ी में रह कर या उससे  
 अधिकार हो उतर कर, धारा ६९ के अनुसार

मांगे जाने पर तुरत ही, अपना पास या टिकिट, जांच के लिये पेश  
 करने में कुसूर करे या इन्कार करे, या न दे, तो किसी ऐसे रेलवे  
 मुलाजिम के मांगने पर, जिसे रेलवे प्रबन्धक ने इस सम्बन्ध में  
 नियुक्त किया हो, ऐसे अतिरिक्त महसूल देने का जुरमेदार होवा  
 जिसका आगे चलकर इस धारा में वर्णन हुआ है, उस दूरी के  
 साधारण इकहरे किराये के सिवाय जो वह सफर कर चुका हो,  
 या जहां कि उस स्टेशन के सम्बन्ध में सन्देह हो जहां से कि वह  
 रवाना हुआ हो तो उस स्टेशन से साधारण इकहरे किराये के  
 सिवाय जिससे कि ट्रेन गाड़ी वास्तवमें चली हो, या यदि गाड़ी के  
 आरम्भिक रवाना होने पश्चात् गाड़ी में रुक कर करने वाले मुसा-  
 फिरों के टिकिटों की जांच हुई हो, तो उस स्थान से साधारण इक-  
 हरे किराये के सिवाय जहां कि टिकिट जांचे गये हों, या उनके एक

से अधिक बार जांचे जाने की दशा में, जहां कि अन्तिम बार जांचे गये हों।

(२) यदि कोई मुलाफिर किसी ऐसी गाड़ी में या गाड़ी से या ट्रेन से यात्रा करे या यात्रा करने की चेष्टा करे जो उस गाड़ी या ट्रेन से ऊंचे दर्जे की हो जिम्मे के लिये कि उस ने पास प्राप्त किया हो या टिकिट खरीदा हो, या उस स्थान से आने वाली में या गाड़ी पर सफर करे जहां तक सफर करने का वह टिकिट या पास के द्वारा अनिवार्य हो, तो किसी ऐसे रेलवे मुलाजिम या गणने पर जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा इस सम्बन्धमें नियुक्त हो, उस अतिरिक्त सदस्य के देने का ज़ुम्मेदार होगा जिसका इस धारा में आने के तहत दर्ज हुआ है, उक्त शेष किराये के सिवाय जो जानकी दिये हुए किराये और उस किराये के दरम्यान हो जो उस सफर के सम्बन्ध में देय हो जो उसने किया हो।

( ३ ) उक्त अतिरिक्त किराया, जिसका निष्पन्न उपधारा ( १ ) और उपधारा ( २ ) में दृष्टा है,

( क ) जब कि मुलाफिर किराया बढ़ने के पश्चात् तुरत ही और किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा पकड़े ( Detected ) जाने से पूर्व उस रेलवे मुलाजिम से जो ट्रेन में नौकरी पर हो, किराया भरने का दाल पट्ट दे तो, एक रुपया, दो आना या आठ आना होगा, और

( ख ) किसी दूसरी दशा में, छह रुपये, एक रुपया या तीन रुपये होंगे,

अर्थात् यदि मुलाफिर ऊंचे दर्जे या नीचे दर्जे की गाड़ी में या किसी और दर्जे या प्रकार की गाड़ी में सफर कर रहा हो, या उतामें सफर किया हो या सफर करने की चेष्टा की हो तो उस दर्जे या प्रकार की गाड़ी के लिहाज से:

परन्तु ध्यान यह है कि किसी दशा में उक्त अधिक किराया—

( क ) जब कि उसके देने की ज़ुम्मेदारी उपधारा ( १ ) से अनुसार उत्पन्न होती हो, उस साधारण रकम के किराये की रकम से न घटेगा जो जिसके देने का वह मुलाफिर जिस पर किराया बढ़ा हो उक्त उपधारा के अनुसार ज़ुम्मेदार है, या

(ख) जब कि उसके देने की जुम्मेदारी उपधारा (२) के अनुसार उत्पन्न होती हो, तो उस शेष रकम से अधिक न बढ़ेगा जो उस मुलाफिर द्वारा दिये गये किराये, जिस पर कि महसूल चढ़ा हो और उस किराये के व्ययमान हो जो उस सफर के सम्बन्ध में देय हो जो उस मुलाफिर ने किया हो।

(४) यदि कोई मुलाफिर अतिरिक्त किराया और महसूल जिसका वर्णन कि उपधारा (१) में हुआ है, या अतिरिक्त किराया और शेष महसूल जिसका वर्णन कि उपधारा (२) में हुआ है, देने का जुम्मेदार हो, उक्त उपधाराओं में से एक या दूसरी उपधारा के अनुसार, जैसी कि वशा हो, उसके मांगे जाने पर उक्त किराया (आदि) देने में कुसूर करे या इन्कार करे तो, इस सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियुक्त किसी रेलवे मुलाजिम क किसी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देने पर, वह रकम जो उस पर बाजिव हो, मुलाफिरसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार वसूल योग्य होगी मानो उक्त मजिस्ट्रेट ने मुलाफिर पर जुरमाना किया हो, और व्यों ही कि वसूल होजाय, रेलवे प्रबन्धक को वह रकम देदी जायगी।

**धारा ११४—** यदि कोई मनुष्य वापसी टिकट का कोई अद्धा वापसी टिकट या कोई अद्धा बदलना | बेचे वा बेचने की चेष्टा करे या अपने पास ले पृथक् करे वा पृथक् करने की चेष्टा करे, इस अभिप्राय से कि दूसरा मनुष्य उससे सफर कर लके, या वापसी टिकट का वैसा अद्धा खरीदे तो, उसे ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, और यदि वापसी टिकट को उस अद्धे का खरीदार उससे सफर करे वा सफर करने की चेष्टा करे तो, उसे ऐसे अतिरिक्त ( Additional ) जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की हद उस सफर के सम्बन्ध में जिसका टिकट के द्वारा अधिकारी हो, इकहरे किराये की रकम तक हो सकती है।

**धारा ११५—** किसी ऐसे जुरमाने का जो धारा ११२ या पूर्वोक्त अन्तिम दो धाराओं के जुरमाने के सम्बन्ध की कार्यवाही | पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार किया जाय, वह अंग जिसका अभिप्राय उक्त धाराओं में वर्णित इकहरे किराये से है, व्यों

हो कि वसूल हो, उक्त जुर्माने के किसी अंश को गवर्नमेन्ट के प्रति, जमा करने से पूर्व, रेलवे प्रबन्धन को अदा कर दिया जायगा।

धारा ११६— यदि कोई मुलाफिर जान बूझ कर अपने पास या टिकट का पास या टिकटको ऐसा बदल दे या बिगाड़ दे जल्दना या बिगाड़ना जिसकी तारीख, संख्या या उसका कोई मूल भाग पढ़े जाने योग्य न रहे, तो उसे ऐसे जुर्माने का वण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

धारा ११७— (१) यदि कोई मनुष्य जो हून या सांक्राफिक रेलवे में हून या सांक्राफिक रेलवे में सवारी यात्रा करना या ऐसे मनुष्य को यात्रा करने देना

मिथ रोग से ग्रस्त हो, धारा ७१ उपधारा (२) के प्रतिकूल, किसी रेलवे पर प्रवेश या यात्रा

करे, तो उसे और उक्त मनुष्य को, जिसकी निगरानी में उक्त मनुष्य उक्त समय रेलवे पर हो उस दि उक्त उक्त प्रकार प्रवेश किया या सफर किया, ऐसे जुर्माने का वण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है, उस किराये की जगह के बिनाय जो उनमें से किसी ने धारा धारा ७१ और पास या टिकट की जगह के बिनाय जो उनमें से किसी ने प्राप्त किया और सारीदा हो, और रेलवे से रेलवे के किसी मुलाजिम द्वारा निकाला जा सकता है।

(२) यदि कोई ऐसा रेलवे का मुलाजिम जो धारा ७१ उपधारा (२) में निर्दिष्ट किया गया है, वह जान कर कि कोई मनुष्य किसी हून या सांक्राफिक रोग से पीड़ित हो रहा है, जान बूझकर उक्त मनुष्य को, उसके मुलाजिमों से उसके पृथक् करने का प्रबन्ध करने दिया, रेलवे पर सफर करने दे, तो उसे ऐसे जुर्माने का वण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक हो सकती है।

धारा ११८— (१) यदि कोई मुलाजिम किसी गाड़ी में, उक्त गाड़ी में बैठना या और वस्तु अन्विष्ट रूप से गाड़ी से उतरे या प्रदेश करने या उतरे की चेष्टा करे, या गाड़ी की यात्रा को रोक कर जो इस गेट पार्स या अन्य स्थान से

मिला हुआ है जो सवारियों के गाड़ी में चढ़ने या उतरने के लिये रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियत हो, दूसरी ओर से गाड़ी में प्रवेश करे या गाड़ी से उतरे, या प्रवेश करने या उतरने की चेष्टा करे या किसी गाड़ी का उस समय बगली दरवाजा खोले जब कि ट्रेन चल रही हो, उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

( २ ) यदि कोई मुलाजिम, किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा बाज़ रहने के लिये आगाह किये जाने पर भी, किसी गाड़ी की छत, सीढ़ियों या पाय दोन या एन्जिन पर या ट्रेन के किसी ऐसे अन्य भाग पर जो मुलाजिमों के काम में आने के लिये न बना हो, सफ़र करने में हट करे, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है और वह रेलवे से किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा निकाला जा सकता है।

धारा ११६— यदि कोई मनुष्य, यह जानते हुए कि अमुक उस गाड़ी या अन्य स्थान पर गाड़ी, दर्जा, कमरा या अन्य प्रवेश करना जो स्त्रियों के लिये स्थान रेलवे प्रबन्धक द्वारा रिज़र्व्ड हो स्त्रियों के नितान्त प्रयोग के लिये

रिज़र्व्ड है, उचित उजू बिना, उक्त स्थान में प्रवेश करे या प्रविष्ट होने पर, जब कि उससे किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा उस स्थान से निकल जाने को कहा जाय, वहां रहे, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक हो सकती है उस किराये की जवती के सिवाय जो उसने अदा किया हो और उस पास या टिकट की जवती के सिवाय जो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

धारा १२०— यदि कोई मनुष्य, किसी रेलवे गाड़ी में या रेलवे में नशे में होना या रेलवे के किसी भाग पर, अन्य कष्ट कर कार्य करना

( क ) नशे की दशा में हो, या,

( ख ) कोई कष्ट कर ( Nuisance ) कार्य या लज्जा जनक कार्य

( Act of indecency ) करे या अश्लील भाषा या गाली प्रयोग करे, या

( ग ) जान बूझ कर और बिना उचित उद्देश के किसी मुलाफिर के धाराम में छलल डाले या किसी लैम्प को बुझावे,

तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, किसी ऐसे किराये की जगह की विषय हो उसने अदा किया हो और किसी पाल या टिकट की जगह हो तिकट हो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है ।

धारा १२१— यदि कोई मनुष्य जान बूझकर किसी मुला-  
रेलवे के माँदर को उस जिस रेलवे के सरकारी काम में  
के सरकारी काम से रोक्ता रुकावट या बिघ्न डाले तो उसे ऐसे  
जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक  
हो सकती है ।

धारा १२२— यदि कोई मनुष्य अनुचित रूप से रेलवे पर  
अनुचित प्रवेश और अनुचित प्रवेश करे तो उसे ऐसे जुर्माने का  
प्रवेश से राजधाने से रुकावट दिया जायगा जिसकी संख्या  
बीस रुपये तक हो सकती है ।

( २ ) यदि कोई मनुष्य जिसने रेलवे पर उक्त प्रकार प्रवेश  
दिया, किसी रेलवे मुलाजिम या रेलवे प्रबंधक की ओर से किसी  
अन्य मनुष्य द्वारा दहे जाने पर भी रेलवे से न निघटे, तो उसे  
ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये  
तक हो सकती है और यदि रेलवे मुलाजिम या अन्य मनुष्य द्वारा  
रेलवे से निकाला जा सकता है ।

धारा १२३— यदि ट्राम गाड़ी, ओमनीबस, गाड़ी या अन्य  
ओमनीबस या ट्रामगाड़ी रेलवे से रेलवे का हाँदने घाटा या  
गाड़ी की टिकटों के सम्बन्ध में या रेलवे से रेलवे में हो, किसी  
रेलवे मुलाजिम या पुलिस अधिकारी की उचित आज्ञाओं का

मिला हुआ है जो सवारियों के गाड़ी में चढ़ने या उतरने के लिये रेलवे प्रबन्धक द्वारा नियत हो, दूसरी ओर से गाड़ी में प्रवेश करे या गाड़ी से उतरे, या प्रवेश करने या उतरने की चेष्टा करे या किसी गाड़ी का उस समय बगली दरवाजा खोले जब कि ट्रेन चल रही हो, उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

( २ ) यदि कोई मुलाजिम, किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा बाज़ रहने के लिये आगाह किये जाने पर भी, किसी गाड़ी की छत, सीढ़ियों या पाय दान या एन्जिन पर या ट्रेन के किसी ऐसे अन्य भाग पर जो मुलाजिमों के काम में आने के लिये न बना हो, सफ़र करने में हट करे, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है और वह रेलवे से किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा निकाला जा सकता है।

धारा ११६— यदि कोई मर्द मनुष्य, यह जानते हुए कि अमुक उस गाड़ी या अन्य स्थान पर गाड़ों, दर्जा, कमरा या अन्य प्रवेश करना जो स्त्रियों के लिये स्थान रेलवे प्रबन्धक द्वारा रिज़र्व्ड हो स्त्रियों के नितान्त प्रयोग के लिये

रिज़र्व्ड है, उचित उजू बिना, उक्त स्थान में प्रवेश करे या प्रविष्ट होने पर, जब कि उससे किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा उस स्थान से निकल जाने को कहा जाय, वहां रहे, तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक हो सकती है उस किराये की जवती के सिवाय जो उसने अदा किया हो और उस पास या टिकट की जवती के सिवाय जो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा रेलवे से निकाला जा सकता है।

धारा १२०— यदि कोई मनुष्य, किसी रेलवे गाड़ी में या रेलवे में नशे में होना या रेलवे के किसी भाग पर, अन्य कष्ट कर कार्य करना

( क ) नशे की दशा में हो या,

( ख ) कोई कष्ट कर ( Nuisance ) कार्य या लज्जा जनक कार्य

( Act of indecency ) करे या अश्लील भाषा या गाली प्रयोग करे, या

( ग ) जान दूध कर और बिना उचित उजू के किसी मुसाफिर के आराम में छलल डाले या किसी लैम्प को बुझावे,

तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, किसी ऐसे किराये की जगहों के विषय जो उसने अदा किया हो और किसी पास या टिकट की जगहों के विषय जो उसने प्राप्त या खरीद किया हो, और वह किसी रेलवे मुलाजिम द्वारा रेलवे से गिराया जा सकता है।

धारा १२१— यदि कोई मनुष्य जान बूझकर किसी मुला-  
रेलवे के चौकरी को उस | जिस रेलवे के सरकारी काम में  
के सरकारी काम से रोकता रुकावट या बिघ्न डाले तो उसे ऐसे  
जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या एक सौ रुपये तक  
हो सकती है।

धारा १२२— यदि कोई मनुष्य अनुचित रूप से रेलवे पर  
अनुचित प्रवेश और अनुचित | प्रवेश करे तो उसे ऐसे जुर्माने का  
प्रवेश से राजधाने से हटार दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या  
पचास रुपये तक हो सकती है।

( २ ) यदि कोई मनुष्य जिसने रेलवे पर उक्त प्रकार प्रवेश  
किया, किसी रेलवे मुलाजिम या रेलवे प्रबन्धक की ओर से किसी  
अन्य मनुष्य द्वारा पड़े जाने पर भी रेलवे से न निकले, तो उसे  
ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये  
तक हो सकती है और वह रेलवे मुलाजिम या अन्य मनुष्य द्वारा  
रेलवे से निगाटा जा सकता है।

धारा १२३— यदि ट्राम गाड़ी, ओमनीबस, गाड़ी या अन्य  
ओमनीबस द्वारा पारोया रेलवे के | लवारी का हाँकने घाटा या  
लौकरी की विद्युत्तों के सम्बन्ध पलाई घाटा, उस समय जबकि  
में जाना चलाना करना वह रेलवे के अहाते में हो, किसी  
रेलवे मुलाजिम या पुलिस अधिकारी की उचित आज्ञाओं का



उलंघन करे तो उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या बीस रुपये तक हो सकती है

**धारा १२४— निम्न लिखित हर दो दशाओं में, अर्थात्—**

**फाटक खोलना या उचित**

**रूप से बन्धन करना**

( क ) यदि कोई मनुष्य यह जानता हुआ या यह भिन्नान्न करने का कारण रखता हुआ कि कोई एन्जिन या ट्रेन किसी रेलवे लैन पर आरुही है, किसी ऐसे फाटक को खोले जो सड़क के आर पार रेलवे के दोनों ओर लगा हो, या गुजरने या गुजरने की चेष्टा करे या किसी मवेशी, सवारी या अन्य चीज को रेलवे के आर पर हाँके या ले जाये, या हाँकने या लेजाने का प्रयत्न करे.

( ख ) यदि, फाटक वाले की अनुपस्थिति में, कोई मनुष्य उक्त फाटक को, जिस का वर्णन ऊपर हुआ है, खोले कि वह मनुष्य और कोई मवेशी, सवारी या अन्य चीज जो उस की निगरानी में हो, फाटक के भीतर से गुजर गये हो, बन्धन करे और न लगावे,

तो उक्त मनुष्य को ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिस की संख्या पचास रुपये तक हो सकती है ।

**धारा १२५— ( १ ) किसी ऐसे मवेशी के मालिक या पशुओं का अनुचित प्रवेश ।** जुम्मेदार मनुष्य को जो किसी ऐसी रेलवे पर भटकती फिरे जो पशुओं के रोकने के लिये ठीक तरह से घिरी हुई हो, ऐसे जुर्माने का दण्ड होगा जिस की संख्या प्रत्येक पशु के लिये पाँच रुपये तक हो सकती है किसी ऐसी रेलवे के लिवाय जो मवेशियों के अनुचित प्रवेश के कानून सन १८७१ ( एक्ट १ सन १८७१ ) के अनुसार दखल की जा सकती हो या दखल योग्य हो

( २ ) यदि कोई पशु, रेलवे पर उचित रूप से पार कराने के अभि प्राय या अन्य अभि प्राय को छोड़ कर और प्रकार से, किसी रेलवे पर जान बूझ कर हाँक दिया जाय या जान बूझ कर रहने दिया जाय तो, रेलवे प्रबन्धक की मरजी पर, उक्त पशु के जुम्मेदार

मनुष्य या मालिक को ऐसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा जिस की संपूर्ण प्रत्येक पशु के हिलाव से दण्ड रुपये तक हो सकती है, किसी ऐसी रकम के निवाय जो पशुओं के अनुचित प्रवेश के कानून खन १८७१ [ एक्ट १ खन १८७१ ] के अनुसार बसूल की जा सकती हो या बसूल योग्य हो।

[ ३ ] कोई ऐसा जुरमाना जो इस धारा के अनुसार किया जाय, यदि अदालत ऐसी कोर्ट है उस तरह बसूल की जा सकती है जिस की आज्ञा कि पशुओं के अनुचित प्रवेश के कानून खन १८७१ [ एक्ट १ खन १८७१ ] की धारा २५ में, है

[ ४ ] पशुओं के अनुचित प्रवेश के कानून खन १८७१ [ एक्ट १ खन १८७१ ] की धारा ११ और २५ के शब्द "सरकारी सड़क" में रेलवे का सम्मिलित होना सम्झा जायगा और कोई रेलवे मुन्सिफ उन अधिकारों को काम में ला सकता है जो एक धाराओं में से पहिली धारा के अनुसार पुलिस-अधिकारियों को प्रदान हुए हैं।

( ५ ) शब्द मवेशी का इस धारा में वही अर्थ है जो मवेशियों के अनुचित प्रवेश के कानून खन १८७१ [ एक्ट १ खन १८७१ ] में है।

**धारा १२६— यदि कोई मनुष्य कानून के विरुद्ध—**

कानि पं.दाने की नीयत से  
द्वेन गाड़ी दरबाद करना या  
दरबाद करने का प्रयत्न करना।

[ ६ ] किसी रेलवे पर या रेलवे के आर पार टकड़ी, पत्थर, या अन्य पदार्थ ला लीज रखे या फेंके, या

[ ७ ] किसी ऐसी रेल, स्लीपर, या अन्य वस्तु या चीज़ को जो किसी रेलवे से सम्बन्धित हो निटारो, हटावे, खोले या उस की रंगद से पुछा करे, या

( ८ ) किसी ऐसे पाहटों या अन्य मशीनों को, जो किसी रेलवे से सम्बन्धित हों, फेंके, हिलावे, खोले या चरले, या

( ९ ) किसी रेलवे पर या रेलवे के निकट कोई सिगनल या रोशनी बरे या दिखलावे, या किसी सिगनल या रोशनी को छिपावे या हटावे, या

( ड ) किसी ऐसी रेलवे के सम्बन्ध में कोई अन्य काम या चीज करे या करावे या करने की चेष्टा करे,

इस द्वारे या जानकारी के साथ कि वह किसी ऐसे मनुष्य की सलामती में उस के काम से खतरा होने की सम्भावना है जो किसी रेलवे पर सफर कर रहा हो या किसी रेलवे में हो, तो उसे यावज्जीवन देश निकाले का दण्ड दिया जायगा या ऐसी मीमांसा की कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है।

**धारा १२७—** यदि कोई मनुष्य कानून के विरुद्ध किसी

<p>हानि पहुंचाने की नीयत से उन मनुष्यों की हानि पहुंचाना या पहुंचाने का प्रयत्न करना जो रेलवे से यात्रा कर रहे हों</p>	<p>ऐसी पहिये वाली चीज पर, चीज के मुकाबिले, आदर या ऊपर, जो किसी ट्रेन का भाग हो, कोई लकड़ी, पत्थर या</p>
--	---

अन्य चीज या वस्तु, फेंके, गिरावे या मारे, इस द्वारे या जानकारी के साथ कि उस के कार्य से किसी ऐसे मनुष्य की सलामती में खतरा पड़ने की सम्भावना है जो किसी ऐसी उक्त पहिये वाली चीज या किसी ऐसी अन्य पहिये वाली चीज में या पर हो जो उली ट्रेन का भाग हो, तो उसे यावज्जीवन देश निकाले का दण्ड दिया जायगा या ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है।

**धारा १२८—** यदि कोई मनुष्य किसी कानून विरुद्ध कार्य

<p>इच्छा युक्त कार्य या कार्य त्याग द्वारा उन मनुष्यों की सलामती संशय में डालना जो रेलवे में यात्रा कर रहे हो</p>	<p>द्वारा, या किसी इच्छा युक्त कार्य त्याग या असानधानी के कारण, किसी ऐसे मनुष्य की सलामती खतरे में डाले या</p>
---	--

डकवाये जो किसी रेलवे पर सफर कर रहा हो या रेलवे में हो, या किसी पहिये वाली चीज को किसी रेलवे पर रोकने या रुकवाये या रोकने की चेष्टा करे तो उसे ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है।

धारा १९९—यदि कोई मनुष्य शीघ्रतासे या असावधानीसे

जल्दी या असावधानता के कार्य	कोई काम करे या ऐसा काम न
या कार्य त्याग द्वारा, उन मनुष्यों	करे जिस के करने के लिये वह
की सहायता संशय में डालना	कानून से बद्ध ( पाबन्द ) हो
जो रेलवे में यात्रा कर रहे हों	और उक्त कार्य त्याग से किसी

ऐसे मनुष्य की सहायता में खतरा पड़ने की सम्भावना हो जो किसी रेलवे पर सफर कर रहा हो या रेलवे में हो, उसे ऐसी कैद का दण्ड दिया जायगा जिस की अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या उसे जुरमाने का दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायंगे।

धारा १३०— ( १ ) यदि कोई नाबालिग ( अमात व्यवहार )

विशेष आता कर्त्यों के उन	जो वार्षिक वर्ष से कम अवस्था
कार्यों के सम्बन्ध में जिनके	का हो, किसी रेलवे के सम्बन्ध
रेलवे में यात्रा करने वालों की	में, उन कार्यों या कार्य—त्यागों
सहायता में संशय पड़े	में से, जिसका निरूपण पूर्वोक्त

अन्तिम बार धाराओं में से किसी धारा में किया गया है, किसी कार्य या कार्य—त्याग का दोषी हो, तो भारतीय दण्ड संग्रह (ताजीरात हिंदू एक्ट ४५ रात १८६०) की धारा ८२ या ८३ में चाहे जो कुछ होते हुए, यह लक्ष्य धारणा कि उसने अपराध किया, और उसे दण्ड देने वाली अदालत को अधिकार है कि यदि वह उचित समझे, यह आज्ञा दे कि उक्त नाबालिग को, यदि लड़का है, पैतृ मारने का दण्ड दिया जायगा, या यह आज्ञा दे सकती है कि उक्त नाबालिग का बाप या अभिभावक ( Guardian ) उस मीयाद के भीतर जो अदालत नियत करे, ऐसा सुचलता लिख दे जिसमें यह अपने को ऐसे दण्ड के लिये बद्ध होना स्वीकार करे, जो अदालत धारणा दे, नाकि उक्त नाबालिग को उक्त कार्य या कार्य—त्यागों में से किसी कार्य या कार्य—त्याग के द्वारा दोषी होने से रोके।

( २ ) मुदत के की रकम, यदि लब्ध होजाय, अदालत द्वारा इस प्रकार दण्ड योग्य होगी मानो वह उसी का किया हुआ जुरमाना हो।

( ३ ) यदि वाप या अभिभावक उपधारा ( १ ) के अनुसार उस समय के भीतर मुचलकी न लावे जो अदालत ने नियत किया हो, उसे ऐसे जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है ।

## कार्य—प्रणाली

धारा १३१—( १ ) यदि कोई मनुष्य कोई ऐसा अपराध करे कुछ धाराओं की प्रति कृता | जिसका वर्णन धारा १००, १०१ के अपराध में गिरफ्तारी ११९, १२०, १२१, १२६ १२७, १२८, या १२९ या धारा १३० की उपधारा ( १ ) में हुआ है, तो वह मनुष्य बिना वारन्ट या अन्य लेख बद्ध इस्तयार नामे के किसी रेलवे मुलाजिम या पुलिस अधिकारी द्वारा, या ऐसे अन्य मनुष्य द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है जिसे उक्त मुलाजिम या पुलिस अधिकारी अपनी सहायता को बुलावे ।

( २ ) उक्त प्रकार गिरफ्तार किया हुआ मनुष्य, कम से कम सम्भवित ( विलरय के साथ, ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने लेजाया जायगा जिसको उस मुकद्दमे का विचार करने या विचारार्थ सुपुर्द ( Commit ) करने का अधिकार हो ।

धारा १३२—( १ ) यदि कोई मनुष्य, उपर्युक्त अन्तिम ऐसे मनुष्यों की गिरफ्तारी जिनके धारा में दर्जित अपराध का भागने की संभावना हो या छोड़ कर, इस एक्ट के जिनका पता न मालूम हो | अनुसार कोई अपराध करे, या कोई अतिरिक्त महसूल या अन्य रकम जो धारा ११३ के अनुसार मांगी जाय न दे या देने से इन्कार करे, और यह विश्वास करने का कारण हो कि वह भाग जायगा या उसका नाम और पता मालूम न हो, और वह पूछने पर अपना नाम और पता न बतलाये, या यह विश्वास करने का कारण हो कि उस का बतलाया हुआ नाम और पता गलत है, तो कोई रेलवे मुलाजिम या पुलिस अधिकारी या कोई अन्य मनुष्य जिसे उक्त मुलाजिम या अधिकारी अपनी सहायता को बुलावे, उस मनुष्य को बिना वारन्ट या अन्य लेख बद्ध इस्तयार नामे के गिरफ्तार कर सकते हैं ।

( २ ) गिरफ्तार किया हुआ मनुष्य उसकी जमानत देने पर छोड़ दिया जायगा, या, यदि उसका नाम और पता निश्चित हो जाय तो, मजिस्ट्रेट के सामने, जब आवश्यकता पड़े, उसकी उपस्थिति के लिये, बिना जमानत, मुचलका लिखने पर छोड़ दिया जायगा ।

( ३ ) यदि उक्त मनुष्य अपनी जमानत न दे सके और उसका ठीकनाम औरपता मालूम नहो,तो वह,क्रमसेक्रम सम्मिलित विलम्ब के साथ, उस सब से पाल के मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जायगा जिस को उसके विचार करने का अधिकार प्राप्त हो ।

( ४ ) जायदात कौजदारी १८८२ ( एक्ट १० खन १८८२ ) के अध्याय ३९ और ४२ की आज्ञाएं, जहां तक संभव हो सकें, उस जमानत और मुचलके से सम्बन्ध रखेंगी जो इस धारा के अनुसार दी जाय और लिखे जाय ।

धारा १३३—प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट या उस मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट जिनको इस एक्ट के अनुसारविचार अधिकार प्राप्तहो सिवाय जिसके अधिकार दूसरे दरजे के अधिकारों से कम न हो, कोई मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अनुसार अपराध का विचार न करेगा ।

धारा १३४—( १ ) कोई ऐसा मनुष्य जो इस एक्ट के प्रति-  
विचार-स्थान कूल या उस नियम के प्रतिकूल जो इस एक्ट के अनुसार पने, अपराध करे, उक्त अपराध के लिये उस स्थान में विचारणीय होना जहां कि वह हो या जिसको स्थानीय गवर्नमेंट इस संबंध में विशोधित करे, और उसका विचार उस अन्य स्थान में भी होगा जिसमें कि किसी और कानून के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो उस का विचार हो सकता ।

( २ ) उप धारा ( १ ) के अनुसार प्रत्येक विपत्ति ( Notification ) स्थानीय सरकारी गज़ट में प्रकाशित की जायगी और उसकी एक कापी जनता की सूचना के लिये प्रत्येक ऐसे रेलवे स्टेशन के किसी विरिष्ट ( Conspicuous ) स्थान पर प्रदर्शित की जायगी जिससे लिये कि स्थानीय गवर्नमेंट आता है ।

# दसवाँ परिच्छेद

## पूरक आशाएं

धारा १३५—किसी एकट में या किसी ऐसे इकरारनामे या स्थानीय अधिकारियों की ओर | फ़ैसला पन्चायती में जो किसी से रेलवियों पर टैक्स एकट के आधार पर हो, चाहे कोई बात खिलाफ़ ही क्यों न हो, रेलवियों के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्धकों से, स्थानीय अधिकारियों के सरमायों की सहायतायें, टैक्स वसूल करने का निम्न लिखित नियमों के अनुसार प्रबन्ध किया जायगा, अर्थात्:—

( १ ) कोई रेलवे प्रबन्धक किसी स्थानीय अधिकारी के सरमायों की सहायता के लिये किसी टैक्स के अदा करने का उस समय तक ज़ुम्मेदार न होगा जब तक कि सपरिषद् गवर्नर जनरल, सरकारी गजट में ( प्रकाशित ) विज्ञप्ति द्वारा, उस रेलवे प्रबन्धक को उक्त टैक्स के अदा करने का ज़ुम्मेदार करार न दे दें ।

( २ ) जब कि इस धारा के खंड ( १ ) के अनुसार सपरिषद् गवर्नर जनरल की विज्ञप्ति जारी रहे, रेलवे प्रबन्धक स्थानीय अधिकारी या तो उक्त विज्ञप्ति में वर्णित टैक्स अदा करने का ज़ुम्मेदार होगा, या उसके बदले में ऐसी रकम [ यदि हो ] देने का ज़ुम्मेदार होगा जिसे वह सम्बन्ध में सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त अफसर, उस मुआयले की समस्त अवस्थाओं का विचार करके, समय २ पर उचित और ठीक निर्णय करे ।

( ३ ) सपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह इस धारा के खंड ( १ ) के अनुसार विज्ञप्ति को मसूख कर दें या बदल दें ।

( ४ ) इस धारा की किसी बात के यह अर्थ न लिये जायगे कि वह किसी रेलवे प्रबन्धक को किसी स्थानीय अधिकारी के साथ पानी या रोशनी के संग्रह के लिये या रेलवे के अदातों की सफाई के लिये या किसी ऐसे अन्य काम के लिये, इकरार (contract) करने से रोकेंगा जो स्थानीय अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र फल के किसी भाग में जो उसकी निगरानी में हो, करता हो या करना चाहता हो ।

( ५ ) इस धारा में स्थानीय अधिकारी का अभिप्राय उस स्थानीय अधिकारी से है जिस की परिभाषा जनरल फ्लाइंग प्रदत्त १८८७ में की गई है, और उस में वह अधिकारी सम्मिलित है जो पोलीसों के काम करने या किसी नदी की रक्षा करने के सम्बन्ध में किसी करलाये की निगरानी और प्रदत्त को कानून के अनुसार अधिकारी ( Entitled मुस्तद्दिक ) या सुपुर्द दार ( Entrusted ) हो।

धारा १३६—( १ ) कोई पहिले वाली चीज़, कल, मद्रा हुआ रेलवे की सम्पत्ति के प्रति कूल वंज, औज़ार, कल ठीक करने एकराय डिगरी सम्बन्धी शर्त । का सामान, सामग्री या अलवान जो रेलवे प्रदत्त अपनी रेलवे पर या अपने स्टेशनों या कारखानों में ट्राफिक के अभिप्राय के लिये काम से लाता हो या उसने संग्रह किया हो, उपरिष्ठ गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, किसी ऐसी अदालत या किसी ऐसे स्थानीय दफ्तर या समुप्य की, जिसको माल के कुर्क का जवाब करने का या और प्रकार से इजराय डिगरी की इल्दत में माल लिबाने का कानून के अनुसार अधिकार हो, किसी डिगरी या आशा की इजराय में लिये जाने योग्य न होगा।

( २ ) इस धारा ( १ ) की किसी बात से यह अर्थ न लिया जायगा कि वह किसी अदालत में उस अधिकार में दस्तक्षेप डालेगा जो डिगरी या आशा के इजराय में रेलवे की आमदनी कुर्क करने के सम्बन्ध में हो।

धारा १३७—( १ ) रेलवे का प्रत्येक नौकर भारतीय दण्ड शास्त्रीय दण्ड संग्रह के अध्याय ९ के अभिप्रायों के लिये रेलवे के नौकर सरकारी नौकर समझे जायगे। संग्रह ( प्रदत्त ४५ खन १८६० ) के अध्याय ९ के अभिप्रायों के लिये सरकारी नौकर समझा जायगा।

( २ ) उक्त संग्रह की धारा १६१ की "कानूनी मुआवज़ा" की परिभाषा में, शब्द "गवर्नमेन्ट" से, उपधारा ( १ ) के अभिप्रायों के लिये, यह समझा जायगा कि उसमें रेलवे के नौकर का नियुक्त करने वाला एक दैतियत से शामिल है।



( ३ ] कोई रेलवे का नौकर—

[ क ] किसी ऐसे माल को जो धारा ५५ या ५६ के अनुसार नीलाम पर रखा जाय, स्वयं या मुख्तार द्वारा, अपने नाम से दूसरे के नामले, साझे में या दूसरों के साथ हिस्सों में, न खरीदेगा और न बोली बोलेगा, या ।

[ ख ] किसी रेलवे प्रबन्धक की इस सम्बन्ध में किसी आज्ञा के प्रतिकूल व्यापार में संलग्न न होगा ।

( ४ ) भारतीय दण्ड संग्रह ( ताजीरात हिन्द ) की धारा २१ में खाहे जो कुल हो, रेलवे का नौकर, सिवाय उन अभिप्रायों के जिन का वर्णन उपधारा (१) में हुआ है, उक्त संग्रह के किसी और अभिप्रायों के लिये, सरकारी नौकर न समझा जायगा ।

**धारा १३८—**यदि कोई रेलवे का नौकर अपने पद से पृथक् रेलवे प्रबन्धक को उस सम्पत्ति या मुअत्तल हो जाये, या मर के सरसरी रूप से देने का कार्य जाय, भाग जाय या गैर हाजिर क्रम जिसे रेलवे के नौकर ने रोक हो, और वह या उसकी स्त्री या लिया हो । बिधवा, या उस के खानदान या

प्रतिनिधियों का आदमी, उस अभिप्राय की लेखबद्ध सूचना पाने पर भी, रेलवे प्रबन्धक को या उस मनुष्य को जिसे रेलवे प्रबन्धक इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, कोई स्टेशन, रहने का मकान, दफ्तर या अन्य भवन उसके सम्बन्धी सामानों सहित, या कोई रजिस्टर, कागजात या अन्य चीजें, देने से इंकार या देने में अस्वावधानी करे जो उपर्युक्त लिखी किसी घटना के होने के समय रेलवे प्रबन्धक की सम्पत्ति हो और उक्त रेलवे मुलाजिम के कब्जे या निगरानी में हो, तो किसी पहिले दर्जे के मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह उस प्रार्थना पत्र पर, जो रेलवे प्रबन्धक द्वारा या उसकी ओर से दिया जाय, यह आज्ञा दे कि कोई अफसर पुलिस उचित सहायता के साथ उक्त भवन में प्रवेश करे और जिस को वहां पाये निकाल दें और उस पर कब्जा कर ले. या रजिस्टरों, कागजों या अन्य चीजों पर कब्जा करे और उनको रेलवे प्रबन्धक या उस मनुष्य को हवाला कर दे जो रेलवे प्रबन्धक की ओर से इस सम्बन्ध में नियुक्त हो ।

धारा १३६—इस एक्ट के अधिप्रायोंके लिये या इस एक्ट के सपरिपद गवर्नर जनरल से प्राप्त पत्र व्यवहार को प्रकट करने की विधि ।

सम्बन्ध में, सपरिपद गवर्नर जनरल को ओर से जो सूचना कि दी जाय, जो निर्णय कि किया

जाय, जो हिदायत कि की जाय, जो आज्ञा या नियुक्ति कि की जाय, जो सरासति. एजानन्दी या स्वीकृति कि प्रकट की जाय, या उस में जो अधिकार या शर्त वर्णित हो, पर्याप्त और पालने योग्य होगा यदि वह लेख बद्ध हो और उस पर भारतीय गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, या असिस्टेंट सेक्रेटरी, या किसी अन्य अधिकारी या नौकरके जो सपरिपद गवर्नर जनरल की ओर से उन कामों के सम्बन्धमें काम करने का अधिकार रखता हो, जिनसे वह संबन्धित हो, दस्ताक्षर हो, और सपरिपद गवर्नर जनरल किसी दशा में, उक्त कथित बातों में से किसी बात के सम्बन्ध में उस समय तक बद्ध ( Bound पाबंद ) न होंगे जब तक कि किसी लेख पर उक्त कथित रूप से हस्ताक्षर न हों ।

धारा १४०—कोई ऐला नोटिस या अन्य लेख पत्र, जिसका रेलवे प्रबन्धकों पर नोटिसों की तामील

इस एक्ट के अनुसार रेलवे प्रबन्धक पर तामील होना आवश्यक या उचित

हो उस रेलवे की दशामें जिसका प्रबंध गवर्नमेंट या हिन्दुस्तानी रियासत करती हो, मैनेजर पर और उस रेलवे की दशा में जिसका प्रबंध कोई रेलवे कंपनी करती हो, रेलवे कंपनी के भारत में रहने वाले ऐजेंट पर, निम्नलिखित तरीके से तामील किया जा सकता है ।

( क ) उक्त मैनेजर या ऐजेंट को नोटिस या अन्य लेख पत्र देकर दे, या

( ख ) उसके दफतर में उसे छोड़कर, या

( ग ) किसी महसूल दी हुई बिट्टी में मैनेजर या ऐजेंट के नाम उसके दफतर के पते पर डाक द्वारा भेज कर और भारतीय डाक साना के कानून सन १८६६ के तीसरे भाग के अनुसार रजिस्टरी करा कर ।

**धारा १४१—** कोई नोटिस या अन्य लेख पत्र जिसका रेलवे रेलवे प्रबन्धकों द्वारा प्रबन्धक की ओर से किसी मनुष्य पर नोटिसों की तामील तामील होना इस एक्ट के अनुसार आवश्यक या उचित हो, निम्न प्रकार तामील किया जा सकता है,

- ( क ) उक्त मनुष्य को उसे देकर, या
- ( ख ) उक्त मनुष्य के साधारण रहने के स्थान या अन्तिम जाने हुए रहने के स्थान पर उसे छोड़ आकर, या
- ( ग ) पहिले महसूल की हुई चिट्ठी में, उक्त मनुष्य के नाग के उसके साधारण रहने के मकान के पते या अन्तिम जाने हुए रहने के मकान के पते पर डाक द्वारा भेज कर और भारतीय डाक खानों के कानून दान १८६६ के भाग तीन के अनुसार रजिस्टरी करा कर ।

**धारा १४२—** जब किसी नोटिस या अन्य लेख पत्र की डाक अनुमान जब कि नोटिस द्वारा तामील की जाय, तो की तामील डाक द्वारा की जाय उसका उस समय तामील होना समझा जायगा जब कि चिट्ठी जिसमें उक्त नोटिस या लेख पत्र है, डाक के साधारण साधन से देदी जाय, और ऐसी तामील के साबित करने में यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि उक्त चिट्ठी पर जिसमें नोटिस या अन्य लेख पत्र हो ठीक रूप से पता लिखा गया और उसकी रजिस्टरी उचित रूप से की गई थी ।

**धारा १४३—** ( १ ) धारा २२, धारा ३४ या धारा ८४ के नियमों के सम्बन्ध में अनुसार नियमका, या उपर्युक्त धाराओं में से किसी धारा के अनुसार या धारा ४३ की उप-धारा ( ४ ) के अनुसार नियम के रह होने, मंसूख होने या बदलने का प्रभाव उस समय तक न होगा जब तक कि वह भारतीय गज़ट में प्रकाशित न हो जाय ।

( २ ) जब कि इस एक्ट के अनुसार बने हुए नियम के, या उक्त नियम के रह होने, मंसूख होने या बदलने की, इस एक्ट के अनुसार भारतीय गज़ट में प्रकाशित होने की आवश्यकता हो, तो उक्त

प्रकाशित होने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक होगा कि उन मनुष्यों को जो उससे प्रभावित हों इस तरीके से विशेष सूचना दी जायगी जैसी कि लपरिपद गवर्नर जनरल, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

( ३ ) लपरिपद गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वह उस नियम को जो उन्होंने इस एक्ट के अनुसार बनाया हो रद्द कर दें या बदल दें।

धारा १४४— ( १ ) लपरिपद गवर्नर जनरल को अधिकार है

लपरिपद गवर्नर जनरल को अधिकारों का दिया जाना	कि वह भारतीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा, स्वाधीनतः अथवा
---	---

राज्यों के माध्याम, किसी स्थानीय गवर्नमेन्ट को उन अधिकारों या कर्त्तव्यों में से कोई अधिकार या कर्त्तव्य छुट्टी करे जो लपरिपद गवर्नर जनरल को इस एक्ट के अनुसार किसी रेलवे के सम्बन्ध में प्राप्त हैं, और यह भी अधिकार है कि उसी या वैसी ही विज्ञप्ति द्वारा, यह निश्चय कर दें कि कोत सी स्थानीय गवर्नमेन्ट, उक्त प्रकार दिये हुए अधिकारों या कर्त्तव्यों के प्रयोग होने के अभिप्रायों के लिये रेलवे के सम्बन्ध में स्थानीय गवर्नमेन्ट संपन्नो जायगी।

( २ ) लपरिपद गवर्नर जनरल को कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा १२९ की आज्ञाएं जहां तक कि सम्बन्धित की जा सकती हैं, उस स्थानीय गवर्नमेन्ट की कार्यवाहियों से सम्बन्धित होंगी जो एव धारा ( १ ) की विज्ञप्ति के अनुसार लपरिपद गवर्नर जनरल के अधिकार कायम में लाती या कर्त्तव्यों का पालन करती हो।

धारा १४५— ( १ ) ऐसी रेलवे के मैनेजर को जिसका

रेलवे के मैनेजर और ऐजेंट का अदायग में प्रतिनिधित्व	प्रदन्ध गवर्नमेन्ट या देसी रियासत द्वारा होता हो, और ऐसी रेलवे के ऐजेंट को जिसका प्रदन्ध रेलवे दम्पती के द्वारा होता
--	--

हो, अधिकार है कि वह टेण्डर दस्तावेज द्वारा, किसी रेलवे

मुलाजिम या अन्य मनुष्य को किसी दीधानी, फौजदारी या अन्य अदालत के सामने किसी कार्य वादी में, उस मैनेजर या पेजेन्ट की ओर से काम करने का प्रति निधि होने का अधिकार प्रदान करे।

(२) वह मनुष्य जिसे रेलवे प्रबन्धक की ओर से पैरवी मुकद्दमा करने का अधिकार प्राप्त हो, बिना विचार इस बात के कि जाबता फौजदारी सन १८८२ (एक्ट १० सन १८८२) की धारा ४९५ में कुछ ही लिखा हो, मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना मुकद्दमों की पैरवी करने का अधिकारी होगा।

धारा १४६ लपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि

<p>दुखानी ट्रामवेज के सम्बन्ध में एक्ट की प्रचार-बुद्ध करने का अधिकार</p>	<p>वह भारतीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस एक्ट को या इस के किसी भाग को, किसी ऐसी ट्रामवे से</p>
---	---

सम्बन्धित कर दें जो स्टोम या अन्य कल की शक्ति से चलाई जाय।

धारा १४७— लपरिषद् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि

<p>इस एक्ट से रेलवेज को प्रथक रखने का अधिकार</p>	<p>वह समान विज्ञप्ति द्वारा, किसी रेलवे को, इस एक्ट की किसी आश्वसे सुरतस्ना</p>
--	---

(पृथक) कर दें।

धारा १४८— (१) धारा ३ खण्ड (५), (६) और (७),

<p>बातें जो “रेलवे और रेलवे के नौकर” की परिभाषाओं की पुरक हैं</p>	<p>और धारा ४ से १९ तक (दोनों सम्मिलित) धारा ४७ से ५२ तक (दोनों सम्मिलित) ५९, ७९, ८३ से ९२</p>
---	---

तक (दोनों सम्मिलित), ९६, ९७, ९८, १००, १०१, १०३, १०४, १०७, १११, १२२, १२४, १३२ तक (दोनों सम्मिलित), १३४ से १३८ तक (दोनों सम्मिलित), १४०, १४१, १४४, १४५ और १४७ के अभि-  
प्रायों के लिये, शब्द “रेलवे” से चाहे वह अकेला जाया है या किसी शब्द के पड़िछे, वह रेलवे या रेलवे का भाग जो बनाई जा रही है और वह रेलवे या रेलवे का भाग जो मुसाफिरों, पशुओं और माल

के सर्व साधारण के लिये जेजाने के काम में न आती ही और वह रेलवे भी सम्बन्धित है जो धारा ३ खण्ड (४) में एक शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो।

(२) धारा ५, २१, ८३, १३०, १०१, १०३, १०४, १२१, १२२, १२५, और १३७, की उपधाराएं (१), (२) और (४), और धारा १३८ के अभिप्रायों के लिये, शब्द "रेलवे का नौकर" में वह मनुष्य सम्मिलित है जो रेलवे पर उस की सेवा के सम्बन्ध में किसी ऐसे मनुष्य द्वारा नियुक्त किया गया हो जो रेलवे प्रबन्धक के साथ कुशाद्विदा पूरा करता हो।

धारा १४६— भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ११४ और भारतीय दण्ड संग्रह १९५ में "इस संग्रह या दण्ड संग्रह के कानून का संशोधन" द्वारा "के स्थान में शब्द " ब्रिटिश भारत या दण्ड संग्रह के कानून द्वारा " रखे जायेंगे।

धारा १५०— सिन्ध प्रेशीन रेलवे एक्ट सन १८८७ (एक्ट ११ सिन्ध प्रेशीन रेलवे एक्ट सन १८८७) की भूमिका के उस भाग सन १८८७ का संशोधन के बदले जिसका प्रारम्भ "जहां तक कि इसका सम्बन्ध है " शब्दों से होता है और अन्त "पूर्णतः सम्बन्धित हो" शब्दों के साथ होता है, यह शब्द रखे जायेंगे "उत्तर पश्चिमीय रेलवे के दिरसे सिन्ध प्रेशीन के उस भाग से पूर्णतः सम्बन्धित होगा जो सिन्ध प्रान्त के बाहर स्थित है।"

# पहिला शैड्यूल

## कानून जो मंसूख हुए

( दूसरी धारा देखिये )

संख्या और साल	नाम	मंजूरी की वद
---------------	-----	--------------

### सपरिषद गवर्नर जनरल के कानून

३ सन १८६५	बाइकों का कानून १८६५	धारा ७(जहां तक कि उसका संबंध रेलवेज़ से है) और धारा १०
४ सन १८७९	भारतीय रेलवे का कानून १८७९	कुल
४ सन १८८३	भारतीय रेलवे का कानून १८८३	कुल
११ सन १८८६	भारतीय ट्रामवेज़ का कानून १८८६	धारा ४९

### सपरिषद लैफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के कानून

२ सन १८८२	बंगाल की पुश्ताबन्दी का कानून सन १८८२	धारा १६, और धारा १७ में उक्त धारा के पहिले पैरे की शर्त और शब्द "या पूर्वोक्त अन्तिम धारा के अनुसार" "और शब्द "या रेल की लड़क" जहां कहीं वह आये हों
-----------	---------------------------------------	---

# दूसरा शैड्यूल

चीजें जो प्रकट और चीमा की जायगी

## ( धारा ७५ देखिये )

( क ) लोना और चांदी, सिक्केदार या बेसिककेका, बना हुआ या बिना बना हुआ;

( ड ) मुलुममे की चीजें

( ग ) कपड़े, जरबकत और लैल, जिसमें लोने चांदी का हिस्सा हो, परन्तु वह किसी अफसर, लिपाही, खलासी पुलिस अफसर, या ऐसे मनुष्य की, जो भारतीय बालन्टीयरों के कानून सन १८६९ के अनुसार बालन्टीयरों में भरती हुआ हो, या किसी ऐसे सरकारी अफसर की जो ब्रिटानिया या दूसरे देश का हो, और जो सरदी पदनने का अधिकारी हो, सरदी या सरदी का भाग न हो।

( ब ) मोती, मूल्यवान पत्थर, जवाहरात और गहना आदि

( ज ) किसी प्रकार की जेब घड़ियां धर्मघड़ियां और टाइम पीस,

( घ ) सरकारी कागजात फिफालत

( छ ) सरकारी स्टाम्प

( ङ ) बिल आफ एक्सचेंज, पुन्डी, प्रामेसरी नोट, बैंक नोट, और एक्शों के भदा करने की चिट्ठियां और अन्य दस्तावेज,

( स ) नकशे, लेख और जायदाद के दस्तावेज

( ग ) रंगदार तस्वीरें, खुदी हुई ( तस्वीरें ) लैथो की छपी हुई चीजें, फोटों की तस्वीरें, खुदी हुई नक्काशी, पत्थर की मूर्तियां, और कला कौशल के अन्य काम,

( ट ) मिट्टी के दरतन और वह तमाम चीजें जो शीशे, चीनी मट्टी या लंग गर गर की बनी हों,



( ९४ )

- ( ठ ) रेशम, बनी हुई या न बनी हुई दशा में, और चाहे दूसरी चीजों के साथ मिलाकर बना हो या न बना हो,
- ( ड ) ताल
- ( ढ ) लैस और पशमी चीज़ें ( फ़र )
- ( ण ) अफीम
- ( त ) षाथोदांत, आवजूस, मूंगा और सेंदल की लकड़ी
- ( थ ) मुद्गक, सेंदल का तैल और अन्य आवश्यक्रीय तैल जो इत्र या अन्य सुगन्धि के बनाने में काम आते हों,
- ( द ) गाने के और साइन्स के यन्त्र,
- ( ध ) खास मूल्य की कोई चीज़ जिसे सपरिषद् गवर्नर जनरल ने भारतीय गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा, इस सूची में शामिल कर दिया हो ।

---

मिलने का पता—

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी० पी० कम्पनी

अलीगढ़ सिटी ।

सरकार गवर्नमेन्ट से मंजूर की हुई

## कानून की पुस्तकें

हिन्दी भाषा में हाल तक की तरतीब सहित जिनको एक सुयोग्य वकील द्वारा इंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद करा के सभी छपाई हैं जिनको थोड़ी हिन्दी जानने वाले भी आसानीके साथ समझ सकें और मुकद्दमे की समस्त कार्यवाही समय पड़ने पर स्वयं ही कर सकें।

कानून जायदादीवाली सार १)	कानून दफतीना 1)
कानून जायदादीवाली सार १)	कानून तार 1)
कानून ताजीरात हिंद २)	कानून प्रेत (छापाखाना) 1)
कानून पुल्ल 11)	कानून अखबार 1)
कानून डाकखाना 11)	कानून दंडवारा 2)
कानून मियाद समाजत 11)	कानून रजिस्टरी 11)
कानून पंचायत 1)	कानून रेलवे १)
कानून जूआ 1)	कानून खफीफा 1)

## कानून दर्पण

यह पुस्तक इतनी सर्व प्रिय हुई है कि थोड़े ही दिनों में इसके ७ संस्करण छपकर एजाराँ प्रतियाँ बिक गईं। इसमें भारत के प्रायः सबही कानून लिखे हैं जैसे कानून ताजीरात हिंद, जायदादीवाली व पौजदारी मियाद समाजत, आयकारी, पल्हेदारी दफतीना हथियार गदाइत व अमानत, फेल नाजायज़, पागल खाना स्टाम्प, कोर्ट फील, रजिस्टरी इफ्तम टैक्स, इन्तकाल जायदाद, ट्रेडमार्क, तल्लक दफतीना, कम्पनी फारखाने इत्यादि बहुत सी कानूनों की सरल सुगमता खूरी यह है कि कोई बात कानून की लिखने से रह नहीं गई। हर मुमुक्षु समझ सके बात २ पर वकील मुख्तारों की सुशामद और रुपये ठगाने से बची जरा सो गलती से मुकद्दमा खराब न होतके। मुकद्दमे की समस्त कार्यवाही स्वयं ही कर सको मू० १।। खर्च 1)

पता—बाद गंगाप्रसादगुप्त डी.पी.कम्पनी अलीगढ़ सिटी

लिफ्ट २) में सरकार का बनाया हुआ

## घर का वकील

### सरल हिंदी भाषा में ताजीरात हिंद

हिन्दी भाषामें तरमीम किया हुआ और इलाहाबाद, नम्वई कल-  
कत्ता, मद्रास, आदि हाईकोर्ट की नजरों व टीना, टिप्पणी तथा  
उदाहरण सहित जिसे थोड़ा पढ़ा भी समझले कुछ न पूछना पड़े  
इस पुस्तक का पढ़ना हर मनुष्य को जरूरी है क्योंकि चाहे कोई  
रजगार करो कानून से काम अवश्य पढ़ेगा परन्तु कानून के न  
ब्यानने का उज़र किसी अदालतमें नहीं सुना जाता इस लिये प्रत्येक  
को महाशय हिन्दी भाषा से अनुराग रखते हों वरद्वारे इस  
“कानून ताजीरात हिन्द” को अवश्य मगावें मूल्य २)

### कार्रवाई दीवानी

इस पुस्तक में अदालत दीवानी संबंधी जरूरी समस्त बातें-  
जैसे नालिशदायर करना व स्थानमियाद समागत कोर्टकोस खसून-  
कानूनी, महस्ताना, नालिश खर्चा, अरजीदावा, ब्यान तहरीरी, नफल  
लेना, हुक्म इस्तनाई नालिश का मुतकिय होना, सम्मन तामील  
गैरहाज़िरी करीबेन, एन्द सपाल दरतावेजों की देखी, जदती, तथा  
बापसी, इज़राय डिग्री अफ्तारी कमीसन, नावालिग, नालिश, मुफ-  
लिसी, पंचायत, अपील नज़रसानी, अदालत खुकीफा, हुनकरफात  
आदि दीवानी के मुतलक सब ही जरूरी बातें ऐसी सरल भाषा में  
लिखी हैं जिनको पढ़कर आसानी के साथ काम खर्च से बिना मश-  
वरे के अपनी कुछ अदालती कार्यवाही कर सके हो। मूल्य १)

### कार्रवाई फौजदारी

इस पुस्तक में मजिस्ट्रेटी सब मजिस्ट्रेटी शिक्षण, पुलिस फौजदारी  
संबंधी समस्त अदालतों में मुकद्दमा लड़ाने की पेरोकारी करने का  
हर मनुष्य के सुभीते के लिये खुलासा वर्णन किया गया है जिससे  
द्वारा अपने मुकद्दमों की पेरोकारी आसानी के साथ बिना वकील  
की सहायता के प्रति एक मनुष्य कर सका है। मूल्य १।)

पता—बाबू गंगाप्रसाद गुप्त, डी, पी, कम्पनी अलीगढ़ मिट्टी

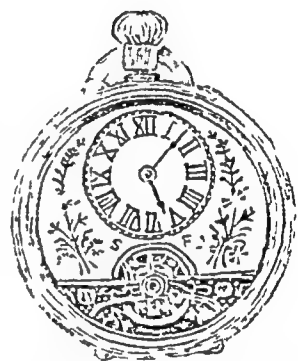
# अभी विलायत से नये चालान की आई हुई फैन्सी और मजबूत घड़ियां

हमारे कारखाने से प्रति एक घड़ी (परीक्षा) देखभाल कर के छोड़े ही कामों में मजबूत और खूबसूरत घड़ियां ग्राहकों को भेजी जाती है वही कारण है कि ग्राहक महाशय हमारे ही कारखाने से घड़ी मंगा कर प्रसन्न रहते हैं।

## चाँदी की सप्ताहिक वाच

गारन्टी १० वर्ष

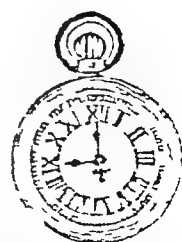
यह घड़ी सब घड़ियों से अधिक खूबसूरत और मजबूत पनी हुई है इसमें कुल घड़ियों से एक अच्छी बात यह है कि एक दफा चापी लगाने से ७ दिन बराबर चलती रहती है रोजाना चायी देने की जरूरत नहीं तामने डाइल पर सेटिन्ड की सुई स्थानमें एक पर्यंश चलता हुआ कैसा भला गालूप होता है कि दिन भर इसकी देखा ही करे रहोत ही मजबूत जोइल दार जिसमें हीरे जड़े हुए नं० १०५ मूल्य १०) अस्तली चाँदी की नम्बर १०६ मूल्य १६) यजाय और घड़ियों के इस घड़ी की मांग सब से ज्यादा आती है आप भी इसको मंगा कर परीक्षा करें अगर पसन्द न आवे तो वापस कर दें



## वेस्ट पैटन्ट वाच

गारन्टी २ वर्ष

रासकोप मशीन निकल दोस चलने में बहुत ही जल्दा और मजबूत खूबसूरत फैन्सी कैस जिस पर नकली काम किया हुआ कम खर्च वाला नशीन नम्बर १२० मूल्य ५॥)



पता—बाहू गंगाप्रसादगुप्त डी.पी.कम्पनी अलीगढ़ सिटी

फलाई पर बांधने की असली डैवडोमस मारके की

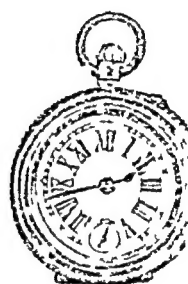
## सप्ताहिक रिस्ट वाच

यह घड़ी कलाई पर बांधने वाली असली डैवडोमस कारखाने की बनी हुई है जो एक दफा चाबी देने से ७ दिन बग़ावर चलती रहती है इसमें लीवर और जोड़ल भी लगे हुए हैं घोंड़े आदि की सवारी तथा कूद फाँड़ में भी बन्द नहीं होती यद्यो न ही खूबसूरत चलने में निहायत मजबूत सच्चा वक्त देने वाली मध्यरे में भी बिजली की तरह चमकने वाली चांदी के केस की मूल्य २०)

## खूबसूरत लेडी वाच

गारन्टी ३ वर्ष

यह घड़ी बहुत ही खूबसूरत और मजबूत है वक्त सच्चा और ठीक बतलाती है इस कारखाने की इस घड़ी को पब्लिक ने बहुत पसन्द किया है कम खर्च बालानशीन छोटा साइज सेकिंड की सुई वाली मूल्य ६) कलाई पर बांधने की तस्मे सहित ७)



## रेलवे रेगुलटर वाच

गारन्टी ३ वर्ष

यह घड़ी प्रसिद्ध और पुराने कारखाने की बनी हुई है इसके डाइल पर अन्जन की तस्वीर बनी हुई बहुत मजबूत और सच्चा वक्त देने वाली खूबसूरत और दर्शनीय है इसी से तो रेलवे मुलाजिम इसको अधिक खरीदते हैं नम्बर १०१ का मूल्य ६)



मिलने का पता—

बाबू गंगाप्रसाद गुप्त डी, पी, कम्पनी

अलीगढ़, उत्तरा





